R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 22 । अंक : 15
01 से 15 मई 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

नीलेश कुम्भानी, सूरत

मीरा यादव, खजुराहो

राजकुमार पटेल

भाजपा ने मारा दम गिर गया बम...!

पहले खजुराहो, फिर सूरत और इंदौर में इंडिया ब्लॉक के साथ हुआ खेला

15 साल पहले कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल भी दे चुके हैं पार्टी को दगा

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

इस अंक में

लालफीताशाही

9 | बिल्डरों की आस, सरकार की फांस

अगर यह कहा जाए कि मप्र में जमीन की कीमत सोने के भाव से भी अधिक तेजी से बढ़ रही है तो इसमें अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस कारण जमीन के धंधे में सफेदपोश, राजनेता और अधिकारी भी लगे हुए हैं। ऐसे ही लोगों...

राजपथ

10-11 | कम मतदान ने बढ़ाई चिंता

मप्र में मिशन 29 के घमासान के तहत पहले और दूसरे चरण की 12 सीटों पर पिछली बार की अपेक्षा कम पड़े मतदान ने भाजपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों को हलाकान कर दिया है। दरअसल, इस चुनाव में मुद्दे पूरी तरह...

इंदौर

14 | निगम का ड्रेनेज...

इंदौर नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक निगम प्रशासन दावा करता आ रहा था कि घोटाले में 28 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हो गया है कि आरोपी पांचों फर्म 20 करोड़...

मेट्रो

18 | सफेद हाथी बना मेट्रो रेल...

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट सरकार के लिए सफेद हाथी बन चुका है। भोपाल के लोग मेट्रो की सवारी कब से कर सकेंगे यह अभी तय नहीं हो पाया है। उधर स्थिति यह है कि प्रोजेक्ट का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि मेट्रो के लिए यात्री कहां से मिलेंगे इसका अता-पता किसी...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

18वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा मिशन 400 पार पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए भाजपा एक सीट निर्विरोध जीत चुकी है, दो पर जीत पहले से तय मानी जा रही है। क्योंकि मप्र की खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन दस्तखत ना होने से खारिज हो गया। फिर गुजरात के सूरत में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी निलेश कुम्भानी और डमी, दोनों प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया था।

राजनीति

30-31 | गरीबी हटाओ बनाम...

लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दावों और वादों का पिटारा खुल गया है। जितने उम्मीदवार, उतने वादे। जितने दल, उतने दावे। इन वादों और दावों की अंधी गलियों में आम आदमी खो सा गया है। आम आदमी से जुड़े रोटी, कपड़ा, रोजगार, मकान, पढ़ाई और दवाई के मुद्दे...

महाराष्ट्र

35 | मराठी अस्मिता की लड़ाई

महाराष्ट्र में शिवसेना और राकांपा में बड़ी टूट से लोकसभा चुनावों में लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इसे मराठी अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मराठी अस्मिता पर चोट भाजपा खेमे को भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र इस मायने में क्लासिक केस है कि कैसे केंद्र में...

बिहार

38 | जाति की जमावट

क्या बिहार में इस बार राजनीतिक दल लोकसभा का चुनाव कुछ अलग तरीके से लड़ रहे हैं। आखिर क्यों पुराने समीकरण इस बार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा पहले के चुनावों में दिखता था। भाजपा की ओर से इस बार बिहार में ऐसा क्या किया गया है...

6-7 अंदर की बात
39 प.बंगाल
40 पड़ोस
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

ये राजधानी है या बूचड़खाना...

किसी कवि ने क्या खूब कहा है...

गगन से आगे कदम आज जो बढ़ाने चला है।
तेरा विकास, ऐ मानव तुझे मिटाने चला है।।

इन पंक्तियों को देश के हृदय प्रदेश की राजधानी भोपाल चरितार्थ करती है। यहां पिछले दो दशक से विकास के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। विकास के लिए स्मार्ट सिटी, बीआरटीएस कॉरिडोर, सड़क निर्माण और चौड़ीकरण, ओवरब्रिज, मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट, कोलार सिक्सलेन सहित कई योजनाएं चल रही हैं। ये योजनाएं भोपाल को पेरिस बनाने के दावे के साथ चल रही हैं, लेकिन वर्तमान में अनियंत्रित विकास और अस्त-व्यस्त परियोजनाओं के कारण राजधानी किसी बूचड़खाने से कम नजर नहीं आ रही है। दरअसल, सरकार ने योजनाएं तो क्रियान्वित कर दीं, लेकिन लगभग सारी योजनाएं समयसीमा पार कर गई हैं। इस कारण अधूरे ब्रिज, अधूरी सड़कें, खुदी सड़कें, जहां-तहां पड़ा मलबा, आधे-अधूरे पिलर, स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर के सबसे हरे-भरे क्षेत्र को तहस-नहस किए जाने के कारण शहर मलबे का ढेर नजर आ रहा है। बीते दस सालों में निर्माण कार्यों को लेकर जिस प्रकार से पेड़ काटे गए हैं, उससे भोपाल की हरियाली में 30 फीसदी की कमी आई है। उससे भी चौंकाने वाली बात है कि बीते पांच वर्षों में इसमें 20 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। व्यापक स्तर पर पेड़ों की कटाई वाले नौ स्थानों पर 225 एकड़ हरित क्षेत्र के सफाए के बाद वहां कांक्रीट के जंगल बना दिए गए। शहर में ग्रीन कवर कम होने के साथ वायु प्रदूषण का बड़ा कारण हवा में उड़ती धूल और तेजी से हो रहे निर्माण कार्य हैं। 67 प्रतिशत प्रदूषण धूल के कारण हैं। जबकि, धुआं छोड़ती गाड़ियों के कारण 12 प्रतिशत प्रदूषण हो रहा है। मेट्रो और फ्लाईओवर के निर्माण से भी 11 प्रतिशत प्रदूषण हो रहा है। जबकि कचरा जलाने से भी शहर में पांच प्रतिशत प्रदूषण फैल रहा है। बड़े और छोटे तालाब को रामसर साइट और भोज वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। इसके बावजूद इसका संरक्षण करने में अधिकारी नाकाम साबित हो रहे हैं। जबकि रसूखदारों में बड़े तालाब के किनारे और कैचमेंट क्षेत्र के अंदर तक 50 से ज्यादा मैरिज गार्डन समेत अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को निर्माण किया गया है। एफटीएल सीमा के अंदर सैर सपाटा भी है। इधर तालाब के आसपास कॉलोनियों का सीवेज ट्रीटमेंट और अस्पताल, नर्सिंग होम, सर्विस स्टेशन का गंदा पानी इसे दूषित बना रहा है। इसी तालाब में खेतों से रासायनिक पदार्थों से दूषित वर्षा का पानी भी तालाब में आकर मिल जाता है। इस तालाब के पानी को बी ग्रेड का माना जाता है, लेकिन बाहर से आने वाले दूषित पानी के तालाब में मिल जाने से यह घटकर सी और डी ग्रेड का हो गया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम स्वयं इस पर विचार करें तो हमारे बचपन के बाद युवावस्था फिर प्रौढ़ावस्था और अंत में वृद्धावस्था आती है, यानी जीवन में धीरे-धीरे परिवर्तन आता है। आज हम जिस रूप में हैं, तीस दशक पूर्व हम वैसे नहीं थे। इसी क्रम में हम भोपाल शहर का आंकलन करें तो इस अंतराल में बहुत-सी चीजें लुप्त हो गई हैं। कभी अपनी हरियाली और सौंदर्यता के कारण देशभर में ख्यात भोपाल आज कांक्रीट के जंगल, अनियंत्रित विकास, खराब सड़कें, ट्रैफिक जाम वाला शहर बन गया है। विकास के नाम पर शहर को विनाश की ओर लेकर जाया जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बिना मास्टरप्लान के शहर को बर्बाद करने में सफेदपोश, नेता और अफसरों का सबसे बड़ा हाथ है।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 22, अंक 15, पृष्ठ-48, 1 से 15 मई, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी,
जयपुर:- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी
फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर,
फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर,
भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर,
मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास
मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

कड़ी कार्यवाही हो

प्रदेश सहित देशभर में बोरवेल में बच्चों के गिरने की खबरें आम हो गई हैं। शासन-प्रशासन को इसके लिए सख्ती से कार्यवाही करनी चाहिए। जिन-जिन लोगों के बोरवेल खुले हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से बोर को भरवाना चाहिए। अगर वे सक्षम नहीं हैं तो प्रशासन से मदद लेनी चाहिए।

● **दिलीप सिंह,** राजगढ़ (म.प्र.)

चुनावी रण दिलचस्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अबकी बार 400 पार के नारे को साकार करने के लिए मप्र में भाजपा चुनाव में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस भी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मप्र की सभी 29 सीटों पर भाजपा जीत का परचम लहराती है या कांग्रेस इसमें सेंध लगाती है।

● **अनीता परिहार,** इंदौर (म.प्र.)

नक्सलियों पर नकेल कब?

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आए दिन फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस एफओबी स्थापित किए जा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि नक्सली अपने पुराने ठिकाने छोड़कर घने जंगल की तरफ भागने लगे हैं। इससे आमजन को परेशानी का खतरा बढ़ गया है। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

● **विजय वर्मा,** सीहोर (म.प्र.)

जलसंकट से कब मिलेगी निजात?

जलसंकट आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बन गया है। मप्र में कुल मिलाकर 82 हजार 643 वॉटर बॉडीज मौजूद हैं। इसमें से शहरों में 1520 तालाब, 1 वॉटर कंजर्वेशन स्कीम और 110 दूसरे जल स्रोत हैं, इस तरह कुल 1631 वॉटर बॉडीज हैं। प्रदेश के गांवों में 78298 तालाब हैं। इसके अलावा 71 टैंक, 30 झील, 75 तालाब और 337 जल संरक्षण स्कीम और डेम, इसके अलावा 2201 दूसरे तरह के जलस्रोत मौजूद हैं। प्रदेश में 1366 वॉटर बॉडीज ऐसी हैं, जिस पर न सिर्फ अतिक्रमण हो चुका है, बल्कि उन पर निर्माण भी किया जा चुका है। 917 जल स्रोतों की हालत तो यह है कि इसमें अब सुधार कर पाना भी संभव नहीं है। सरकार को इस संकट से निपटान का हल खोजना ही होगा।

● **पुरुषोत्तम दांगी,** खंडवा (म.प्र.)

पर्यावरणीय मुद्दा जंगल की आग

जंगल की आग बार-बार होने वाला पर्यावरणीय मुद्दा बन गई है, जिसके दुनिया भर के पर्यावरण और मानव समुदायों पर विनाशकारी परिणाम हो रहे हैं। मप्र के वन क्षेत्रों में विविध आदिवासी समुदाय रहते हैं जो सदियों से प्रकृति के साथ सह-अस्तित्व में हैं। राज्य के प्रमुख आदिवासी समुदाय, जिनमें गोंड, बैगा और कोरकू शामिल हैं, जंगल के करीब रह रहे हैं और अपने निर्वाह के लिए वन पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक निर्भर हैं। जंगल की आग के कारण इनके जीवनयापन में समस्या आन खड़ी होती है।

● **अंजुम कुरैशी,** विदिशा (म.प्र.)

जागरूकता जरूरी

जलवायु परिवर्तन का खतरा झेलने वाले जिलों में ही कुष्ठ रोग व अन्य उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (एनटीडीएस) जैसे हाथी पांव रोग (फाइलेरिया) का अधिक फैलाव होता है। हाथी पांव एक विषाणु-जनित संक्रमण है, जिससे पैर, बांह और जननांगों में सूजन हो जाता है। प्रदेश सरकार सहित अन्य राज्यों की सरकारों को इसके लिए जागरूकता फैलानी चाहिए। जिससे आने वाले समय में कुष्ठरोग पर जीत पाई जा सके।

● **निमेश सिंह,** रतलाम (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

राजद छोड़ सकते हैं देवेंद्र प्रसाद

आम चुनाव के मतदान से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। एक ओर जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता वृषिण पटेल और अशफाक करीम ने राजद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद ने बीते दिनों अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए। जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि वह राजद छोड़ सकते हैं। देवेंद्र प्रसाद ने आरोप लगाए कि राजद में अब लोकतंत्र की कमी हो गई है। आज लालू यादव पार्टी के सिद्धांतों से समझौता कर रहे हैं। चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं की जगह बाहरी लोगों को टिकट दिया जा रहा है। पहले राजद में यूज एंड ग्रो होता था, लेकिन अब यहां यूज एंड थ्रो का रवैया अपनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि राजद 2024 के लोकसभा चुनाव में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन अगर पार्टी 2024 में ही चुनाव नहीं जीतेगी तो 2025 में कैसे जीतेगी। हम सच बोलने से कभी पीछे नहीं हटे और अगर सच बोलना बगावत है तो हम बागी हैं। यही नहीं पूर्णिया सीट से पप्पू यादव को टिकट नहीं दिए जाने पर भी देवेंद्र ने नाराजगी जताई है।

क्या राज ठाकरे ने कर दी गलती ?

मनसे प्रमुख राज ठाकरे का भाजपा को बिना शर्त समर्थन के फैसले के बाद उनकी पार्टी में भगदड़ शुरू हो गई है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राज ठाकरे ने भाजपा को समर्थन देकर गलती कर दी है। पार्टी के महासचिव कीर्ति कुमार शिंदे ने मनसे छोड़ने का ऐलान कर दिया है, उन्होंने महासचिव पद व पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पार्टी के कई अन्य पदाधिकारियों ने भी इस्तीफे का ऐलान किया है। मनसे छोड़ने वालों में शामिल पार्टी महासचिव कीर्ति कुमार शिंदे ने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि मनसे प्रमुख ठाकरे ने 2019 में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ रुख अपनाया था। अब पांच साल बाद राज साहेब ने देश के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में अपनी राजनीतिक भूमिका बदल ली है। राजनीतिक विश्लेषक बताएंगे कि वह कितने गलत हैं और कितने सही। गौरतलब है कि बीते दिनों राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की वार्षिक रैली में प्रधानमंत्री मोदी और महायुति गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की थी। जिसके बाद कीर्ति कुमार शिंदे के अलावा मिहिर दावते और मुंबई के बाहरी इलाके डोंबिवली में मनसे की छात्र शाखा के पदाधिकारियों ने भी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कहा- हमने देखा कि राज साहेब के बदलते रुख का सामना करना मुश्किल है और इसलिए अलग होना ही बेहतर है। कार्यकर्ताओं का एक वर्ग चुप है लेकिन वे इस फैसले से खुश नहीं है।

कांग्रेस के मुद्दों पर लड़ रही भाजपा!

दो चरण के मतदान के बाद चुनाव को देखने और समझने का नजरिया बदल गया है। कम मतदान की अपने-अपने अंदाज में व्याख्या हो रही है। विपक्षी पार्टियां इसे सरकार के प्रति मोहभंग मान रही हैं तो भाजपा का कहना है कि विपक्ष से लोगों को कोई उम्मीद नहीं है इसलिए सिर्फ सरकार का समर्थन करने वाले ही बूथ पर जा रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि दोनों धारणाएं अतिवादी हैं। सच्चाई दोनों के बीच कहीं है। लेकिन उससे भी दिलचस्प बात यह है कि भाजपा का पूरा चुनाव प्रचार ही बदल गया है। भाजपा अब तक जिन मुद्दों पर प्रचार कर रही थी वो सारे मुद्दे हाशिए में चले गए हैं। उनकी जगह नए मुद्दे आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये नए मुद्दे आसमान से टपके हैं। ऐसा भी नहीं है कि अचानक कोई बड़ा घटनाक्रम हो गया और समूचा नैरेटिव बदल गया। ये नए मुद्दे आए हैं कांग्रेस के घोषणापत्र से या कांग्रेस नेताओं के बयानों से। सो, कह सकते हैं कि अब चुनाव कांग्रेस के घोषणापत्र पर या कांग्रेस के तय किए गए एजेंडे पर लड़ा जा रहा है। यह कई मायने में कांग्रेस की बड़ी उपलब्धि है कि उसके चुने गए मुद्दे पर चुनावी नैरेटिव सेट हो रहा है। ध्यान रहे पिछले 10 साल से राजनीति का समूचा विमर्श भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय कर रहे थे।

भाजपा फंसी!

भाजपा फंस गई है। तय मानें 400 पार की सुनामी तो दूर भाजपा की आंधी और हवा भी नहीं है। यदि अब तक हुए मतदान के प्रतिशत व भाजपा के अभेद प्रदेशों में हुई वोटिंग तथा जातीय समीकरणों की फीडबैक को पूरे चुनाव का सैंपल आधार मानें तो लोगों में भाजपा को जिताने का वह जोश कतई नहीं है, जिससे बड़ी जीत की हवा समझ आए। उलटे उन सीटों पर भाजपा को हराने की मौन हलचल है, जहां बड़ी संख्या में भाजपा विरोधी परंपरागत वोट हैं। इसलिए 400 पार की सुनामी तो दूर सामान्य बहुमत के लिए भी अगले छह चरणों में भाजपा को बहुत पसीना बहाना होगा। मतलब 2014 और 2019 में मतदान की बढ़ती संख्या के साथ नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ उछलता था, वह ट्रेंड इस चुनाव में गिरता हुआ है। अब माहौल फीका है। मौन और ठंडा चुनाव है। तभी पिछले दो चुनावों में मतदान के बढ़ते ट्रेंड और उसी अनुपात में चढ़ते मोदी ग्राफ को पहले चरण में झटका है। जबकि भाजपा के इन इलाकों में 2014 और 2019 में वोटिंग का प्रतिशत और भाजपा का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा था।

कांग्रेस में अंदरूनी बवाल

बिहार में कांग्रेस के 9 उम्मीदवारों की सूची में भी नेता पुत्रों को तवज्जो दिए जाने को लेकर सूबे के पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त नाराजगी और बेचैनी है। सूबे के नेताओं का साफ कहना है कि नेताओं के सगे-संबंधियों के राजनीतिक करियर की शुरूआत और बाहर से आए प्रवासी सियासी पक्षियों के लिए कांग्रेस की चुनावी जीत के फॉर्मूले की कुर्बानी दी गई है। प्रदेश के कुछ नेताओं ने तो कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर पार्टी नेतृत्व तक अपनी नाराजगी और शिकायत पहुंचा दी है। कांग्रेस ने बिहार के पांच उम्मीदवारों की गत दिनों सूची जारी करने के बाद पटना साहिब की एक बची सीट पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे अंशुल अविजित को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। अंशुल अकेले नेता संतान नहीं हैं जो कांग्रेस की 9 उम्मीदवारों की सूची में हैं। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह को महाराजगंज से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है।

सरदार बड़ा असरदार

प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में एक सरदारजी चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल, ये सालों से भोपाल में काम कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इनका मुख्य काम अफसरों की काली कमाई को मैनेज करना है। वैसे तो वे हर तरह का काम कर लेते हैं। आम लोग सरदारजी को एक व्यवसायी के तौर पर जानते हैं, लेकिन वे रसूखदारों के लिए बड़े धंधेबाज का काम करते हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि जो भी नया काम आता है, उसमें ये रूचि दिखाना शुरू कर देते हैं। अफसर भी उनकी रूचि का पूरा ध्यान रखते हैं। सूत्र बताते हैं कि कभी सेंट सुंघाकर अफसरों को साधकर काम करने वाले सरदारजी कहां से कहां पहुंच गए हैं। आलम यह है कि इनके पास कामों की कमी नहीं है। सारे काम-धंधों के बीच इन दिनों ये धारा-16 की छूट का भी काम देख रहे हैं। अफसरों से अपने अच्छे संबंध का फायदा उठाकर लोगों को धारा-16 की छूट का फायदा दिलवाकर सरदारजी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। उनको जानने वाले बताते हैं कि सरदारजी कामधंधा कोई भी करे, लेकिन वे ईमानदारी से सबको उनके हिस्से की प्रसाद पहुंचा देते हैं। इनकी पहुंच और इनके रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इनकी पहुंच प्रदेश की सबसे ऊंची वाली प्रशासनिक कुर्सी तक भी है। सूत्र बताते हैं कि यह महाशय इन दिनों उक्त बड़े आईएएस अधिकारी के लिए भी काम कर रहे हैं।

बदलेगा शिवराज का एक और निर्णय

जिस सीपीए (राजधानी परियोजना प्रशासन) को पूर्व मुख्यमंत्री ने नाकाबिल मानते हुए बंद कर दिया था, उसे वर्तमान सरकार फिर से शुरू करने जा रही है। करीब दो साल बाद सीपीए को शुरू करने की कवायद एक राज्य मंत्री के प्रयास से शुरू की जा रही है। गौरतलब है कि इसी साल मार्च माह में सीपीए को चालू करने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया था। इसमें कहा गया था कि एक अधिकारी की जिद के कारण कतिपय कारणों से सीपीए बंद कर दिया गया था। इसको लेकर न तो जनप्रतिनिधियों से चर्चा की गई और न ही उन्हें विश्वास में लिया गया। बताया जा रहा है कि वर्तमान मुख्यमंत्री ने सीपीए को बंद करने के मामले को गंभीरता से लिया है। यानी पूर्व मुख्यमंत्री के एक और फैसले को वर्तमान सरकार बदलने जा रही है। इस संबंध में राज्य शासन स्तर पर विधिवत निर्णय ले लिया गया है और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसका पूरा प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। सीपीए बंद करने के पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रमुख प्रशासनिक पद पर बैठे अफसर की नाराजगी अहम वजह बताई गई थी। यहां तक कहा गया था कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से ऐसा कराया।

कौन बचा रहा मगरमच्छों को ?

करीब 7 साल पहले प्रदेश की व्यवसायिक राजधानी में शराब ठेकों में 42 करोड़ रुपए के फर्जी बैंक गारंटी लगाने की मामले में दोषी पाए गए आबकारी विभाग के दो अफसरों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि आखिरकार भ्रष्टाचार के इन मगरमच्छों को कौन बचा रहा है। गौरतलब है कि जब यह मामला हुआ था, उस समय तत्कालीन विभागीय आयुक्त को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने जांच शुरू ही की थी कि अपने निजी कारणों के कारण वे बीच में ही चली गईं। सूत्रों का कहना है कि अगर वे रहतीं तो दोनों दोषी अफसर बच नहीं पाते। उनके जाने के बाद से जांच अधर में लटक गई है। अभी तक दोषियों से पैसे भी नहीं वसूले गए हैं। उधर, सूत्रों का कहना है कि नए जांच आयुक्त की खोज भी चल रही है। इस बड़े फर्जीवाड़े में दोषी पाए गए दोनों अफसरों के रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अभी तक दोनों की जांच के लिए अभियोजन स्वीकृत नहीं हुए हैं। और तो और इस मामले में एक पूर्व कमिश्नर तो एक आरोपी जिनके यहां लोकायुक्त के छापे पड़े थे, उनके संदर्भ में यहां तक लिखकर चले गए कि इन पर कोई मामला नहीं बनता है। दरअसल, साहब उनके स्वजातीय थे। इसलिए कहा जा रहा है कि उसको बचाने के लिए साहब ने ऐसा लिख दिया होगा। हम आपको यहां यह भी बता दें कि अपने स्वजातीय आरोपी को बचाने वाले साहब खुद एक जमीन घोटाले में फंस गए हैं।

अब सख्ती से बेदखली

प्रदेश में नई सरकार के गठन के 4 माह से अधिक का समय गुजर गया है, लेकिन बार-बार की चेतावनी के बाद भी पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और कई अधिकारियों ने सरकारी मकान को खाली नहीं किया है। गुहार, मनुहार कर-करके सरकार थक गई है। लेकिन सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाकर बैठे लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी की है। पूर्व मंत्रियों, पूर्व विधायकों और कई अधिकारियों से सरकारी बंगलों को खाली करवाने के लिए अफसरों की एक कमेटी भी बना दी गई है। यह कमेटी सरकारी बंगलों पर कब्जा जमाकर बैठे लोगों से मुलाकात करेगी और उनसे बंगलों को खाली करने के लिए कहेगी। अगर उसके बाद भी बंगले खाली नहीं किए गए तो उन्हें नोटिस दिया जाएगा। नोटिस भी ऐसा-वैसा नहीं, बल्कि आदेशात्मक रहेगा। यानी अगर नोटिस के बाद भी किसी ने बंगला खाली नहीं किया तो शासकीय अमले द्वारा उक्त बंगले के जोर-जबरदस्ती के साथ खाली कराया जाएगा। अब देखना यह है कि माननीयों के बंगले का मोह छूटता है या नहीं।

दो और सीपी की तलाश

राजधानी भोपाल और व्यवसायिक राजधानी इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम की सफलता से सरकार उत्साहित है। ऐसे में सरकार अब दो अन्य बड़े शहरों जबलपुर और ग्वालियर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की कवायद में जुटी हुई है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद सरकार इस दिशा में तेजी से काम करेगी। इसलिए दोनों शहरों में पुलिस कमिश्नर (सीपी) तैनात करने के लिए योग्य आईपीएस अधिकारियों की खोज शुरू हो गई है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि दोनों शहरों की कमान वर्तमान समय में प्रमोटी आईपीएस अधिकारियों के हाथ में हैं। सूत्रों का कहना है कि जैसे ही यह खबर आईपीएस अधिकारियों के कानों तक पहुंची है, उन्होंने पुलिस कमिश्नर बनने के लिए लॉबिंग शुरू कर दी है। किसी ने अभी से दिल्ली में अपने संपर्क सूत्रों को सक्रिय कर दिया है, तो कोई प्रदेश में ही संघ, संगठन और सरकार में जुगाड़ बैठा रहा है। गौरतलब है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में जबलपुर और ग्वालियर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणाएं की थीं।

अंग्रेजों ने हम पर राज किया, उन्होंने हमें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राजा भी झुक गए। राजाओं ने अंग्रेजों के साथ रोटियां तोड़ीं और अपनी बेटियों की शादी उनसे की। लेकिन हमारे रूखी समुदाय ने न तो अपना धर्म बदला और न ही अंग्रेजों के साथ दोस्ताना संबंध स्थापित किए।

● **पुरुषोत्तम रुपाला**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कपड़े तो संतों के पहनते हैं, लेकिन उन्हें संतों जैसा ज्ञान नहीं है। एक योगी की भाषा गलत नहीं होनी चाहिए। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि सत्यनारायण भगवान की कथा में चूरन नहीं प्रसाद वितरित होता है। इस चूरन खाने वाले ने कई लोगों का हाजमा दुरुस्त किया है। सीएम योगी अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं।

● **शिवपाल यादव**

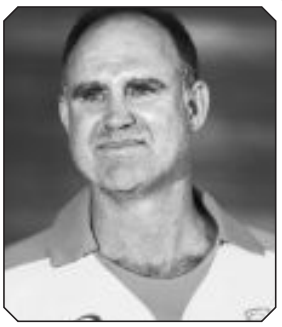

इस समय भारतीय क्रिकेट टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनकी बराबरी के विश्व की अन्य टीमों में कोई नहीं है। इन्हीं में से एक हैं विराट कोहली। टी-20 वर्ल्डकप में विराट कोहली से ओपनिंग करानी चाहिए। पावर प्ले में विराट को खेलना चाहिए। उन्हें उन 6 ओवरों में ज्यादातर समय ओपनिंग बैटर के रूप में खेलने से भारत मजबूत होगा।

● **मेथ्यू हेडन**

अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव में चीन का दखल बढ़ रहा है। हमें चीन के हस्तक्षेप के कई सबूत मिले हैं। जो हमें बिलकुल भी स्वीकार नहीं हैं। चीन और कुछ देश अलग-अलग कैंपेन चलाकर अमेरिका को बांटने की कोशिश कर रहे हैं।

● **एंटनी ब्लिंकन**

जीवन में मेरे जितना संघर्ष और उतार-चढ़ाव शायद ही किसी ने देखा होगा। दूसरों के खेतों में काम करके मैंने घर चलाया और स्कूल की फीस भी भरी। फिर जब कॉलेज में गई तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम किया। इससे कॉलेज की फीस भी निकल जाती और घर खर्च भी चल जाता। मैंने कुछ दिनों तक बतौर रिसेप्शनिस्ट भी काम किया है। एक दोस्त के कहने पर मैंने मॉडलिंग शुरू की। फिर मुंबई का रुख किया और वहां काफी संघर्ष के बाद टीवी शो में काम भी मिले, लेकिन फिर मैंने शादी कर ली। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। अब मैं तलाक केस लड़ रही हूं और आगे की जिंदगी बेहतर करने के लिए संघर्ष कर रही हूं।

● **कंगना शर्मा**

वाक्युद्ध

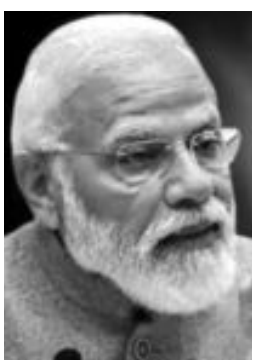

कांग्रेस ने 70 साल तक देश में राज किया, लेकिन अब भी वह देशवासियों का शोषण करने की कोशिश में लगी हुई है। कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वे आपकी संपत्तियों का सर्वे कराएंगे और उन्हें अधिक बच्चे पैदा करने वालों में बांट देंगे। इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिए।

● **नरेंद्र मोदी**

प्रधानमंत्री जैसा कह रहे हैं, वैसा कुछ भी नहीं है। 10 सालों में जनता को भ्रम में रखने वाले मोदीजी अब एक बार फिर भ्रम फैलाकर लोगों की सहानुभूति लेना चाह रहे हैं। लेकिन अब लोगों को यह बात पूरी तरह से पता चल गई है कि पीएम और उनकी सरकार केवल घोषणाएं और वादे कर रहे हैं, काम तो बिलकुल ही नहीं।

● **राहुल गांधी**

बिल्डरों की आस, सरकार की फांस

इंदौर-भोपाल में धारा-16 के प्रावधान यथावत

आगामी मास्टर प्लान के लागू ना होने तक शासन ने वृद्धि निवेश क्षेत्र के लिए धारा-16 के प्रावधान इंदौर-भोपाल सहित अन्य शहरों के लिए पहले लागू कर दिए थे। चूंकि बड़े शहरों की तुलना में छोटे शहरों में इन प्रावधानों को लागू करने में व्यवहारिक कठिनाई आ रही थी, जिसके चलते संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश ने एक संशोधित आदेश जारी किया है। इसमें इंदौर-भोपाल में तो धारा-16 के तहत पूर्व में जो प्रावधान लागू किए थे वे यथावत रहेंगे, जिसमें न्यूनतम 10 एकड़ जमीन, सड़कों की चौड़ाई 12 मीटर से लेकर अन्य अनिवार्यताएं लागू की गई हैं। वहीं देवास, पीथमपुर, जबलपुर सहित अन्य क्षेत्रों के लिए विकास अनुज्ञा के लिए संशोधन किए गए। यहां तक कि इन शहरों में जो वृद्धि निवेश क्षेत्र है वहां पर कृषि उपयोग में स्वीकार गतिविधियों को ही अनुमति दी जाएगी। इंदौर का आगामी मास्टर प्लान अधर में है। पहले तो 2035 तक के लिए प्लान की तैयारी की गई और पिछले दिनों भोपाल में हुई मीटिंग में लगभग इस बात पर सहमति बन गई कि अब 2041 के मास्टर प्लान को लागू किया जाएगा। वैसे भी अभी 2025 तक प्लान का अमल में आना संभव ही नहीं है। चूंकि इंदौर के नए प्रस्तावित मास्टर प्लान में 79 गांवों को शामिल किया गया है, जो वृद्धित निवेश क्षेत्र कहलाते हैं और इनमें अनुमतियां नगर तथा ग्राम निवेश की धारा-16 के तहत दी जा रही हैं।

अगर यह कहा जाए कि मप्र में जमीन की कीमत सोने के भाव से भी अधिक तेजी से बढ़ रही है तो इसमें अतिश्योक्ति नहीं होगी। इस कारण जमीन के धंधे में सफेदपोश, राजनेता और अधिकारी भी लगे हुए हैं। ऐसे ही लोगों के लिए नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा-16 ऐसा हथियार बन गई है, जिसका वे अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करते हैं। पूर्व में धारा-16 को प्रतिबंधित कर दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने जमीनों के धंधों पर नकेल कसने के लिए धारा-16 पर प्रतिबंध लगाया था। उनका मानना था कि इससे विकास अवरूद्ध नहीं होगा। साथ ही नई कॉलोनियों का मकड़जाल नहीं बुनेगा। लेकिन वर्तमान में धारा-16 की छूट दे दी गई है। इससे बिल्डरों में आशा की किरण जग गई है। लेकिन यह छूट सरकार की फांस बन गई है। आलम यह है कि धारा-16 की छूट मिलते ही जमीनों के सौदागर सक्रिय हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि 8 से 10 लाख रुपए बीघा लेकर धारा-16 से छूट दिलाने का धंधा जोरों पर शुरू हो गया है। इसका आंकलन इसी से लगाया जा सकता है कि एक महीने के अंदर इंदौर में ही दो दर्जन से अधिक मामले ऐसे आ चुके हैं, जिसमें धारा-16 की छूट दे दी गई है। ऐसा ही हाल भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन जैसे शहरों का है।

जानकारों का कहना है कि धारा-16 से छूट दिलाने का धंधा इस कदर चरम पर है कि सरकार की बदनामी होने लगी है। यही नहीं जमीनों के गोरखधंधे की खबर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान में जो स्थिति है, ऐसी ही स्थिति को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्य सचिव ने धारा-16 को प्रतिबंधित कर रखा था। ऐसे में अब जब वर्तमान सरकार ने धारा-16 की छूट का प्रावधान किया है तो उस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। बताया जाता है कि राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण में कई दलाल जमीनों के धंधे में जुट गए हैं। इससे सारी सरकारी व्यवस्था चरमरा गई है। गौरतलब है कि अभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई है, इस कारण भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों के मास्टर प्लान अधर में लटके हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ धारा-16 की अनुमतियां आसान किए जाने का फायदा उठाने के लिए जमीनों का कारोबार तेज हो गया है। जानकारों का कहना है कि धारा-16 का फायदा उठाकर रसूखदार लोग जमीनों के खेल में जुट गए हैं। गौरतलब है कि धारा-16 को पूर्व में प्रतिबंधित किए जाने के कारण अनुमतियां ठप पड़ी थीं। इससे सैकड़ों प्रोजेक्ट लटक गए और चुनिंदा को ही अनुमतियां मिल सकीं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस ने चुन-चुनकर धारा-16 की छूट लोगों को दी। जिससे उस दौर में जमीनों का कारोबार मनमाने ढंग से किया गया। लेकिन अब वर्तमान सरकार इस प्रक्रिया को आसान बनाने में जुटी है।

गौरतलब है कि जो मास्टर प्लान तैयार किया जाना है उसकी प्रक्रिया भी पहले विधानसभा चुनाव और अब लोकसभा के चलते अटकी पड़ी है। लिहाजा मास्टर प्लान का प्रारूप चुनाव संपन्न होने के बाद ही जारी होगा, क्योंकि अभी चुनाव के वक्त प्रारूप प्रकाशन के बाद जमीन मालिकों को फायदा पहुंचाने के आरोप अलग लगेंगे, क्योंकि बढ़ती आबादी और शामिल किए गए निवेश क्षेत्र में कई जमीनों का उपयोग कृषि से आवासीय, वाणिज्यिक व पीएसपी करना पड़ेगा। उनमें अनुमतियां हासिल करना कॉलोनाइजरों-बिल्डरों के लिए मुश्किल भरा हो गया है। इसकी अनुमति धारा-16 में भोपाल से दी जाती है और चुनिंदा प्रोजेक्ट को ही यह अनुमतियां जुगाड़ के जरिए मिल सकीं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सहमति जताई और आश्वस्त किया कि धारा-16 के प्रोजेक्टों में मंजूरी के काम में गति आएगी और प्रक्रिया को भी आसान करेंगे। गौरतलब है कि मास्टर प्लान बन रहा है। लोगों को उम्मीद है कि इस बार हर हालत में मास्टर प्लान लागू हो जाएगा। लेकिन मास्टर प्लान में सबकुछ अच्छा होगा, यह कहा भी नहीं जा सकता। इसकी वजह यह है कि जब भी मास्टर प्लान बनाया जाता है, नेताओं, अफसरों और रसूखदारों की सहूलियतों का ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि पिछले 19 साल से भोपाल का मास्टर प्लान केवल कागजों पर ही भटक रहा है। जब भी मास्टर प्लान तैयार होता है, उस पर आपत्तियां बुलाई जाती हैं, सुनवाई होती है, उसके बाद न तो आपत्तियों पर कोई कार्रवाई होती है, और न ही मास्टर प्लान को अमलीजामा पहनाया जाता है। इस बार भी बन रहे मास्टर प्लान के संदर्भ में लोगों का कहना है कि यह केवल रसूखदारों के हितों पर ही आधारित होगा, इससे आम आदमी का कोई लेना-देना नहीं होगा। उधर, जानकारों का कहना है कि मास्टर प्लान लागू हो या न हो, इससे दलालों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। धारा-16 की छूट उन्हें मनमर्जी करने की पूरी छूट देगी।

● कुमार विनोद

मप्र में मिशन 29 के घमासान के तहत पहले और दूसरे चरण की 12 सीटों पर पिछली बार की अपेक्षा कम पड़े मतदान ने भाजपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों को हलाकान कर दिया है। दरअसल, इस चुनाव में मुद्दे पूरी तरह गुम हैं और मतदाता मौन। ऐसे में पार्टियां आंकलन नहीं कर पा रही हैं कि मतदाताओं का मूड क्या है। हालांकि भाजपा को भरोसा है कि मोदी की गारंटी और मोहन के विकास मॉडल के आधार पर पार्टी प्रदेश की सभी 29 सीटें जीत लेगी। उधर, कांग्रेस भाग्य के सहारे उम्मीद लगाए हुए है।

कम मतदान ने बढ़ाई चिंता

मप्र में चार चरणों में 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। पहले दो चरणों के दौरान 12 सीटों पर हुए मतदान ने नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा पर 67 फीसदी मतदान हुआ है। पिछली बार इन सीटों पर औसत 75 फीसदी वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से करीब 8 फीसदी कम वोटिंग हुई है। वहीं दूसरे चरण में सतना, रीवा, दमोह, टीकमगढ़, खजुराहो, होशंगाबाद में 58.35 प्रतिशत मतदान हुआ। इन सीटों पर पिछली बार 67.77 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस बार भी मतदान कम होने से चुनाव आयोग के साथ ही नेताओं और पार्टियों की चिंता बढ़ गई है।

उधर, लोकसभा चुनाव में वोटिंग घटने पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मप्र के नेताओं को दो टूक शब्दों में कहा है कि जिन मंत्रियों के इलाकों में वोटिंग प्रतिशत कम होगा, उनका मंत्री पद चला जाएगा। बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, जिनके क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। शाह के इस फरमान ने भाजपा विधायकों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल, कम मतदान की वजह गर्मी को दिया जा रहा है। लेकिन पिछली बार भी इसी तरह की गर्मी में चुनाव हुए थे। ऐसे में कम मतदान ने भाजपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों को पसोपेश में डाल दिया है। राजनीतिक दलों और निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी ताकत लगाने के बाद भी मतदान प्रतिशत 2019 के चुनाव के मुकाबले काफी कम रहा। अब राजनीतिक दल इस बात से घबराए हुए हैं कि आखिर 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में हुए चुनाव में 8 प्रतिशत कम वोटिंग क्यों हुई? भाजपा ने तो हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट पर रखा था। बाइक सवारों का दल बनाया गया था। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने के लिए बाकायदा पीले चावल दिए गए थे। बावजूद इसके शाम तक हुई वोटिंग के बाद भी मतदान प्रतिशत घट गया। प्रदेश की पहले चरण की 6 सीटों में 67.08 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो कि पिछले 2019 के चुनाव की तुलना में करीब 8 कम है। चिंताजनक बात यह है कि मप्र की सभी छह लोकसभा सीटों में पिछले चुनाव के मुकाबले कम मतदान हुआ है।

भाजपा के लिए नाक का सवाल बनी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में कम मतदान होना पार्टी नेताओं को चौंका रहा है। छिंदवाड़ा में पूर्व में हुए चुनाव का आंकलन किया जाए तो पता चलता है कि जब-जब इस क्षेत्र में मतदान बढ़ा है तो भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन इस बार कम मतदान होने से भाजपा संशय में है। 2009 में 71.86 फीसदी मतदान हुआ था, कांग्रेस जीती थी। 2014 और 2019 के आम चुनाव मतदान प्रतिशत बढ़ा तो कांग्रेस की जीत का अंतर कम हुआ। 2014 में कांग्रेस के कमलनाथ 1 लाख 16 वोटों जीते थे। लेकिन 2019 में कांग्रेस के नकुलनाथ महज 37 हजार वोट के अंतर से बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। इस बार चुनाव में 2 प्रतिशत वोटिंग कम हुई है। अगर पुराने आंकलन सही साबित होते हैं तो यह खबर भाजपा के लिए कतई अच्छी नहीं है। छिंदवाड़ा में इस बार 79.18 प्रतिशत मतदान हुआ जबकि 2019 में 82.42 प्रतिशत मतदान हुआ था। सीधी में 2019 के मुकाबले 14 फीसदी कम, शहडोल में भी 11 फीसदी कम वोटिंग हुई है। इसी प्रकार मंडला की बात की जाए तो यहां 5 फीसदी कम मतदान हुआ है। जबलपुर लोकसभा में 9 फीसदी कम वोटिंग हुई। आदिवासी क्षेत्र सिहोरा में सबसे ज्यादा 65 प्रतिशत मतदान हुआ है। बालाघाट में भाजपा उम्मीदवार भारती पारधी का

तय होगा मंत्रियों और विधायकों का भविष्य

लोकसभा चुनाव में वोटिंग घटने पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मप्र के नेताओं को दो टूक शब्दों में कहा है कि जिन मंत्रियों के इलाकों में वोटिंग प्रतिशत कम होगा, उनका मंत्री पद चला जाएगा। बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा, जिनके क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। शाह के फरमान के बाद मप्र के मंत्रियों और अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है। गौरतलब है कि मप्र में भाजपा प्रदेश की सभी 29 सीटों को जीतने के लक्ष्य पर काम कर रही है। लेकिन सांसदों के लिए हो रहे इस चुनाव में भाजपा के 163 विधायकों की भी परीक्षा हो रही है। परीक्षा ऐसी-वैसी भी नहीं बल्कि अग्निपरीक्षा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि आलाकमान ने विधायकों को पहले से ही सचेत कर दिया है कि यह चुनाव उनका भविष्य भी तय करेगा। यानी लोकसभा चुनाव के दौरान जिस विधायक के क्षेत्र में पार्टी को अधिक वोट प्राप्त होगा उसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है और जिसके क्षेत्र में कम वोट मिलेगा उसके पर कतरे जा सकते हैं।

मुकाबला कांग्रेस सम्राट सिंह सरस्वार और बसपा के कंकर मुंजारे से है। यहां मतदान भले ही तीन से चार प्रतिशत कम हुआ हो लेकिन अभी भी भाजपा यहां संतुष्ट दिखाई दे रही है। राजनीतिज्ञों का कहना है कि कंकर मुंजारे ने कांग्रेस के वोट काटे होंगे, ऐसा कहा जा सकता है। शहडोल लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 10 फीसदी कम वोटिंग हुई। इससे कांग्रेस में उत्साह दिख रहा है। संभावित है कि भाजपा की मौजूदा सांसद हिमाद्री सिंह की जीत का मार्जिन कम हो सकता है।

इस बार का आम चुनाव वादों और दावों की जगह गारंटी और भरोसे का है। हालांकि पहले और दूसरे चरण के मतदान संपन्न हो गए हैं, इसके बावजूद केंद्रीय मुद्दों और प्रभावी नारों के अभाव में चुनाव प्रचार में उफान नहीं दिख रहा। शांत मतदाता न तो गारंटी की ओर भरोसे से देख रहे हैं और न ही भरोसे पर गारंटी देने का संकेत दे रहे हैं। न तो किसी मुद्दा विशेष पर देश में बहस छिड़ी है और न ही कोई ऐसा नारा है, जो लोगों की जुबान पर चढ़ा हो। हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के साथ कई क्षेत्रीय दल अपने-अपने मुद्दों को केंद्र में लाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। विपक्षी गठबंधन केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, चुनावी बॉन्ड और केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना के मुद्दे को तूल देने की कोशिश कर रहा है। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इनकी कोशिश केंद्रीय योजनाओं के कारण आए सकारात्मक बदलाव और हिंदुत्व से जुड़े राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद-370 का खात्मा, सीएए जैसी उपलब्धियों को मुद्दों के केंद्र में लाने की है। चुनाव प्रचार के उफान पर न आने का सबसे बड़ा कारण मुद्दों को लेकर विपक्ष में निरंतरता प्रदर्शित करने का अभाव है। खासतौर से विपक्षी गठबंधन बनने के बाद भी विपक्ष मैदान में खुलकर उतरने के बदले सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने में ही उलझा है। भले ही यह गठबंधन दो बार एक मंच पर आने में सफल रहा है, मगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी, शाह, नड्डा की तुलना में बहुत कम जनसभाओं को संबोधित किया है।

2019 का आमचुनाव इस चुनाव से बिल्कुल अलग था। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व ही सियासी मैदान भ्रष्टाचार बनाम राष्ट्रवाद का रूप ले चुका था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर चौकीदार चोर है, के नारे लगवा रहे थे, जबकि भाजपा पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ हुई एयर स्ट्राइक को मोदी है तो मुमकिन है नारा लगा रही थी। राफेल मामले में प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले को भाजपा गरीब पर हमले से जोड़ रही थी। इन दोनों ही मुद्दों पर तब राष्ट्रव्यापी चर्चा शुरू हो चुकी थी। घर-घर गारंटी अभियान की शुरुआत कर चुकी कांग्रेस ने पहली नौकरी पक्की, भर्ती भरोसा, पेपर लीक मुक्ति, गिग वर्कर सुरक्षा और युवा रोशनी गारंटी के रूप में अलग-अलग वर्गों को साधने की कोशिश की है। इसके अलावा पार्टी ने महिला, किसान, श्रमिक और हिस्सेदारी न्याय के तहत अलग-अलग वर्गों के लिए कई वादे किए हैं। वहीं एनडीए के लिए अबकी बार 400 पार, तो अपने लिए 370 सीटें जीतने का दावा कर रही भाजपा ने मतदाताओं को साधने के लिए ब्रांड मोदी को हथियार बनाया है। पार्टी युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तीकरण, किसानों के कल्याण और हाशिये पर पड़े कमजोर लोगों के सशक्तीकरण के लिए मोदी गारंटी दे रही है। जबकि विकसित भारत के निर्माण और देश की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी दे रही है। किसी एक मुद्दे को केंद्र में लाने की सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन की तमाम कोशिशें सिरे नहीं चढ़ी हैं। विपक्षी गठबंधन के नेता लालू प्रसाद की प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी के खिलाफ भाजपा ने मोदी का परिवार अभियान चलाया। भाजपा इंदिरा सरकार के समय तमिलनाडु से सटे कच्चातिवु द्वीप को श्रीलंका को दिए जाने के मुद्दे पर आक्रामक है।

वहीं, विपक्षी गठबंधन कभी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग, कभी चुनावी बॉन्ड में भ्रष्टाचार, तो कभी केंद्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि चुनाव मुद्दाविहीन रहा, तो हार-जीत तय करने में स्थानीय मुद्दे अहम भूमिका निभाएंगे। जो दल स्थानीय समीकरण साधेगा, चुनाव प्रबंधन बेहतर होगा, वह बाजी मार लेगा। विश्लेषक इसके लिए पांच राज्यों के हालिया विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हैं। कर्नाटक और तेलंगाना में भ्रष्टाचार मुद्दा था, जबकि मप्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान करीब-करीब मुद्दाविहीन था। इस कारण कर्नाटक व तेलंगाना में सत्ता बदली, जबकि तीन राज्यों में भाजपा ने बेहतर प्रबंधन से बाजी मार ली।

● **कुमार राजेंद्र**

बागी बिगाड़ेंगे भाजपा और कांग्रेस का गणित

लोकसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के कई बागी नेता भी ताल ठोक रहे हैं। जातिगत समीकरणों से प्रभावित होने वाली चंबल और विंध्य क्षेत्र की 5 सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बगावती नेताओं ने दोनों पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया है। ये जीतने में भले कामयाब न हों, लेकिन जातिगत वोटों की गोलबंदी कर हार-जीत के मार्जिन को घटा या बढ़ा सकते हैं। भाजपा ने ग्वालियर ग्रामीण के पूर्व विधायक भारत सिंह कुशवाह को लोकसभा का टिकट दिया है, जिन्हें कांग्रेस के साहब सिंह गुर्जर ने 2023 के चुनाव में हराया था। कुशवाह के खिलाफ गुर्जर समाज गोलबंद हैं। कांग्रेस से ग्वालियर पूर्व सीट से हारे प्रवीण पाठक मैदान में हैं, जिन्हें नारायण सिंह कुशवाह ने चुनाव हराया था। कांग्रेस से दावेदारी में आगे रहे पूर्व सांसद रामसेवक गुर्जर टिकट कटने से खफा चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस से जुड़े एक प्रॉपर्टी कारोबारी कल्याण सिंह गुर्जर अचानक बसपा के टिकट पर मैदान में कूद गए हैं। सूत्रों के मुताबिक बसपा से गुर्जर को टिकट दिलाने के पीछे भाजपा की रणनीति है, ताकि कांग्रेस को एकमुश्त मिलने वाले गुर्जर वोटों में सेंध लगाई जा सके। भाजपा ने नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक दिमनी के पूर्व विधायक शिवमंगल सिंह तोमर को उतारा है। कांग्रेस ने सुमावली से भाजपा के पूर्व विधायक रहे सत्यपाल सिंह सिकरवार (नीटू) को टिकट दिया है। दोनों प्रत्याशी क्षत्रिय समाज से आते हैं। कांग्रेस के टिकट की दौड़ में शामिल रहे रमेश गर्ग ने बगावती रुख अपनाते हुए बसपा के टिकट पर ताल ठोक दी है। वे कांग्रेस के शहरी वोटर्स के साथ ही भाजपा के परंपरागत वैश्य वर्ग के मतों में सेंध लगा सकते हैं। भिंड सीट अजा के लिए आरक्षित है। भाजपा ने मौजूदा सांसद संध्या राय और कांग्रेस ने फूलसिंह बरैया को उतारा है। टिकट कटने से खफा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता व 2019 में प्रत्याशी रहे देवाशीष जरारिया बसपा के टिकट पर चुनाव में कूद गए हैं।

वन विभाग की कुंजी रणजीत के हाथ

मप्र में अगर किसी से पूछा जाए कि वन मंत्री कौन हैं, तो हर कोई यही कहेगा कि नागर सिंह चौहान। लेकिन अफसरों की मानें तो वित्तीय सेवा के अधिकारी रंजीत सिंह चौहान ही वन विभाग को चला रहे हैं। यानी विभाग में किसको कहां पदस्थ करना है, किस ठेकेदार को काम देना है, ऐसी सारी व्यवस्था रणजीत सिंह चौहान ही देख रहे हैं। इस कारण अब तो लोग नागर सिंह चौहान को शैडो वन मंत्री कहने लगे हैं। वित्तीय सेवा के अधिकारी रणजीत सिंह चौहान पूर्व में भी वन विभाग मुख्यालय में अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे हैं। इसके अलावा तत्कालीन अपर मुख्य सचिव वन केके सिंह के सलाहकार के रूप में मंत्रालय में काम कर चुके हैं। कुछेक महीने पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघार के यहां भी बिना औपचारिक आदेश के कार्यरत थे। सिंघार के यहां आते ही उन्होंने वन बल प्रमुख के वाहन की डिमांड कर दी। जब फॉरेस्ट अधिकारियों ने उन्हें नियमों का हवाला देते हुए उनकी मनपसंद वाहन के लिए अपात्र बताया तब वे वन मंत्री के कान भरने लगे थे। इसी दौरान सीनियर आईएफएस अधिकारियों की मौखिक और लिखित शिकायत मंत्री तक पहुंचने लगी और अंतत: वे वहां से रुखसत कर दिए गए।

अब नागर सिंह चौहान वन मंत्री तो बन गए किंतु उनका मंत्रालय अपर संचालक स्तर के वित्तीय सेवा के अधिकारी रणजीत सिंह चौहान संचालित कर रहे हैं। जंगल महकमे में उन्हें शैडो वन मंत्री के रूप में देखा जा रहा है। विभाग में सप्लायर का वर्क आर्डर जारी करना हो या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग, ये सभी कार्य अधिकारियों से मिलकर वह स्वयं कर रहे हैं। यही कारण है कि विधायकों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की सिफारिशी तबादला आदेश चुनाव आचार संहिता लगने के पूर्व जारी नहीं हो सके। वन विभाग में अधिकांश अधिकारी वन मंत्री चौहान के अनाधिकृत ओएसडी रणजीत सिंह चौहान को शैडो मंत्री के रूप में देखते हैं। फील्ड में पदस्थ डीएफओ यह मानते हैं कि रणजीत सिंह चौहान उनके नजदीकी हैं। उनकी मान्यताओं पर तब और बल मिलता है, जब अधिकारी अपने मंत्री से मिलने जाते हैं और वे उन्हें चौहान से मिलने का संकेत दे देते हैं। इसके कारण ही विभाग के अफसर उन्हें शैडो वन मंत्री के रूप में देखते हैं। अब नेताओं को भी ऐसा एहसास होने लगा है, वह इसलिए कि धार, झाबुआ और अलीराजपुर के विधायकों एवं नेताओं ने वन विभाग के डीएफओ, एसडीओ से लेकर रेंजरों को हटाने और उनकी प्राइम पोस्टिंग करने की सिफारिश की थी। वन मंत्री चौहान ने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मंथन कर सूची तैयार कर मंत्रालय को भेजी। इस बीच पार्टी हाईकमान ने उनकी पत्नी अनीता सिंह चौहान को झाबुआ-रतलाम लोकसभा सीट का प्रत्याशी बनाया गया है। सूत्रों का कहना है कि एक खनन व्यवसायी के भाई मंत्रीजी की पत्नी के चुनाव का खर्च उठा रहे हैं। गौरतलब है कि मंत्रीजी के विभाग में तबादलों का काम भी कुछ हद तक यही व्यवसायी देख रहे हैं। उधर, मंत्रीजी झाबुआ-रतलाम लोकसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त हो गए और इसका लाभ उठाते हुए विधायकों के सिफारिश वाले अधिकारियों के तबादले की सूची में नाम हटाकर रणजीत सिंह चौहान ने अपने पसंदीदा डीएफओ, एसडीओ और रेंजरों के तबादला आदेश आचार संहिता लगने के चंद घंटे पहले जारी करवा दिए। वन मंत्री के नजदीकी सूत्रों का कहना है कि विधायकों और नेताओं की अनुशंसा वाले तबादले आदेश जारी नहीं होने के कारण वन मंत्री के प्रति नाराजगी है और वे चुनाव बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से शिकायत करने का मन बना चुके हैं।

वन विभाग में लंबे समय से सप्लायर का एक नेक्सस सक्रिय है। इस सिंडिकेट से वन मंत्री चौहान के अनाधिकृत ओएसडी भी जुड़ गए हैं। दबाव के चलते ही महकमे में एक दर्जन से अधिक डीएफओ ने चैन लिंक और वायरबेड खरीदी की निविदा में ऐसी शर्त जोड़ दी, जिससे केवल चौहान के नजदीकी फर्म को ही वर्क आर्डर मिल सके। बताया जाता है कि डीएफओ को फोन करके अपने चहेते फर्म को ठेका दिलवाने के लिए नई-नई शर्तें जुड़वा रहे हैं। दक्षिण सागर, बैतूल और बालाघाट समेत एक दर्जन डीएफओ ने चैनलिंक और वायरबेड खरीदी के लिए निविदा आमंत्रित की हैं। इस निविदा में 3 करोड़ के टर्न-ओवर के साथ यह शर्त भी जोड़ दी कि भारत मानक ब्यूरो से मान्यता प्राप्त फर्म ही निविदा में हिस्सा ले सकेंगी। यह शर्त पहली बार जोड़ी गई। इस शर्त के कारण तीन दर्जन से अधिक संस्थाएं प्रतिस्पर्धा से बाहर हो गई। मप्र में भारतीय मानक ब्यूरो से लाइसेंस प्राप्त दो फर्म ही रजिस्टर्ड हैं। यह दोनों फर्म ही कांग्रेस नेता के रिश्तेदार की हैं। यानी कांग्रेस नेता के रिश्तेदार को उपकृत करने के लिए प्रदेश के एक दर्जन डीएफओ ने पहली बार यह शर्त निविदा में जोड़ दी है। यह बात अलग है कि प्रतिस्पर्धा से बाहर हुई संस्थाओं ने शिकवे-शिकायतें शुरू कर दी हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

पूर्व में भी इनके खिलाफ की गई थी शिकायतें

पूर्व में इनके विरूद्ध श्रीनिवास मूर्ति सदस्य सचिव जैव विविधता बोर्ड की शिकायत पर भी शासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपर मुख्य सचिव केके सिंह के वित्तीय सलाहकार रहते हुए इनके द्वारा अपने लिए लग्जरी कार की मांग एवं अतिरिक्त वित्तीय लाभ लेने के कारण हटाए गए थे। बिजनेस रूल का हवाला देते हुए गलत तरीके से शासन में बैठे अधिकारियों के बीच कार्य विभाजन करवाने के पीछे भी चौहान ही मुख्य सूत्रधार थे। इस मुद्दे पर तत्कालीन वन मंत्री उमंग सिंघार और अतिरिक्त मुख्य सचिव एपी श्रीवास्तव के बीच विवाद ब्यूरोक्रेसी में खूब उछला था और मामला अभी भी जांच के लिए लंबित है। वित्त विभाग से गैर हाजिर होकर वन मंत्री के लिए ओएसडी के रूप में काम करने वाले के खिलाफ मुख्य सचिव वीरा राणा से भी शिकायत की गई है। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने पत्र लिखा है कि रणजीत सिंह चौहान वित्त विभाग से गैरहाजिर होकर वन मंत्री नागर सिंह चौहान के लिए अनाधिकृत तौर पर ओएसडी के रूप में काम कर रहे हैं। चौहान स्वयं को ओएसडी बताकर विभाग के सीनियर आईएफएस अधिकारियों से लेकर डीएफओ तक पर दबाव डालकर अपनी मनमर्जी से काम करवा रहे हैं। रणजीत सिंह चौहान वित्तीय सेवा अधिकारी जिसकी सेवाएं प्रमुख सचिव वित्त विभाग द्वारा अभी तक विधिवत तौर पर प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को स्थानांतरित नहीं की हैं। दिलचस्प पहलू यह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय ने भी इनके द्वारा वन मंत्री के जरिए भिजवाई गई ओएसडी बनाने संबंधित नोटशीट भी वापस कर दी गई है।

चुनावी चक्कर में बिखर रहे परिवार

विधायक पत्नी ने किया पति के खिलाफ प्रचार

बालाघाट में राजनीति के लिए एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी करने वाले कंकर मुंजारे और अनुभा मुंजारे एक-दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाते रहे। बालाघाट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी कंकर मुंजारे कहते हैं कि जब ओलावृष्टि हुई और किसानों की फसल बर्बाद हो गई तो अनुभा मुंजारे कहां थीं? तब विधायक क्षेत्र के किसानों को अपने हाल पर छोड़कर काशी-मथुरा घूम रही थीं। अब ये वो अनुभा मुंजारे नहीं रहीं। ये भ्रष्टाचारियों के साथ मिल गई हैं। मुंजारे हर सभा में इस बयान को दोहराकर अपनी विधायक पत्नी अनुभा मुंजारे के खिलाफ बोलते रहे। दूसरी तरफ, बालाघाट से कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे सभाओं और बैठकों में कांग्रेस उम्मीदवार सम्राट सिंह सरस्वार के लिए वोट मांगती रहीं। पति-पत्नी के बीच का ये वैचारिक मतभेद प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है।

देश की राजनीति ऐसी होती जा रही है कि समाज में ही बंटवारा नहीं हो रहा बल्कि घरों में भी फूट पड़ रही है और पति पत्नी के रिश्ते तक बिखर रहे हैं। मप्र की बालाघाट लोकसभा सीट पर इन दिनों कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जहां पति-पत्नी के दिलों में राजनीति ने दरार पैदा कर दी है। 1989 में बालाघाट से निर्दलीय सांसद कंकर मुंजारे परसवाड़ा विधानसभा सीट से 1985 में जनता पार्टी की टिकट पर, 1993 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी से और 1998 में पुन: जनता पार्टी की टिकट पर विधायक चुने गए थे जबकि इनकी पत्नी अनुभा मुंजारे सात बार विधानसभा चुनाव और तीन बार सांसदी का चुनाव लड़ने के पश्चात आखिरकार 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बालाघाट विधानसभा सीट से पहली महिला विधायक बनने में सफल हुईं। इस हिसाब से कंकर मुंजारे का राजनीतिक अनुभव अपनी पत्नी के मुकाबले अधिक है जिसे अनुभा भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि वे अपने पति के चलते ही राजनीति में आई अन्यथा वे स्कूल में अध्यापिका होतीं। विपरीत वैचारिक मत के बाद भी दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे का सम्मान करते हैं किंतु लोकसभा चुनाव में अब एक-दूसरे पर जमकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं।

दरअसल, कंकर मुंजारे इस बार बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर बालाघाट संसदीय सीट से लोकसभा प्रत्याशी हैं जबकि उनकी पत्नी कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह सरस्वार के लिए वोट मांग रही हैं। हालांकि ऐसा पहले भी हुआ है कि एक ही परिवार के सदस्य भिन्न प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार करें किंतु इन पति-पत्नी का मामला अनोखा होता जा रहा है। कंकर मुंजारे ने वैचारिक मतभेद के चलते अपना घर छोड़कर बालाघाट से 20 किलोमीटर दूर खेत में झोपड़ी बना ली है और वे वहीं रह रहे हैं जबकि उनकी पत्नी अपने बेटे के साथ घर में रहती हैं। कंकर मुंजारे कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सिंह पर राजनीतिक हमले करने के बजाय अपनी विधायक पत्नी पर क्षेत्र की अनदेखी करने और ओलावृष्टि के समय मथुरा-वृंदावन घूमने का आरोप लगा रहे हैं, जिस पर उनकी पत्नी सब आपसे ही सीखा है, कहकर कंकर मुंजारे को असहज कर रही हैं। कंकर तो यहां तक भी बोल गए कि यदि अनुभा उनकी पत्नी न होतीं तो वे विधायक बनने के लायक ही नहीं थीं। दोनों के बीच वैचारिक मतभेद उनके घर पर भी दिख रहा है जहां कांग्रेस का झंडा लगा है और बसपा का झंडा कंकर मुंजारे ने उतारकर अपनी झोपड़ी पर लगा दिया है। 19 अप्रैल को प्रथम चरण के मतदान में बालाघाट सीट पर जब मतदान पूर्ण होने के बाद कंकर मुंजारे ने अपने घर वापस जाने की बात कही थीं, किंतु जो राजनीतिक अलगाव दोनों में हो गया है, उससे क्या इनका आपसी सामंजस्य और वैवाहिक जीवन पटरी पर आ पाएगा, यह मप्र में चर्चा का विषय बन गया है। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि कंकर मुंजारे कांग्रेस से लोकसभा का टिकट मांग रहे थे जो उन्हें नहीं मिला और अनुभा मुंजारे जिन सम्राट सिंह का चुनाव प्रचार कर रही हैं, उनके पिता अशोक सिंह सरस्वार से वे स्वयं दो बार विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं।

शरद पवार के गढ़ बारामती लोकसभा में भी स्थिति ऐसी बन गई है जो आम जनता के साथ ही पवार परिवार को असहज कर रही है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के सामने एनसीपी संस्थापक शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले खड़ी हैं जिससे पहले से छिन्न-भिन्न पवार परिवार में और कलह बढ़ गई है। ननद-भाभी के बीच की लड़ाई ने चाचा-भतीजा के आपसी मतभेद को मनभेद में बदल दिया है। शरद पवार किसी भी कीमत पर सुप्रिया सुले को जिताना चाहते हैं जबकि अजीत पवार अपनी पत्नी के सहारे अपने चाचा को राजनीतिक रूप से समाप्त करना चाहते हैं। यह तभी संभव है, जब वे चाचा से बारामती छीन लें क्योंकि चाचा की राजनीतिक गर्भनाल बारामती है। एक बार बारामती से चाचा को दूर किया तो पूरी राजनीतिक विरासत पर अजीत पवार का कब्जा हो जाएगा। तब सुप्रिया सुले को भी उनकी सरपरस्ती में आना होगा और यही शरद पवार नहीं चाहते। इसलिए शरद पवार सुप्रिया की जीत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे किंतु क्षेत्र में अजीत पवार का भी खासा समर्थक वर्ग है जो शरद पवार को चिंतित कर रहा है। राजनीतिक विरासत के चलते टूट चुके पवार परिवार की वैचारिक लड़ाई अब परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी दुविधा का कारण बन रही है। 2019 में लोकसभा चुनाव से पूर्व तृणमूल कांग्रेस के नेता सौमित्र खान ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था और विष्णुपुर लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद भी बन गए। उनके चुनाव प्रचार में उनकी पत्नी सुजाता मंडल ने दिन-रात एक कर दिए किंतु 2022 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान सुजाता मंडल ने भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता ले ली जिससे उखड़कर सौमित्र खान ने सुजाता मंडल से तलाक ले लिया। दोनों राजनीति की अलग-अलग पटरियों पर सरपट दौड़ रहे थे किंतु लोकसभा चुनाव ने दोनों को पुन: एक-दूसरे के सामने ला खड़ा किया। सौमित्र खान विष्णुपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हैं जबकि सुजाता मंडल को तृणमूल कांग्रेस ने इसी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है।

● **सुनील सिंह**

निगम का ड्रेनेज महाघोटाला

इंदौर नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक निगम प्रशासन दावा करता आ रहा था कि घोटाले में 28 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया, लेकिन पुलिस जांच में खुलासा हो गया है कि आरोपी पांचों फर्म 20 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाल भी चुकी हैं और उसके एवज में निगम ने जीएसटी भी जमा करवा दिया है। इस तरह यह घोटाला 107 करोड़ रुपए का हो चुका है। हैरानी यह है कि इन कंपनियों ने **वर्क ऑर्डर,** रॉयल्टी कटौत्रा, लेवल शीट, मटेरियल, नक्शा और साइट की फोटो, एमबी सभी की हूबहू नकल की। लालच में इन्होंने मात्र एक दिन में पांच-पांच किमी लाइनों की खुदाई, ड्रेनेज लाइन डालना, 500 चैंबर बनाना, ट्रेंच को भरना, जैसे सभी कामों की एंट्री कर दी। बावजूद इन्हें 20 करोड़ का भुगतान हो चुका है। निगम ने नींव कंस्ट्रक्शन (मो. साजिद), ग्रीन कंस्ट्रक्शन (मो. सिद्दीकी), किंग कंस्ट्रक्शन (मो. जाकिर), क्षितिज इंटरप्राइजेज (रेणु वडेरा) व जान्हवी इंटरप्राइजेज (राहुल वडेरा) के खिलाफ एफआईआर करवाई थी।

नगर निगम में हुए 107 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले में गत दिनों दो ठेकेदार भाइयों मो. जाकिर और मो. साजिद ने एमजी रोड थाने में सरेंडर कर दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि दोनों को आईटी पार्क से गिरफ्तार किया है। दोनों पर 10 हजार रुपए का ईनाम घोषित था। इसके बाद नगर निगम के सब इंजीनियर उदयसिंह सिसोदिया और कम्प्यूटर ऑपरेटर चेतन भदौरिया को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने ठेकेदार राहुल बडेरा और उनकी पत्नी रेणु बडेरा को भी विजय नगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। अब उम्मीद जगी है कि इस घोटाले की तह तक पहुंचा जा सकेगा। गौरतलब है कि इस महाघोटाले में वर्क ऑर्डर नंबर भी पुराने लगाए गए। विशेष मद से भुगतान की कोशिश की गई। आवक-जावक नंबर के साथ ही टेंडर के नंबर भी गलत दर्ज किए गए। पुरानी फाइलों के नंबर लिए गए। वर्कऑर्डर भी फर्जी बनाया गया। भुगतान के लिए ड्रेनेज शाखा के फंड का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। विशेष मद से यह फर्जी कंपनियां बजट उड़ाने के चक्कर में थी। जिन बिल क्रमांक का उल्लेख किया गया, ड्रेनेज शाखा में उन नंबरों पर अन्य बिलों की जानकारी चस्पा थी। मामले से जुड़े ड्रेनेज और लेखा शाखा के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित अन्य ने भी पुलिस विभाग को जांच के लिए नमूने दे दिए हैं।

निगमायुक्त शिवम वर्मा ने बैंकों से इन फर्म के खातों पर रोक लगाने को कहा था, पर स्टेटमेंट से पता लगा कि करोड़ों रुपए का भुगतान हो चुका है। जिन कामों के लिए 30 से 40 लाख का टेंडर हुआ, उसके लिए एक से डेढ़ करोड़ के बिल लगाए गए। 12 प्रतिशत के हिसाब से निगम ने जीएसटी भी चुकाया। पुलिस ने पहले 20 फाइल जब्त की फिर 13 फाइल्स और मंगवाई। इस तरह ड्रेनेज शाखा से 33 फाइल और कुल 36 फाइलें पुलिस ने जब्त की हैं। उधर, निगम की जांच समिति भी निगमायुक्त को दो-तीन दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही से कार की डिक्की में रखी फाइलें चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट भी एमजी रोड थाने पर ही घोटाले उजागर होने के एक महीने पहले दर्ज करवाई। अभी तो सतह पर यह सिर्फ 107 करोड़ का घोटाला ही दिख रहा है, मगर इसकी खुदाई ड्रेनेज की तरह ही अगर की जाए तो **यह 150 करोड़** या उससे भी अधिक तक पहुंच जाएगा, क्योंकि वर्षों से ठेकेदारों, नेताओं और अफसरों, कर्मचारियों की मिलीभगत से यह खेल चलता रहा है। अब हालांकि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी इस पूरे घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग जहां प्रमुख सचिव से की है। वहीं उनका कहना है कि यह आश्चर्य का विषय है कि जिस अधिकारी को इस घोटाले की जांच करनी थी, उसी की कार की डिक्की से चोरी कैसे हो जाती है। सालों से यह घोटाला चल रहा है, लेकिन किसी अधिकारी-कर्मचारी ने इसे पकड़ा नहीं और जब पोल खुली तो एफआईआर दर्ज कराने से लेकर अन्य प्रक्रिया शुरू की गई। महापौर का स्पष्ट कहना है कि वे इस तरह की गंदगी को अपने कार्यकाल में पूरी तरह से साफ करेंगे।

● **अरविंद नारद**

फर्जी हस्ताक्षरों के साथ बोगस लॉगइन-पासवर्ड का भी इस्तेमाल

उल्लेखनीय है कि अभी तो ई-नगर पालिका के चलते सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। मगर कुछ वर्ष पूर्व लेगेसी पर काम होता था। अभी सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इन फाइलों पर अपने फर्जी हस्ताक्षर बताए हैं। हालांकि पुलिस द्वारा नमूने लेकर हस्ताक्षरों की जांच तो की जा रही है, मगर एक और बड़ा मामला लॉगइन-पासवर्ड का भी है, क्योंकि ये सारे भुगतान 2021-22 और उसके बाद हुए हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि चूंकि ओटीपी नहीं आता है इसलिए यह पता लगाना मुश्किल है कि इन लॉगइन-पासवर्ड का इस्तेमाल कैसे और किसने किया। हालांकि निगम का आईटी विभाग इसकी जांच में जुटा है, क्योंकि बिना अंदरूनी व्यक्ति के लॉगइन-पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं हो सकता। इस महाघोटाले में लिप्त पांचों फर्जी कंपनियों न्यू कंस्ट्रक्शन, ग्रीन और किंग कंस्ट्रक्शन के साथ क्षितिज और जान्हवी इंटरप्राइजेस के कर्ताधर्ताओं से जुड़ी अचल संपत्तियों की जानकारी भी पुलिस ने निगम से मांगी है। राहुल बडेरा और रेणु बडेरा के बेशकीमती-आलीशान बंगले का खुलासा हो चुका है, जो कि पुलिसिया जांच में बड़ा मददगार साबित हुआ। वहीं अपोलो डीबी सिटी में ही इनका एक फ्लेट भी है। वहीं अन्य फर्मों के मोहम्मद सिद्दीकी व अन्य की मदीना नगर में संपत्तियां मिली हैं। अब कोर्ट आदेश पर पुलिस इन संपत्तियों की कुर्की भी करवाएगी। हालांकि इन भगोड़े ठेकेदारों की और भी संपत्तियां हैं, जो उन्होंने अपने रिश्तेदारों या अन्य के नाम पर खरीद रखी हैं।

आदिवासी होंगे अपराध मुक्त!

आदिवासियों से छीना जा रहा है वनाधिकार

सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाले राज्य, मप्र ने सितंबर 2019 में एमपी वनमित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया। इस वेब पोर्टल का मकसद था कि खारिज कर दिए गए दावों के लिए दावेदारों को फिर से आवेदन करने की अनुमति मिल सके और साथ ही नए दावेदारों के लिए आईएफआर जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। 2008 में एफआरए के लागू होने से लेकर जनवरी 2019 तक, मप्र को 5,79,411 आईएफआर के दावे प्राप्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेश के अनुसार, इनमें से 2,24,624 दावों को मंजूरी मिली और 3,54,787 को खारिज किया गया। यानी 61.2 प्रतिशत दावों को नामंजूर कर दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेश के बाद राज्य को एमपी वनमित्र पोर्टल के माध्यम से जिला स्तर पर 1,74,525 आईएफआर दावे मिले। मप्र के एक शोधकर्ता को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के माध्यम से जो आंकड़े मिले, उनसे पता चलता है कि इनमें से अक्टूबर 2022 तक 1,51,929 दावों को प्रोसेस किया गया, जिनमें से 1,16,758 को खारिज कर दिया गया। ये शोधकर्ता अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते।

2008 के बाद मप्र सरकार एक बार फिर से आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध वापस लेने की तैयारी कर रही है। यानी 16 साल बाद एक बार फिर आदिवासियों को अपराधमुक्त किया जाएगा। सरकार स्तर पर यह फैसला होने के बाद वन विभाग ने हर साल दर्ज होने वाले करीब 50 हजार वन अपराधों में से आदिवासियों के प्रकरणों की छंटाई शुरू कर दी है। विभाग का दावा है कि इस संबंध में निर्देश आते ही कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। आदिवासियों पर वन भूमि पर कब्जे, अवैध कटाई सहित अन्य मामलों में पिछले 10 साल में करीब 15 हजार प्रकरण दर्ज हुए हैं। राज्य सरकार आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध वापस लेने जा रही है। इसके लिए सरकार ने वन विभाग को एक्शन प्लान बनाकर प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। यही नहीं, जो प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है, उन्हें तत्काल शासकीय अधिवक्ता के माध्यम से निराकरण कराने के लिए कहा गया है। पीसीसीएफ संरक्षण शाखा ने जारी निर्देशों में कहा है कि सभी डीएफओ आदिवासियों पर दर्ज किए गए वन अपराध प्रकरणों को शासन की मंशा के अनुरूप नियमानुसार त्वरित रूप से नस्तीबद्ध करने के लिए कार्रवाई करें। इसके अलावा, वन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की जाए।

सरकार ने आदिवासियों पर दर्ज आपराधिक प्रकरण वापस लेने का निर्णय लिया है। इसमें वन अपराध भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक जंगलों में रहने और रोजमर्रा की जरूरतों के चलते आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अपराध भी वन विभाग ही दर्ज करता है। इसमें लकड़ी चोरी, वनभूमि पर अतिक्रमण और शिकार के मामले होते हैं। वर्ष 2008 से अब तक हर साल करीब एक हजार मामले दर्ज हुए हैं। पीसीसीएफ संरक्षण शाखा ने कालातीत वन अपराध प्रकरणों की समीक्षा वनमंडल स्तर पर स्वयं वनमंडलाधिकारी निरंतर करते रहें। इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाए। मुख्य वनसंरक्षक भी समय-समय पर मासिक बैठक में बिंदु समीक्षा कर यह तय करेंगे कि कोई प्रकरण कालातीत न हो। भारतीय वन अधिनियम 1927 में हुए नवीन संशोधनों का अध्ययन कर अधीनस्थ स्टाफ को अवगत कराया जाए। वन विभाग विभिन्न वन अपराधों में राजसात किए गए वाहनों का सरकारी नंबर लेकर उनका विभागीय कार्यों में उपयोग करेगा। इस संबंध में उच्च स्तर से निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी वनमंडलों के अंतर्गत वन अपराध प्रकरणों में राजसात किए गए वाहनों में यदि कोई वाहन विभागीय उपयोग हेतु उपलब्ध हो, तो उसका विधिवत प्रस्ताव तैयार कर मुख्य वनसंरक्षक विभागीय उपयोग करने की अनुमति प्रदान करेंगे। साथ ही अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (समन्वय) भोपाल मुख्यालय से वाहन उनके वनमंडल को आवंटित कराएंगे एवं आरटीओ भोपाल से सरकारी नंबर एमपी-02 प्राप्त करेंगे। यदि उनके वनमंडल में वाहनों की आवश्यकता न हो, तो अन्य वनमंडलों से वाहन उपयोग में लिए जाने का अनुरोध कर सकते हैं। राजसात की कार्रवाई समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि विभाग आमतौर पर हर साल 50 हजार वन अपराध दर्ज करता है। इनमें से करीब आठ हजार मामले आदिवासियों के खिलाफ दर्ज किए जाते हैं। जबकि करीब छह हजार मामले पांच सौ, एक हजार रुपए के अर्थदंड के बाद समाप्त हो जाते हैं और शेष मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं। सरकार ने विधानसभा चुनाव के ठीक पहले वर्ष 2008 में भी आदिवासियों के खिलाफ तमाम कोर्ट में चल रहे आपराधिक प्रकरण वापस लिए थे। तब विभाग ने 87 हजार 549 वन अपराध वापस लिए थे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक डॉ. श्रीवास्तव ने बुरहानपुर के फील्ड के अफसरों को आपराधिक प्रकरण के निराकरण के लिए 3 महीने का समय दिया है। प्रदेश में सबसे अधिक वन अपराध के प्रकरण बुरहानपुर में ही दर्ज हुए हैं। डॉ. श्रीवास्तव ने अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि बुरहानपुर में आदिवासियों पर वन अधिनियम 1927 और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत दर्ज 513 प्रकरण न्यायालय में लंबित है। सरकारी वकीलों के जरिए इन प्रकरणों का निराकरण करवाएं। यहां यह उल्लेखनीय है कि बुरहानपुर जिले में कुल 1 लाख 90 हजार 100 हेक्टेयर जंगल है। 17000 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रामकों को पट्टे के रूप में बांट दी गई है। सूत्रों की मानें तो बुरहानपुर में करीब 58000 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण माफिया ने कब्जा कर लिया है।

जानकारी के अनुसार 10 वर्षों में 15,000 से अधिक आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध को वापस लेने के लिए वन विभाग के एक्शन प्लान में न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों को निपटाने के लिए शासकीय अधिवक्ताओं को कहा गया है। वहीं पीसीसीएफ संरक्षण शाखा ने अन्य वर्ग पर दर्ज वन अपराधिक प्रकरण वापस होंगे अथवा नहीं, यह स्पष्ट नहीं किया है। जानकारी के मुताबिक निर्देशों के बाद ही प्रकरणों को समाप्त करने के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) डॉ. अजीत कुमार श्रीवास्तव ने एक्शन प्लान तैयार कर सीसीएफ और डीएफओ को भेज दिया है।

● **धर्मेंद्र सिंह कथूरिया**

मप्र में बढ़ते अपराध पर नकेल कसने के लिए सरकार ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की है। इस व्यवस्था को लागू हुए तकरीबन 27 महीने बीत चुके हैं। इसका असर यह हुआ है कि भोपाल और इंदौर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। सरकार भी इसका आंकलन कर रही है और संस्कारधानी जबलपुर और ग्वालियर में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की योजना पर मंथन चल रहा है।

27 महीने में अपराधों पर लगा अंकुश

कुछ साल पहले तक अपराधियों की शरणस्थली के रूप में कुख्यात रहे मप्र में अब न बड़े अपराधी बचे हैं और न अपराध बढ़ रहा है। इसका श्रेय भोपाल-इंदौर में लागू हुए पुलिस कमिश्नर सिस्टम और सरकार की सख्ती को जाता है। एनसीआरबी की पुरानी रिपोर्ट्स के अनुसार, मप्र में सबसे अधिक भोपाल और इंदौर में अपराध होते थे। इसको देखते हुए सरकार ने प्रदेश के दोनों बड़े शहरों भोपाल और इंदौर में 9 दिसंबर 2021 को पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की थी। भोपाल की कमान मकरंद देउस्कर और इंदौर की कमान हरिनारायणाचारी मिश्र को सौंपी गई थी। दोनों की परफॉर्मेंस को देखते हुए सरकार ने इनकी अदला-बदली कर दी। यानी मकरंद देउस्कर को इंदौर और हरिनारायणाचारी मिश्र को भोपाल का पुलिस कमिश्नर बना दिया। हालांकि कुछ दिन बाद मकरंद देउस्कर का बीएसएफ का आईजी बनाकर भेज दिया गया और इंदौर में राकेश कुमार गुप्ता को पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।

भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने का असर पूरे प्रदेश पर पड़ा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 27 महीने में अपराधों पर अंकुश लगा है। खासकर 2023 में कानून-व्यवस्था का सबसे अधिक असर दिखा है। मप्र पुलिस ने साल 2023 में प्रदेश में अपराध नियंत्रण के साथ ही कट्टरपंथी संगठनों एवं माफियाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है। जिससे लोगों में सुरक्षा का भाव बढ़ा है। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए मप्र पुलिस प्रतिबद्ध है। उनके सशक्तिकरण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पुलिस द्वारा कई प्रयास किए गए। पुलिस ने जमीनी स्तर पर क्षमताओं को बढ़ाते हुए तकनीकी तंत्र को भी मजबूत बनाया। जिसके उपयोग से जघन्य एवं गंभीर अपराधों को खोजने में उल्लेखनीय सफलता मिली। समाज को जागरूक करने एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच बढ़ाई गई। पुलिस शारीरिक एवं मानसिक रूप से दक्ष हो, इसके लिए भी पुलिसकर्मियों का कौशल संवर्धन एवं क्षमता उन्नयन किया गया। पुलिस ने अपने आदर्श वाक्य देशभक्ति-जनसेवा को सार्थक किया।

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक मप्र में 2023 में अपराधों में कमी आई है। एससी-एसटी के खिलाफ होने वाले अपराधों पर प्रशासन ने नकेल कसी है। मप्र पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों एचयूटी, जेएमबी, पीएफआई पर कार्रवाई की गई। 2022 की तुलना में 2023 में कुल अपराध में 0.41 प्रतिशत की कमी आई। हत्या में 10.90 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 10.24 प्रतिशत और डकैती में 26.47 प्रतिशत की कमी आई। बच्चों पर होने वाले अपराधों में भी 13.93 प्रतिशत की कमी आई है। अनुसूचित जाति के खिलाफ घटित अपराधों में 4.12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के खिलाफ घटित अपराधों में 13.81 प्रतिशत की कमी आई। ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 23,500 लाउड स्पीकरों को हटाया गया। ऑपरेशन मुस्कान में 11609 बच्चों को ढूंढा गया। भू-माफिया पर 52 केस दर्ज कर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जबकि 10 आरोपियों के खिलाफ जिलाबदर की कार्रवाई की गई। रेत माफिया पर 1,565 केस दर्ज कर 1007 आरोपी गिरफ्तार किए गए और 1599 चारपहिया वाहन जब्त किए गए। चिटफंड माफिया पर पुलिस ने 42 केस दर्ज कर 88 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 785 से अधिक निवेशकों को 2.54 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वापस दिलाई गई। शराब माफिया पर 1 लाख 31 हजार से अधिक केस दर्ज किए गए,

सबसे अधिक उप्र के बदमाश

पुलिस ने अपराधियों की सूची तैयार कर गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उप्र पुलिस को भेज दी है। सबसे ज्यादा अपराधी उप्र के हैं। जो मप्र से सटे जिलों में अपराध कर फरार हो चुके हैं। पीएचक्यू द्वारा जारी की गई सूची के अनुसार फरार अपराधियों में छत्तीसगढ़ के 400, गुजरात के 292, महाराष्ट्र के 1111, राजस्थान के 2198 और उप्र के 4400 हैं। पीएचक्यू के अधिकारियों का कहना है कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पड़ोसी राज्य की पुलिस से कई बार संपर्क किया है। उन्हें अपराधियों की जानकारी भी दी जा चुकी है लेकिन गिरफ्तारी के लिए सहयोग नहीं मिलने से सफलता नहीं मिली है। खास बात है कि फरार आरोपियों में नक्सली भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार को 46 नक्सलियों की सूची दी गई है। इन पर बालाघाट पुलिस ने ईनाम भी घोषित किया है। सभी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और मप्र में नक्सली घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फरार अपराधियों के आंकड़े इस बात का संकेत हैं कि मप्र का अपने पड़ोसी राज्यों से समन्वय नहीं है। राज्यों में कानून व्यवस्था के साथ दूसरे राज्यों में अपराध और बदमाशों पर कार्रवाई के लिए हर साल डीजी स्तर के अधिकारियों की कॉर्डिनेशन बैठक होती है। इस बैठक में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों के सुझाव लिए जाते हैं।

1,35,046 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 19.35 लाख लीटर देशी-विदेशी शराब जब्त की गई। 29 रासुका और 345 जिलाबदर की कार्रवाई की गई। 1727 वाहन जब्त किए गए और 268 वाहन राजसात किए गए। 14 हजार से अधिक अवैध हथियार बरामद कर 3100 से अधिक फायर आर्म्स तथा 48 फायर आर्म्स की फैक्ट्रियां पकड़ी गईं। अब तक डायल 100 से 1 करोड़ 63 लाख जरूरतमंदों को पुलिस सहायता प्रदान की गई। इसमें 15.79 लाख महिलाओं को शामिल किया गया। सड़क दुघर्टना में घायल 10.17 लाख नागरिकों को तत्काल सहायता पहुंचाई। जारी आंकड़ों के मुताबिक 22,987 लापता बच्चों को उनके परिजनों से मिलवाया गया। 2,23,195 महिला एवं पुरुषों को आत्महत्या से रोका गया। चिन्हित अपराधों में 1185 प्रकरणों का कोर्ट ने निराकरण किया। 882 मामलों में सजा हुई। कुल 565 केस में 1021 अपराधियों को उम्रकैद, 6 प्रकरणों में 10 आरोपियों को फांसी की सजा हुई, जबकि दोष सिद्ध करने का प्रतिशत 70 रहा।

मप्र में लगातार राष्ट्रविरोधी ताकतों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। वर्ष 2023 में तीन बड़ी कार्यवाही की गई हैं। इन कार्यवाहियों में हॉकफोर्स ने 2 महिला नक्सलियों सहित 4 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी किया है। इन सभी नक्सलियों पर 14-14 लाख रुपए का ईनाम घोषित था। वर्ष 2023 के अप्रैल में हुई कदला मुठभेड़ में महिला नक्सली सरिता तथा सुनीता, कुंदुल-कोद्दापार जंगल क्षेत्र में सितंबर में हुई मुठभेड़ में नक्सली कमलू को भी धराशायी किया जा चुका है। वहीं 14 दिसंबर को हॉकफोर्स ने मड़काम हिड़मा उर्फ चैतु हिड़मा को भी धराशायी कर दिया। आमजन का सहयोग पुलिस को प्राप्त हो सके व नक्सल प्रभावित जिलों के प्रभावित विकासखंडों के स्थानीय निवासरत युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए विशेष सहयोगी दस्ता का गठन किया गया है। अगस्त 2023 में प्रतिबंधित संगठन सीपीआई की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का सदस्य फरार नक्सली अशोक रेड्डी जबलपुर से गिरफ्तार किया गया। अशोक रेड्डी के विरुद्ध तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 60 से

अधिक गंभीर अपराध पंजीबद्ध, 82 लाख रुपए का ईनाम था। मप्र पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों एचयूटी, जेएमबी और पीएफआई पर प्रभावी कार्यवाही की। मई 2023 में एटीएस, मप्र द्वारा योजनाबद्ध तरीके से रेड करके कट्टरपंथी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर, तहरीक-ए-खिलाफ के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से भोपाल के 10, छिंदवाड़ा का 1 तथा हैदराबाद के 5 सदस्य शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों से भारी मात्रा में जिहादी साहित्य, तकनीकी उपकरण, एयरगन, छर्रे, कॉम्बेट नाइफ, आयरन रॉड, चाकू, गुप्तियां, तलवार बरामद किए गए। इंदौर और भोपाल में कमिश्नर प्रणाली लागू हुए करीब 27 महीने हो गए हैं और अब अपराधों की स्थिति की समीक्षा हो रही है। लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से अपराधों में कमी आई है। इंदौर-भोपाल में काम की समीक्षा के साथ जबलपुर व ग्वालियर में भी कमिश्नर प्रणाली लागू करने पर सरकार विचार कर रही है। पुलिस मुख्यालय में इसकी तैयारी भी चल रही है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणाचारी मिश्र के मुताबिक, पिछले साल के मुकाबले इस साल मुख्य अपराधों में कमी आई है। संपत्ति संबंधी अपराध, चेन स्नेचिंग, लूट में कमी है। एक लाख से कम की चोरियां भी कम हुई हैं, महिला संबंधी अपराधों में भी कमी आई है।

एक तरफ प्रदेश में अपराधों में कमी दर्ज की गई है। वहीं यहां अपराध करने के बाद 8 हजार से अधिक अपराधी फरार हैं। ये अपराधी गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान और उप्र के हैं। हालांकि चुनाव को देखते हुए पुलिस सतर्क हुई है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने उपरोक्त राज्यों की पुलिस को इन अपराधियों की रिपोर्ट भेजी है। इन अपराधियों के अलावा इस समय मप्र में 39,893 अपराधी बेल पर जेल से बाहर हैं। इनमें से कई अपराधियों की बेल निरस्त हो चुकी है, लेकिन 52 जिलों की पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है। कहा जाता है कि या तो ये अपराधी राज्य में ही कहीं छिपकर बैठे हुए हैं या फिर राज्य से फरार हो गए हैं। वहीं पैरोल पर जेल से निकले 143 कैदी भी फरार हैं। दरअसल, चुनाव का समय आते ही पुलिस ने अपराधियों की धर-पकड़ तेज कर दी है। लेकिन प्रदेश में अपराध करने के बाद 8401 बदमाश अपने राज्यों में शरण ले चुके हैं। मप्र पुलिस को लंबे समय से दूसरे राज्यों में बैठे अपराधियों की तलाश है। हालांकि गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशिश कर चुकी है लेकिन हाथ में नहीं आए थे। ऐसे अपराधियों की पीएचक्यू ने सूची तैयार की है। जिन्हें मप्र पुलिस ने फरार या फिर नियमित वारंटी घोषित कर दिया है। सभी आरोपी मप्र से सटे हुए राज्यों के हैं। जिन्होंने मप्र में दाखिल होकर अपराध किया और अब पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग निकले।

● **प्रवीण सक्सेना**

जमानत पर घूम रहे 39 हजार से ज्यादा अपराधी

वहीं प्रदेश में 39 हजार से ज्यादा खूंखार अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। मप्र के स्पेशल डीजी ने स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को भेजे आंकड़े में इसकी जानकारी दी है। इस आंकड़े को देख लोग मप्र पुलिस पर तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं। पिछले दिनों डीजी जीपी सिंह ने पुलिस की कार्यप्रणाली की रिपोर्ट जारी कर दी थी। सिंह ने मप्र के 39 हजार से अधिक बेल जंपर और स्थाई वारंटियों की सूची जारी कर दी। इस सूची के बाद पुलिस अफसरों की कार्रवाई पर सवाल उठे। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ा तो सभी जिलों में वारंटियों की धरपकड़ तेज हो गई। नाइट गश्त और कांबिंग अभियान चलाते हुए अपराधियों को पकड़ा गया। साथ ही पुलिस के सामने चुनौती एक और है। वहीं मप्र के पूर्व डीजीपी अरुण गुटरू का कहना है कि ये तो पुलिस की नाकामयाबी है। ये प्रदेश के लिए बड़ा खतरा है। ये आतंकी गतिविधि से लेकर हर तरह का अपराध कर सकते हैं। हो सकता है पुलिस ने इस मामले में भ्रष्टाचार किया हो। ज्यादा दोस्ताना संबंध में आरोपियों को नहीं पकड़ रहे हों। कह देते हों कि आरोपी नहीं मिला। वहीं इसके अलावा पुलिस बल भी कम है। वीआईपी सुरक्षा से लेकर कोर्ट के काम भी पुलिस कर रही है।

सफेद हाथी बना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट

भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट सरकार के लिए सफेद हाथी बन चुका है। भोपाल के लोग मेट्रो की सवारी कब से कर सकेंगे यह अभी तय नहीं हो पाया है। उधर स्थिति यह है कि प्रोजेक्ट का खर्च बढ़ता ही जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि मेट्रो के लिए यात्री कहां से मिलेंगे इसका अता-पता किसी को नहीं है। आलम यह है कि शहर में मेट्रो ट्रेन के यात्री तलाशने के लिए पिछले 10 साल में सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। मेट्रो कंपनी एक बार फिर दिल्ली की फर्म से यही सर्वे दोबारा करवा रही है। इस बार 5 करोड़ का भुगतान होना है।

शहर का मेट्रो प्रोजेक्ट 2018 में मंजूर हुआ था, और इसको 2022 में पूरा होना था। लेकिन अब अफसरों ने घोषणा की है कि यह मार्च 2027 तक पूरा होगा। यह 5 साल की देरी लागत में वृद्धि करेगी, जिससे कंपनी को नुकसान होगा और लोगों को सुविधा में विलम्ब होगा। जब मेट्रो की दोनों लाइनें करोंद से एम्स और भदभदा से रत्नागिरि तक पूरी तरह से ऑपरेटिव होंगी, तब ही लोगों को वह राइडरशिप मिलेगी। आम आदमी को अंतिम माइल कनेक्टिविटी देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। अफसरों ने लागत कम करने के लिए उपयुक्त जमीनों का उपयोग करने का सुझाव दिया है, जहां पार्किंग के लिए जमीन उपलब्ध है, वहां कमर्शियल स्पेस का विकास भी किया जा सकता है।

भोपाल मेट्रो ट्रेन के लिए यात्री कहां से आएंगे इसके लिए एक और सर्वे कराया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में किए गए सर्वे में प्राइवेट कंसल्टेंट्स ने पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए सरकार को लोक लुभावना सपने दिखाए हैं। वर्ष 2014 में मेट्रो रेल की डीपीआर तैयार होने के बाद मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों की उपलब्धता के लिए सर्वे करवाया। बदले में सवा करोड़ से ज्यादा का भुगतान हुआ। मेट्रो कंपनी एक बार फिर दिल्ली की फर्म से यही सर्वे दोबारा करवा रही है। इस बार 5 करोड़ का भुगतान होना है। यही हाल लो फ्लोर बसों का है। बीसीएलएल भी प्रसन्ना पर्पल, रैडिकल इंफ्रा के जरिए यात्रियों की तलाश के लिए भारी भरकम भुगतान कर सर्वे करवा चुका है। सरकार ने अब तक विभिन्न कंपनियों से मेट्रो प्रोजेक्ट का सर्वे करवाया है। वर्ष 2012 में पहली बार प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी। वर्ष 2013 में रोहित गुप्ता एसोसिएट और जर्मन की एलआरटीसी कंपनी ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना शुरू की। वर्ष 2014 में मेट्रो की डीपीआर रोहित गुप्ता एसोसिएट ने रिपोर्ट तैयार की। कंपनी के 32 करोड़ बकाया हैं। वर्ष 2016 में इंदौर की मेहता एसोसिएट को ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी भविष्य के यात्रियों की तलाश के लिए सवा करोड़ से अधिक का भुगतान हुआ। केंद्र सरकार शहरी आवासीय मंत्रालय के अधीन काम करने वाली फर्म अर्बन मास ट्रांजिट कंपनी को इस बार नए सिरे से मेट्रो के यात्री तलाश करने का काम दिया गया। प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी इसके बदले 5 करोड़ का भुगतान करेगी। भुगतान में प्रदेश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मजबूत करने के लिए कंपनी अपने कंसल्टेंट की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। एमडी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सीबी चक्रवर्ती का कहना है कि मेट्रो ट्रेन एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हर भाग के लिए एजेंसी तय है। हमारी भी पूरी टीम है और लगातार हम मॉनिटरिंग करके काम को पूरा करते हैं। यही हाल लो फ्लोर बस का भी रहा। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत वर्ष 2013 में प्रसन्ना पर्पल कंपनी को-ऑपरेशन का काम दिया। कंपनी ने यात्री सर्वे कर बसों का संचालन किया। इसके बदले सरकारी खाते से बस खरीदकर कंपनी ने स्वयं चलाई एवं मुनाफा कमाया। वर्ष 2018 में नए रूट एवं यात्री तलाश के लिए भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने भोपाल की ही रैडिकल इंफ्रा नामक कंपनी को सर्वे का काम दिया। सवा दो करोड़ से अधिक का भुगतान भी किया।

भोपाल के मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत अब करीब 9500 करोड़ हो जाएगी। काउंसिल ऑफ कंसल्टिंग सिविल इंजीनियर्स के वाइस प्रेसिडेंट, स्ट्रक्चर इंजीनियर डॉ. शैलेंद्र बागरे ने यह जानकारी दी। इस प्रोजेक्ट का पहला रूट 14.19 किमी का होगा, जबकि दूसरा रूट 12.88 किमी का होगा। वर्तमान में यह प्रोजेक्ट 6941.40 करोड़ रुपए की लागत में है। केंद्र ने भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी के साथ 14,442 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। भोपाल में मेट्रो ट्रेन को शहर के हर हिस्से तक पहुंचने का काम जोरों से चल रहा है। मेट्रो ट्रेन कॉरपोरेशन के एमडी सीबी चक्रवर्ती ने बताया कि मेट्रो की नई लाइनों के निर्माण का काम किया जा रहा है। सीहोर तक मेट्रो की लाइन बिछाई जाएगी। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट को अब 8 लाइन में बनाया जाएगा। पहले जहां मेट्रो लाइन 98.78 किलोमीटर लंबी बनने वाली थी, उसे बढ़ाकर 105 किलोमीटर बना दिया गया है। साथ ही इसमें 2 नई लाइन को भी जोड़ा गया है। मेट्रो की कई लाइनों पर काम चल रहा है। हबीबगंज नाका में मेट्रो लाइन पर काम चलने की वजह से रास्ता भी डायवर्ट कर दिया गया है।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

प्रॉयोरिटी कॉरिडोर का निरीक्षण

दिल्ली के अफसरों ने गत दिनों भोपाल मेट्रो के 4 किमी लंबे प्रॉयोरिटी कॉरिडोर का रूट देखा। वे मेट्रो में भी बैठे। साथ ही एम्स, अलकापुरी और डीआरएम स्टेशन पहुंचकर अधूरे काम को जल्दी करने को कहा। ताकि, मेट्रो का कमर्शियल रन जल्द हो सके। निरीक्षण के दौरान मेट्रो की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रतिघंटा रही। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई, मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सिबी चक्रवती समेत अन्य अफसरों के साथ मेट्रो से जुड़े कामों को देखा। उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट के लेट होने की वजह भी जानी। सचिव जैन ने सुभाषनगर से आरकेएमपी तक कुल 5 स्टेशनों का निरीक्षण भी किया। वे मेट्रो में बैठे और रूट से जुड़े हर काम को बारीकी से देखा। इसके अलावा उन्होंने एम्स, अलकापुरी और डीआरएम ऑफिस मेट्रो स्टेशनों का काम भी जल्दी पूरा करने को कहा। सचिव जैन ने मेट्रो के अफसरों के साथ मीटिंग भी की। इस दौरान प्रजेंटेशन भी दिया गया।

आचमन लायक बनेगा कान्ह का पानी

औद्योगिक क्षेत्रों में दो नए ईटीपी बनाने की कवायद

इंदौर में भी प्रशासन व नगर निगम ने कान्ह नदी के माध्यम से शिप्रा में मिलने वाले पानी को शुद्ध करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। नगर निगम कान्ह में शहर के सीवरेज के आउट फॉल बंद करने के साथ औद्योगिक क्षेत्र का पानी भी साफ करके नदी में छोड़ने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए औद्योगिक क्षेत्रों में दो इफ्यूलेंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) बनाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। कान्ह और शिप्रा शुद्धिकरण के लिए मुख्यमंत्री की प्राथमिकता के बाद अब स्थानीय अमला भी सक्रिय हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन और नगरीय क्षेत्र में निगम योजना पर अमल कर रहा है। अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन ने इस संबंध में पालदा और कुमेड़ी में दो स्थान पर ईटीपी प्लांट के लिए उद्योगपतियों के साथ विस्तार से चर्चा की है। सबसे पहले इनकी क्षमता तय करने के लिए उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी का आंकलन किया जा रहा है।

महाकाल की नगरी में आयोजित होने वाले आगामी सिंहस्थ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। आगामी सिंहस्थ में शिप्रा में गंदा पानी प्रवाहित नहीं हो, इसके लिए सरकार ने काम शुरू कर दिया है। सिंहस्थ में आने वाले में संत और श्रद्धालु शिप्रा में आचमन कर सकें, इसके लिए कान्ह नदी शुद्धिकरण के लिए नए सिरे से 615 करोड़ की योजना तैयार की गई है। कान्ह के लिए नमामि गंगे में कुल 511 करोड़ मिलेंगे और अमृत-2 में भी फंड मिलने की उम्मीद है। आचार संहिता के बाद इस पर काम शुरू होने की उम्मीद है। शिप्रा शुद्धिकरण के लिए सरकार ने राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी के सदस्य विगत दिवस इंदौर में थे। चूंकि इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदी का पानी उसमें मिलता है, इसलिए निगमायुक्त शिवम वर्मा ने नमामि गंगे फेज-1 और अमृत प्रोजेक्ट फेज-2 के तहत शहर में सीवर नेटवर्क और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने को लेकर स्मार्ट सिटी ऑफिस में समीक्षा बैठक ली। निगमायुक्त ने कहा कि वर्ष 2040 में शहर की जनसंख्या को देखते हुए शहर के सीधर नेटवर्क की प्लानिंग की जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उद्योगों का वेस्ट नदी के पानी में सीधे छोड़ने की शिकायतें मिली हैं, जिन पर टीम बनाकर कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि कान्ह और सरस्वती नदी के शुद्धिकरण पर 15 वर्षों में 1152 करोड़ खर्च हो चुके हैं। देश की पहली वाटर प्लस सिटी का तमगा हासिल करने के लिए दो वर्ष पहले 200 करोड़ खर्च कर नाला टैपिंग की गई थी। हालांकि वह काम नहीं आई। वर्ष 2028 में सिंहस्थ है इसलिए नदी को साफ करने की कोशिश फिर शुरू हो गई है। इस पर निगम 615 करोड़ खर्च करने की तैयारी कर रहा है। अमृत योजना के पहले चरण में भी दो एसटीपी बनाए गए थे। कुल 10 एसटीपी से 412 एमएलडी पानी साफ कर रहे हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी इंदौर को 511 करोड़ मिले हैं। इससे 240 करोड़ खर्च कर 195 एमएलडी के तीन एसटीपी बनाए जाएंगे। अमृत योजना के दूसरे फेज में भी दो एसटीपी बनाने की योजना है। निगम को आउट फॉल्स रोकने के लिए 11 एसटीपी चाहिए।

बड़ी बात यह है कि अधिकारी अब तक यह भी पता नहीं लगा पा रहे थे कि शहर से रोज कितना सीवर निकल रहा है? उनसे सवाल किया तो उनका कहना है कि अब तक प्लानिंग मैच नहीं कर पा रहे थे। पानी की आपूर्ति के हिसाब से सीवर की मात्रा का अनुमान लगाया है। अभी 412 एमएलडी सीवर ट्रीटमेंट करने की क्षमता है। इसमें से 90 एमएलडी के दो एसटीपी का सिस्टम पुराना हो गया है। आजाद नगर के एसटीपी में 15 एमएलडी कम सीवर आता है। लाइनों में सीवर की मात्रा बढ़ने लगी जो एसटीपी की क्षमता से ज्यादा है। 245 एमएलडी का एसटीपी 100 फीसदी काम कर रहा है। 77 एमएलडी के एसटीपी में 60 एमएलडी सीवर ही आ रहा है।

इंदौर में प्रवाहित होकर उज्जैन से पहले मोक्षदायिनी शिप्रा में मिलने वाली कान्ह और सरस्वती नदियों को शुद्ध करने की कवायद चार दशक से ज्यादा पुरानी है। दोनों नदियों के शुद्धिकरण पर अलग-अलग हिस्सों में एक हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन नदियां पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाईं। हालांकि यह जरूर है कि पहले के मुकाबले नदियों में गंदगी कम हुई है, लेकिन प्रयास अब भी अधूरे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हर बार नदियों के शुद्धिकरण का मुद्दा जोर-शोर से उछलता है। राजनेता और पार्टियां वादे भी करती हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। इस बार भी लोकसभा चुनाव से पहले सिर्फ इंदौर ही नहीं उज्जैन की जनता भी जानना चाहती है कि आखिर ये नदियां कब तक शुद्ध हो जाएंगी। कब हम कान्ह और सरस्वती नदियों को प्रदूषण मुक्त कर इस पानी को शुद्ध करेंगे और कब इन नदियों का शुद्ध पानी शिप्रा में मिलेगा या फिर ऐसी व्यवस्था होगी कि इन दोनों नदियों का पानी शिप्रा में मिलना ही बंद होगा। इंदौर की कान्ह-सरस्वती नदियां उज्जैन की शिप्रा नदी में जाकर मिलती हैं और शिप्रा चंबल में समाती है। चंबल यमुना नदी और यमुना आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है। यही वजह है कि कान्ह और सरस्वती नदियों को नमामि गंगे मिशन में शामिल किया गया है। इंदौर से उज्जैन के रास्ते में इन दोनों नदियों में कई जगह उद्योगों की गंदगी मिलती है। वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का बड़ा धार्मिक आयोजन होना है। इसमें विश्वभर से करोड़ों श्रद्धालु शामिल होंगे और शिप्रा में स्नान करेंगे। यही वजह है कि वर्ष 2028 से पहले कान्ह और सरस्वती को पूरी तरह से शुद्ध करने की चुनौती है। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे मिशन के तहत कान्ह और सरस्वती नदियों के शुद्धिकरण के लिए राज्य को 511 करोड़ रुपए की राशि आवंटित भी कर दी है। कान्ह और सरस्वती नदियों के शुद्धिकरण के प्रयास अस्सी के दशक में शुरू हुए थे। कान्ह नदी के दोनों तरफ पाइपलाइन बिछाई गई थी ताकि सीवेज को नदी में मिलने से रोका जा सके। इसके अलावा नदियों के किनारों को संवारने के लिए भी योजना बनाई गई थी। उसी समय वर्तमान शिवाजी मार्केट से नीचे नदी किनारे दुकानें भी बनाई गई थीं। नदी में नाव चलाने की सिर्फ योजना नहीं बनी बल्कि नदी में नाव चली भी थी। हालांकि वर्षाकाल में आसपास की बस्तियों में पानी भराने के बाद नदियों के शुद्धिकरण की पूरी योजना ही ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद लंबे समय तक नदियों के शुद्धिकरण को लेकर कोई काम नहीं हुआ।

● **जितेंद्र तिवारी**

सीएम इंफ्रा के काम रुके

म प्र में मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास (सीएम इंफ्रा) योजना के तहत होने वाले विकास कार्य यानी सड़क, शहरी यातायात, नगरों को सुंदर बनाने, सामाजिक अधोसंरचना विकसित करने संबंधी नवीन योजनाओं के काम रुके हुए हैं। इसकी मुख्य वजह है कि वित्त विभाग सीएम इंफ्रा के बजट पर कुंडली मारकर बैठा है। नगरीय विकास विभाग के अफसरों की बार-बार की मांग के बावजूद भी बजट जारी नहीं किया जा रहा है। इस संदर्भ में गत दिवस नगरीय विकास विभाग के आला अफसरों ने मुख्य सचिव वीरा राणा से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए सरकार के दिशा निर्देश पर वित्त विभाग ने विभागों के खर्च पर पहरा बैठा दिया है। वित्त विभाग का अनुमान है कि लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी। इसे देखते हुए विभाग ने दिसंबर में वित्तीय प्रबंधन के लिए विभागों के बिना अनुमति विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब 31 विभागों की 123 योजनाओं को इससे मुक्त कर दिया गया है। यानी विभाग इन योजनाओं में बजट प्रविधान के अनुसार राशि व्यय कर सकते हैं। हालांकि, 25 करोड़ रुपए से अधिक का कोई भी आहरण बिना अनुमति के नहीं होगा। नगरीय विकास विभाग के आला अफसरों ने मुख्य सचिव वीरा राणा को बताया कि सीएम इंफ्रा फेज 4 और कायाकल्प 2 के लिए बजट में प्रावधान होने के बाद भी इनकी राशि जारी नहीं की गई है। चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि में भी हर वर्ष दस फीसदी की बढ़ोतरी होना चाहिए। यह भी नहीं की जा रही है। इस पर सीएस ने कहा कि नगरीय निकाय ग्रोथ के इंजन हैं। उनका पेमेंट होना चाहिए।

गौरतलब है कि सीएम इंफ्रा योजना में सड़क, शहरी यातायात, नगरों को सुंदर बनाने, सामाजिक अधोसंरचना विकसित करने संबंधी नवीन योजनाएं ली जाती हैं। राज्य सरकार योजना की लागत का 30 प्रतिशत अनुदान देगी और 70 प्रतिशत राशि निकायों को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी। ऋण राशि और ब्याज की अदायगी 15 से 20 वर्ष की अवधि में शासन और शेष 25 प्रतिशत राशि निकाय द्वारा की जाएगी। सीएम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजना अब चार के बजाय दो साल में पूरी करना होगी। नगरीय प्रशासन ने इसकी अवधि कम कर दी है। इस योजना में पूरे प्रदेश में 500 करोड़ रुपए के काम होने हैं। नगरीय निकायों की सड़कों, सुंदरता, ट्रांसपोर्ट आदि में सुधार के लिए सीएम इंफ्रा के तहत काम होता है। कांग्रेस सरकार ने सीएम इंफ्रा के तीसरे चरण के लिए चार साल की अवधि तय की थी। इसे वर्ष 2020-21 में शुरू कर मार्च 2024 में खत्म करना था। अभी तक इसके काम शुरू नहीं हुए हैं। योजना में नगर निगम से लेकर नगर परिषद तक काम होंगे और इसके लिए उनकी जनसंख्या के आधार पर राशि आवंटित होगी। लेकिन सारी कवायद धरी की धरी रह गई है।

नगरीय विकास विभाग के कामकाज और योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि वे इस सिलसिले में वित्त विभाग के अफसरों के साथ अलग से बैठक करेंगी। अफसरों ने उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत 1 व 2 सहित राज्य की योजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया। मौजूदा प्रगति और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। बैठक में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग संचालनालय में खाली पदों पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि ज्यादातर पर भर्ती या नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

जानकारी के मुताबिक सीएम इंफ्रा फेज 4, मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना, कायाकल्प और मास्टर प्लान की सड़कों के लिए कुल 1200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इसमें सीएम इंफ्रा के लिए 500 करोड़, नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना का 200 करोड़, कायाकल्प का 400 करोड़ और मास्टर प्लान रोड का 100 करोड़ शामिल है। बजट में आवंटित राशि में से ज्यादातर वित्त विभाग ने अटका रखी है। यह समस्या विभाग के अफसर कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव व नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के समक्ष भी रख चुके हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री ने भी वित्त विभाग के अधिकारियों को योजनाओं की राशि जारी करने के निर्देश दिए थे। वहीं प्रदेश में 413 नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति के तौर पर हर साल 300 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रावधान किया जाता है। इस राशि में सालाना दस प्रतिशत बढ़ोतरी का नियम भी है। चुंगी क्षतिपूर्ति में इजाफे की बजाय इसमें से लगातार कटौती की जा रही है। निकायों का बकाया बिजली का बिल चुकाने के लिए वित्त विभाग चुंगी में से राशि काट रहा है और इसे विद्युत कंपनियों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है। हर महीने निकायों को मिलने वाली राशि में से 28 से 40 करोड़ रुपए तक की कटौती की जा रही है। इससे अधिकांश निकायों के सामने वेतन-भत्ते बांटने का संकट खड़ा हो गया है।

● **लोकेश शर्मा**

खर्च का बैरियर हटा, लेकिन सीएम इंफ्रा को फायदा नहीं

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 120 योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाले खर्च पर लगी रोक हटा दी है। ये योजनाएं 31 विभागों की हैं, जिनमें अब वित्त विभाग की तय नीति के हिसाब से राशि खर्च की जा सकेगी। लेकिन इसका फायदा सीएम इंफ्रा को नहीं मिला है। चुनाव के पहले सरकार का फोकस अटल ज्योति योजना में 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दिए जाने, गौशालाओं के संचालन पर खर्च, गांव की बेटी और सरकारी कॉलेजों के भवन के निर्माण पर खर्च होने वाली राशि पर है। इसके साथ प्रदेश की 26 हवाई पट्टियों के विस्तार का काम शुरू हो सकेगा। सरकार के 14 बड़े विभाग इस महीने में 7323 करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे। 31 मार्च तक 30 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। इसमें बड़ी राशि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 2400 करोड़ रुपए दी गई है। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल खासतौर पर बंद पड़ीं नल-जल योजनाओं के चालू करने, लोगों के घर पर नलों से पानी दिए जाने पर खर्च होंगे। यानी गर्मी में कहीं भी पेयजल की दिक्कत न हो, जिसका असर चुनाव पर पड़े। उज्जैन में होने वाले व्यापारिक मेले में उद्योगों को प्रोत्साहन देने और इस आयोजन पर 92 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

'अमानक' में फंसा किसानों का 115 करोड़

लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मप्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विपणन वर्ष 2024-25 के लिए गेहूं की खरीदी तेजी से चल रही है। इस वर्ष लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। 15 अप्रैल तक लगभग 21 लाख 66 हजार टन से अधिक गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में 2 लाख 63 हजार से अधिक किसानों को लगभग 3355 करोड़ रुपए का भुगतान हो गया है। वहीं सहकारी समितियों के जरिए किसानों से खरीदे गए 4.80 लाख क्विंटल गेहूं की क्वालिटी खराब बताकर वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने हजारों किसानों की कमाई पर पानी फेर दिया है। अमानक गेहूं के चक्कर में किसानों के 115 करोड़ रुपए फंस गए हैं। गौरतलब है कि गेहूं खरीदी के लिए नोडल विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम है जिसने प्रदेश में लगभग 3642 खरीदी केंद्र बनाए हैं। ज्ञातव्य है प्रदेश में बेमौसम बरसात तथा ओलावृष्टि के कारण कुछ क्षेत्रों में गेहूं फसल प्रभावित हुई है, दाना भी चमकविहीन हो गया है। सरकार के मौखिक निर्देश पर नागरिक आपूर्ति निगम (नान) ने किसानों से हर तरह के गेहूं को खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन नान के गेहूं को डब्ल्यूएलसी (वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन) ने फेल कर दिया है।

प्रदेश में सहकारी समितियों के जरिए किसानों से खरीदे गए 4.80 लाख क्विंटल गेहूं की क्वालिटी पर दो संस्थानों में फंसे पेच ने हजारों किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। डब्ल्यूएलसी का दावा है कि उक्त गेहूं गुणवत्ता के निर्धारित मापदंड पर खरा नहीं है। यदि इसे लिया गया तो भविष्य में एफसीआई इसे फेल कर सकता है या फिर राशन की दुकानों से होते हुए गरीबों की थाली तक पहुंचा तो आफत आ सकती है। कहा जा रहा है कि किसानों ने खराब गेहूं नहीं बेचा है बल्कि समितियों में खराब हुए हैं। दरअसल समितियों के पास संसाधन कम थे। बारिश से गेहूं गीला हो गया। गीले गेहूं को सुखाने बड़े और कवर्ड मैदान की जरूरत थी। बार-बार मौसम खराब हो रहा था इसलिए समितियों ने पीछा छुड़ाते हुए परिवहन करा दिया।

वहीं किसान संगठनों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनका कहना है कि किसानों ने यदि खराब गेहूं दिया होता तो सहकारी समितियां उसे पहले ही लौटा देतीं। किसानों ने जो गेहूं बेचा है, उसे गोदामों में जमा नहीं किया जा रहा है। समर्थन मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत 119 करोड़ 20 लाख रुपए करीब है। डब्ल्यूएलसी भोपाल से रिटायर्ड मैनेजर अनिल बाजपेयी के मुताबिक समितियां अब इसकी स्वयं के खर्च पर ग्रेडिंग कराते हुए उसे दोबारा भेजेंगी। यदि फिर भी वह एफएक्यू (फेयर एवरेज क्वालिटी) मापदंड में उचित नहीं पाया जाता तो किसानों को लौटाया जाएगा। इस तरह जब तक उक्त गेहूं का निराकरण नहीं हो जाता, किसानों को भुगतान भी नहीं होगा। प्रदेश में 20 मार्च से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू हुई है। अब तक 2 लाख 85 हजार किसान 23 लाख मीट्रिक टन गेहूं बेच चुके हैं। केंद्रों में समितियों द्वारा गेहूं की गुणवत्ता जांच की जाती है। समितियों ने जिस गेहूं को अच्छा बताकर खरीदा उसे डब्ल्यूएलसी ने घटिया बताकर गोदामों में लेने से ही मना कर दिया। किसान नेता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि खरीदी केंद्रों में संसाधनों की कमी थी। विभागों की लापरवाही का खमियाजा किसान बिलकुल नहीं भुगतेंगे। गेहूं लौटाया गया तो किसान आंदोलन होगा। आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति रवींद्र सिंह का कहना है कि रिजेक्टेड गेहूं वापस किए जा रहे हैं। इसकी ग्रेडिंग समितियों से कराएंगे। किसानों का नुकसान न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। जानकारी के अनुसार, उज्जैन में 5203 मीट्रिक टन, शाजापुर में 8572 मीट्रिक टन, देवास में 3150 मीट्रिक टन, इंदौर में 1923 मीट्रिक टन, विदिशा में 2587 मीट्रिक टन, भोपाल में 3440 मीट्रिक टन, सीहोर में 9002 मीट्रिक टन, रायसेन में 6480 मीट्रिक टन, राजगढ़ में 1153 मीट्रिक टन, नर्मदापुरम में 1462 मीट्रिक टन और सागर में 3260 मीट्रिक टन गेहूं रिजेक्ट किया गया है।

देश के बड़े उत्पादक राज्यों में शामिल मप्र में गेहूं का रकबा घट रहा है तो अब सरकारी खरीदी में भी पिछड़ रहा है। पिछले 3 साल में गेहूं की सरकारी खरीद लगातार घटी है। इस साल भी मप्र 100 लाख मीट्रिक टन के टारगेट से आधे पर ही रुक सकता है। 20 मार्च से शुरू हुई सरकारी खरीद के बीच अब तक सिर्फ 25 लाख मीट्रिक टन गेहूं ही सरकारी गोदामों में पहुंचा है। केंद्र सरकार ने इस साल गेहूं खरीद का टारगेट 23 प्रतिशत बढ़ाते हुए लगभग 320 से 330 एलएमटी तय किया है। हालांकि राज्यों द्वारा बोनस नहीं देने या नाममात्र का बोनस देने की वजह से सरकारी मूल्य मंडियों में चल रही कीमतों से पीछे हैं। मप्र में 20 मार्च को 2400 रुपए में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होने के साथ ही प्रदेश की मंडियों में भाव 2200 से 2600 रुपए है। भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राहुल धूत ने कहा कि 2700 एमएसपी होने पर सरकारी खरीद बढ़िया होती।

● **विकास दुबे**

24 हजार करोड़ का गेहूं खरीदेगी सरकार

मप्र में दूसरे अग्रिम उत्पादन अनुमान के मुताबिक वर्ष 2023-24 में लगभग 329 लाख टन से अधिक गेहूं उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से विपणन वर्ष 2024-25 में लगभग 100 लाख टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने मप्र को दिया है। जबकि देश में कुल 320 लाख टन गेहूं की खरीदी एमएसपी पर की जाएगी। प्रदेश में 15 लाख से अधिक किसानों ने गेहूं विक्रय के लिए पंजीयन कराया है। मप्र सांख्यिकी विभाग के अनुसार वर्ष 2022-23 में 5 लाख 90 हजार किसानों से 46 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था और किसानों को 9271 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ था। इसी प्रकार वर्ष 2021-22 में 128.5 लाख मीट्रिक टन खरीदी के बदले 25 हजार 301 करोड़ का भुगतान तथा वर्ष 2020-21 में 129.42 लाख मीट्रिक टन के विरुद्ध 24 हजार 806 करोड़ का भुगतान किया गया था। सरकार की ओर से किसानों को गेहूं की खरीद पर बोनस का भुगतान करने के लिए प्रदेश सरकार पर 3850 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। विपणन सीजन 2023-24 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 रुपए प्रति क्विंटल था जिसे केंद्र सरकार ने इस रबी विपणन सीजन 2024-25 के लिए 2275 रुपए कर दिया है।

घड़ियाल सेंचुरी दबंगों की जद में

दबंग और भू-माफियाओं ने अब चंबल नदी किनारे के बीहड़ों तक पांव पसारना शुरू कर दिया है। जिन बीहड़ों को सरकार समतल नहीं कर पा रही है, उन्हें दबंग समतल कर खेत बना रहे हैं और खेती कर रहे हैं। मुरैना के पोरसा से लेकर श्योपुर के ढोढर, सामरसा तक बीहड़ों में जमकर अतिक्रमण हो रहा है, लेकिन इस अतिक्रमण को रोकने वन विभाग या घड़ियाल सेंचुरी प्रबंधन कोई कदम नहीं उठा रहा है। गौरतलब है, कि चंबल घड़ियाल सेंचुरी का दायरा चंबल नदी से दूर तक के बीहड़ आते हैं। इन बीहड़ों में पर्यावरण विभाग ने अटल प्रगति पथ (एक्सप्रेस-वे) का निर्माण रुकवा दिया था। इन्हीं बीहड़ों में दबंग और भू माफिया पांव पसारने लगे हैं। चंबल घड़ियाल सेंचुरी की सीमा में आने वाले बीहड़ों को जोतकर उनमें खेत बनाए जा रहे हैं।

अंबाह के बीलपुर, कुथियाना, लखुआ, किसरौली, मुरैना के नदुआपुरा, भानपुर, बरवासिन, केंथरी, कैमारा, जौरा-बागचीन के सावदा, भराना, देवगढ़, खांडोली, पंचमपुरा, सबलढ़ में अटार, रहू गांव, बटेश्वरा आदि गांवों में बीहड़ समतल करके खेत हो गए हैं, जिनमें सरसों, गेहूं आदि की फसलें हो रही हैं। हर साल यह अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। उधर, श्योपुर जिले में वीरपुर से लेकर ढोढर, रघुनाथपुर, सामरसा तक बीहड़ों में अतिक्रमण हो गया है। गौरतलब है कि मप्र सरकार ने साल 2016 में 1.62 लाख हेक्टेयर बीहड़ों को समतल कर खेती लायक जमीन बनाने के लिए बीहड़ भूमि उपचार योजना बनाई, जिसका बजट 1100 से बढ़कर 1600 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन बीहड़ समतल नहीं हो सके। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने इन बीहड़ों में चंबल एक्सप्रेस-वे के निर्माण को यह कहते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया, कि इससे चंबल नदी व उसके जलीय जीवों को खतरा है। लेकिन बीहड़ों में बढ़ते बेतरतीव अतिक्रमण पर न तो पर्यावरण मंत्रालय का ध्यान है, न ही स्थानीय प्रशासन का। चंबल नदी के दूसरे किनारे पर पड़ोसी राजस्थान का धौलपुर व करौली जिला है। धौलपुर व करौली जिले में भी चंबल नदी किनारे बीहड़ों में अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। धौलपुर से लेकर करौली जिले की सीमा में जहां-जहां चंबल नदी किनारे बीहड़ हैं वहां-वहां राजस्थान के किसानों ने कईयों जगहों पर बीहड़ को समतल करके खेत बना लिया है। राजस्थान में मोरोली, डांगबसई, बसई नीब, कोटरा, सेवरपाल, महदपुरा, सीलपुरा, घुरैया बसई, तिगरा आदि दर्जनों गांव हैं, इसी तरह करौली के मंडरायल, सेवर, रोधई आदि गांवों में बीहड़ों को खेत बना लिया गया है। राजस्थान की सीमा में 27 हजार हेक्टेयर से ज्यादा बीहड़ अब खेत बन गए और फसलें लहलहा रही हैं। साल दर साल यह दायरा बढ़ता जा रहा है।

उप्र, मप्र सहित राजस्थान की जलीय क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में विकसित कर सन् 1978 में विशेष अधिसूचना जारी कर 2100 वर्ग मील क्षेत्र को चंबल सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। जानकार लोगों की मानें तो प्राकृतिक खराब मौसम भी जलीय जीवों पर संकट का कारण है। सर्दियों के मौसम में पाला और कोहरा भी इनकी मौत का कारण बन जाता है। ऐसे समय में इनको पेट्रोलिंग कर जरूरी उपचार भी दिया जा सकता है लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते संभव नहीं हो पाता है। मादा घड़ियाल हजारों की संख्या में चंबल किनारे रेत की गहराई में अंडा देती हैं लेकिन वन विभाग उनमें से केवल 200 अंडों को सहजकर पाता है। हर अंडे का वजन 150 से 200 ग्राम तक रहता है। मादा घड़ियाल के अंडे देने के 45 दिन बाद वन विभाग अंडों को उठाकर घड़ियाल केंद्र में लाता है। यहां इन अंडों को 15 दिन तक रखा जाता है। मादा के अंडे देने के 60 दिन बाद हैचेंज कर ली जाती है। अंडों से घड़ियाल निकालने की प्रक्रिया को हैचेंज कहा जाता है। जो हर साल मई के जून महीने में होती है। मप्र के तीन, उप्र और राजस्थान के दो-दो जिलों के 435 किलो मीटर में फैले चंबल घड़ियाल वन्यप्राणी अभयारण्य क्षेत्र में चमकदार रेत है और ग्वालियर-मुरैना के नेता लंबे समय से रेत के लिए इस क्षेत्र को बाहर करने की मांग कर रहे थे। वर्ष 1979 में स्थापित इस अभयारण्य में लगभग 1400 घड़ियाल हैं। मादा घड़ियाल मार्च-अप्रैल में चंबल नदी के किनारे रेत में अंडे देती हैं। इसलिए वर्ष 2006 में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अभयारण्य से रेत खनन पर रोक लगा दी थी, तभी से क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि अभयारण्य से रेत निकालने के लिए क्षेत्र को डिनोटिफाई करने की मांग कर रहे थे। पिछले माह केंद्रीय वन्यप्राणी बोर्ड की बैठक में यह मुद्दा आया और बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी। अब सैलाना और सरदारपुर खरमोर अभयारण्य की तरह चंबल घड़ियाल अभयारण्य की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होगा। घड़ियाल अभयारण्य का क्षेत्र कम करने को लेकर पर्यावरणविद् चिंतित हैं। उनका मानना है कि इस प्रस्ताव से चंबल नदी से अधिक रेत निकालने को बल मिलेगा। वैसे भी चोरी-छिपे अभयारण्य की सीमा के अंदर से रेत निकाली जा रही है। वे कहते हैं कि इससे घड़ियाल की वंशवृद्धि की प्रक्रिया प्रभावित होगी। देश में चंबल के बाद बिहार की गंडक नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, जो घड़ियाल की संख्या के मामले में विश्व में दूसरे नंबर पर है। ज्ञात हो कि यह अभयारण्य मप्र में मुरैना, भिंड और श्योपुर, उप्र में इटावा, आगरा और राजस्थान में धौलपुर, करौली जिलों में स्थित है।

● **रजनीकांत पारे**

एक्सप्रेस-वे के सर्वे में भी हुआ खुलासा

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) द्वारा राजस्थान के दीगोद से लेकर श्योपुर, मुरैना और भिंड होते हुए उप्र तक को जोड़ने के लिए 404 किलोमीटर लंबा अटल चंबल प्रोग्रेस-वे बनाने की योजना बनाई थी। पहले यह एक्सप्रेस-वे बीहड़ों से ही बनना था, लेकिन पर्यावरण विभाग ने एनओसी नहीं दी थी। एनएचएआई ने जब बीहड़ों में एक्सप्रेस-वे के लिए सर्वे किया था, तब एक रिपोर्ट मुरैना व श्योपुर जिले के कलेक्टरों को दी गई थी, जिसमें बताया गया, कि जौरा क्षेत्र के तिंदोखर से लेकर देवगढ़, कोटरा और कोल्हूडांडा तक जिन बीहड़ों में मिट्टी के पहाड़ नजर आते थे वहां अब सैकड़ों बीघा समतल जमीन और कईयों जगह उस जमीन पर खेती नजर आ रही है। तिंदोखर के अलावा खाड़ौली, मथुरापुरा, गड़ोरा, जखोना, बरवाई, रायपुरा, नगरा, कनेरा से लेकर भिंड के अटेर, खैरी, खिपैना, बिजौरा क्षेत्र में बीहड़ों की कटाई और उनके समतलीकरण का काम आज भी तेजी से चल रहा है। उस समय श्योपुर जिले में 700, मुरैना में 2200 से 2500 बीघा में तो केवल वहीं अतिक्रमण बताया गया था, जहां एक्सप्रेस-वे बनना था। बाकी बीहड़ों में अतिक्रमण हजारों हेक्टेयर में हैं।

पानी बना चुनावी मुद्दा

लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। तमाम पार्टियां और उनके प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वोटरों से लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं। इन सबके बीच बुंदेलखंड की जल सहेलियों ने भी अपनी मांग सामने रख दी है। बुंदेलखंड में जल संरक्षण के लिए काम रही जल सहेलियों ने कहा कि जो पार्टी और प्रत्याशी बुंदेलखंड में पानी की समस्या और पानी की भौगोलिक स्थिति से जुड़े मुद्दे उठाएगा, उनको ही समर्थन दिया जाएगा। जल सहेली मीरा देवी ने कहा कि बुंदेलखंड देश का एक अलग भौगोलिक एवं सांस्कृतिक भूभाग है, जहां की जलवायु और जैव विविधिता प्रदेश के अन्य हिस्सों से अलग है। बुंदेलखंड को पृथक रूप से महत्व देने की आवश्यकता है। जल सहेलियों ने एक घोषणा पत्र तैयार किया है। इसको जल संकट, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु परिवर्तन को केंद्र में रखकर बनाया गया है। पर्यावरण, पर्यटन, कला एवं संस्कृति की समस्याओं को भी शामिल किया गया है।

मीरा ने बताया कि जल सहेलियां अपने स्तर पर लगातार जल संरक्षण के लिए काम कर रही हैं। उन्होंने खुद कई तालाबों को दोबारा जीवित किया है। बुंदेलखंड मे स्थित बुंदेली एवं चंदेलकालीन तालाबों के संरक्षण के लिए सरकार को एक अलग से कार्य योजना बनाने की जरूरत है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल करने की अपील की। इसके साथ ही यह भी कहा कि जब प्रत्याशी वोट मांगने आएंगे तो उनके सामने यह मुद्दा रखा जाएगा। वैसे तो बुंदेलखंड में पानी के साथ ही पलायन, भ्रष्टाचार और विकास का मुद्दा छाया हुआ है। पानी की किल्लत ऐसी कि खजुराहो में लोग रात 10 बजे तक पानी के लिए दर-दर भटकते नजर आते हैं। भ्रष्टाचार ऐसा कि रेत, गिट्टी और डीजल को पीस यानी टुकड़े में मापकर न सिर्फ बिल लगाए गए हैं बल्कि उनका भुगतान भी हो चुका है। खजुराहो संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले पन्ना जिले की सिमरिया तहसील में रात 10 बजे लोग साइकिल पर पानी ले जाते नजर आते हैं। हैंडपंप पर रात को भीड़ दिखने को मिलती है। यहां बोरवेल सूख गए हैं। बुंदेलखंड में दमोह, खजुराहो और पन्ना जिले में पलायन अब भी बड़ी समस्या है। जानकार कहते हैं कि पलायन के बाद यहां 80 फीसदी गांव खाली हो जाते हैं, लेकिन मनरेगा में उनके नाम की एंट्री होती रहती है। भुगतान भी होता रहता है। बुंदेलखंड में युवाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है।

हर चुनाव में सियासी दलों की ओर से नए मुद्दे उछाले जाते हैं। लेकिन, झांसी-ललितपुर संसदीय क्षेत्र में पानी की समस्या चुनावों में बड़ा सियासी मुद्दा बनी हुई है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पूर्व पं. जवाहर लाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस मुद्दे को उठा चुके हैं। सबसे ज्यादा बांध वाले इस लोकसभा क्षेत्र के कई हिस्सों में गर्मी आते ही जल संकट छा जाता है। लोगों की निर्भरता टैंकरों से आने वाले पानी पर हो जाती है। इस मुद्दे की गूंज लखनऊ और दिल्ली तक में सुनने को मिल जाती है। उप्र के 80 लोकसभा क्षेत्रों में से सबसे ज्यादा 22 बांध झांसी-ललितपुर संसदीय क्षेत्र में हैं। इससे जाहिर है कि यहां अकूत जल संपदा मौजूद है। बावजूद, गर्मी की शुरुआत से ही गांवों में जल संकट छा जाता है। यहां तक कि शहरी क्षेत्र के भी कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। लोग टैंकरों से भेजे जाने वाले पानी पर निर्भर हो जाते हैं। जल संकट का यह मुद्दा दशकों से सियासी दलों की सियासत को धार देता चला आ रहा है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सन् 1952 में लोकसभा के पहले चुनाव में जनसभा को संबोधित करने पं. जवाहर लाल नेहरू झांसी आए थे। उन्होंने क्षेत्र में व्याप्त जल संकट का मुद्दा उठाया था और उसके समाधान का भी भरोसा दिया था। हालांकि, इसके बाद के सालों में झांसी और ललितपुर में कई बांधों का निर्माण किया गया, इसके बावजूद पानी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। जबकि, 15 फरवरी 2019 को झांसी में सभा को संबोधित करने झांसी आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां के इस मुद्दे को उठाया था और बुंदेलखंड क्षेत्र को पाइप पेयजल योजना की सौगात दी थी। इस पर तेजी से काम काम जारी है। कई गांवों में पहली बार नलों के जरिए पानी पहुंचा है। लेकिन, अभी भी कई हिस्सों में लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह तो केवल बानगी भर है। इसके अलावा भी लोकसभा और विधानसभा के हर चुनाव में क्षेत्र में व्याप्त पानी की समस्या विपक्षी दलों के लिए सत्तापक्ष को घेरने के लिए बड़ा हथियार बनी रही। राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में भी जल संकट का मुद्दा स्थायी रूप से अपनी जगह बनाए रहा।

साल 2016 में बुंदेलखंड सूखे की चपेट में था। पानी के लिए यहां हाहाकार मचा था। तब केंद्र सरकार की ओर से यहां वाटर एक्सप्रेस भेजी गई थी। इस ट्रेन के जरिए पानी के टैंकर यहां भेजे गए थे। लेकिन, प्रदेश की सपा सरकार ने इस पानी को लेने से इनकार कर दिया था। ट्रेन छह दिन तक स्टेशन पर खड़ी रही थी। बाद में इसे वापस लौटा दिया गया था। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आरोप-प्रत्यारोपों का लंबा दौर चला था। यह मुद्दा केंद्र और प्रदेश की सियासी सुर्खियों में छाया रहा था।

● श्याम सिंह सिकरवार

जल जीवन मिशन से खुल रहे हैं रोजगार के अवसर

सूखाग्रस्त कहलाने वाले बुंदेलखंड के गांवों में घर-घर तक पेजयल पहुंचने के रास्ते खुल गए हैं। साथ ही गांव के लोगों को यहां बनाई गई परियोजनाओं में पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मेसन के रूप में काम भी मिलने लगा है। हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की जाती है। जन-जन को शुद्ध पेयजल का लाभ पहुंचाने के साथ ही सरकार स्कूली बच्चों के भविष्य और महिलाओं के जीवन को संवारने और उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख रही है। ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ ही स्वच्छ पेयजल के लिए हर गांव से 5 महिलाओं को जल जांच का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महिलाएं गांव में फील्ड टेस्ट किट से पानी की जांच कर रही है। बुंदेलखंड के महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, झांसी में कुछ ऐसे गांव थे, जहां जल संकट की वजह से लोग अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते थे। जल जीवन मिशन योजना पहुंचने के बाद स्थितियां बदलीं और स्वच्छ पेयजल पहुंचने लगा है। ऐसे गांवों के लिए जल जीवन मिशन योजना रिश्तों की लाइफ लाइन बनी है। पथरीली जमीनों पर पीने के पानी के लिए पाइप लाइन बिछाने, गांव-गांव पानी की टंकियों को बनाने, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने, जल स्त्रोतों को बढ़ाने और घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का काम तेजी से किया गया है।

18वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा मिशन 400 पार पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने पूरा दमखम लगा दिया है। अपने मिशन को पूरा करने के लिए भाजपा एक सीट निर्विरोध जीत चुकी है, दो पर जीत पहले से तय मानी जा रही है। क्योंकि मप्र की खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन दस्तखत ना होने से खारिज हो गया। फिर गुजरात के सूरत में कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी निलेश कुम्भानी और डमी, दोनों प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया था। अब इंदौर की सीट पर भाजपा ने ऐसा दम मारा कि कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम भी भाजपा के पाले में आ गिरे हैं।

● राजेंद्र आगाल

जैसे कोई दूल्हा शादी से पहले घोड़ी से ही भाग जाए, आजकल कांग्रेस का हाल वही हो चुका है। पहले गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर कांग्रेस को बिना चुनाव लड़े ही हार मिल गई, क्योंकि उसके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। अब मप्र की इंदौर सीट पर चुनाव से पहले ही पार्टी उम्मीदवार ने मैदान छोड़ दिया। इससे इंदौर लोकसभा क्षेत्र के इतिहास में पहली बार कांग्रेस बे-उम्मीदवार हो चुकी है। साथ ही उसकी चुनावी चुनौती समाप्त हो गई, जहां वो पिछले 35 साल से जीत की बाट जोह रही है। इससे पहले खजुराहो में सपा प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया। इससे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। कुल मिलाकर तीनों सीटों पर चुनाव के बिना ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खाते में हार लगभग तय हो चुकी है। मिशन 400 पार में जुटी भाजपानीत एनडीए इसे बड़ी सफलता मान रही है, वहीं विपक्षी इसे राजनीतिक खेल बता रहे हैं।

18वीं लोकसभा के चुनाव में भाजपा सूरत लोकसभा सीट जीतकर 1-0 से आगे हो गई है। वहीं कांग्रेस तथा प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने और निरस्त होने के चलते इंदौर और खजुराहो सीट पर भी भाजपा की जीत तय है। इन घटनाक्रमों को भाजपा मिशन 400 के लिए शुभ मान रही है। लेकिन देश और प्रदेश में सूरत के कांग्रेस प्रत्याशी नीलेश कुम्भानी और इंदौर के कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम का नामांकन वापस लेना चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे यह पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने अपनी पार्टी से दगा किया हो। इससे पहले 2009 में कांग्रेस के कद्दावर नेता राजकुमार पटेल भी नामांकन पत्र फार्म-ए की मूल प्रति जमा नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका नामांकन रद्द हो गया था।

रण छोड़ रहे कांग्रेसी

देश के चुनाव में दो चरण बीत चुके हैं। और अब कांग्रेस के भीतर रण छोड़ने का अलग ही चरण चल रहा है। कांग्रेस में कोई प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ रहा है, कोई उम्मीदवारी छोड़ रहा है। और कोई गढ़ माने जाने वाली सीट पर उम्मीदवारी का पत्ता ही नहीं खोल रहा है। अब गत दिनों मप्र की बड़ी लोकसभा सीट इंदौर में जहां बारात तैयारी थी, बाराती तैयार थे, लेकिन अचानक दूल्हा पलट गया। यानी इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापसी के आखिरी दिन खुद ही अपना पर्चा वापस लेकर स्वच्छता में टॉप रहने वाले शहर इंदौर से कांग्रेस को चुनाव में साफ कर दिया। 400 पार का नारा देती भाजपा देश में एक सीट निर्विरोध जीत चुकी है, दो पर जीत पहले से तय मानी जा रही है। क्योंकि मप्र की खजुराहो सीट पर इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी मीरा यादव का पर्चा दस्तखत ना होने से खारिज हो गया। यहां बाद में इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी न रहने पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया है। फिर गुजरात के सूरत में कांग्रेस के अधिकृत और डमी, दोनों प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया था। बाकी बसपा समेत निर्दलीय प्रत्याशियों ने पर्चा वापस से लिया। भाजपा के प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए। अब मप्र के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के गृह जिले इंदौर की सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना पर्चा वापस ले लिया है।

इतना ही नहीं, जब इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन वापस लेने पहुंचे तो उनके साथ कलेक्टर ऑफिस में भाजपा विधायक रमेश मेंदोला देखे गए और फिर भाजपा में शामिल होने के लिए मप्र के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ अक्षय कांति बम निकल पड़े। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों कांग्रेस प्रत्याशी ने ऐसा किया? कहीं सरकार पलटे या विधायक। तुरंत ऑपरेशन लोटस के

अक्षय की टिकट वापसी पर घिरे प्रदेश अध्यक्ष

अक्षय बम के नाम वापसी के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पहुंचे। बम के नाम वापस लेने के चलते यहां कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराजगी जताई। संवाददाताओं से चर्चा में पटवारी ने कहा- इंदौर बुद्धिजीवियों का शहर है, यह वह शहर है जिसने विधानसभा का चुनाव हो, महापौर के चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन दिया है, ताकत दी है। अब भाजपा ने इस ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। भाजपा के लोगों ने इंदौर शहर का अपमान किया है। वोटरों को चुनौती दी है कि लोकतंत्र अपनी जगह ताकतवर है, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा- अब पार्टी इस मामले में सोच-समझकर निर्णय लेगी। कांग्रेस की ओर से बम के साथ मोती सिंह पटेल ने भी फॉर्म जमा किया था। बी-फॉर्म अक्षय को मिला और उनके फॉर्म में किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। इसलिए कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार जब बम हुए तो पटेल का फॉर्म रिजेक्ट हो गया। पटेल ने भी पार्टी से ही फॉर्म जमा किया था, यदि वे निर्दलीय भरते तो उसमें 10 प्रस्तावक चाहिए थे। पटेल के प्रस्तावक कम थे, इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, नहीं तो वे निर्दलीय भी लड़ सकते थे। वहीं मप्र की खजुराहो लोकसभा सीट कांग्रेस ने गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को दी थी, लेकिन यहां भी सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। इस तरह भाजपा को वॉकओवर मिल गया है। यहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा मैदान में हैं। हालांकि, इंडिया गठबंधन ने ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी पूर्व आईएएस आरबी प्रजापति को समर्थन दिया, पर यह खानापूर्ति जैसा लग रहा है। बता दें कि खजुराहो में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग हो चुकी है।

आरोप लगते हैं। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन लेकर पलटने पर भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी की कोई कमजोर नस दबाई गई है।

इंदौर में कांग्रेस की शहर कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव को कलेक्टर दफ्तर के बाहर फोन पर कांग्रेस के किसी नेता को कॉल करके गुस्सा निकालते देखा गया। इस दौरान वह फोन पर कह रहे थे, मैं शुरू से कह रहा था कि नाम वापस लेगा, पैसा देखकर टिकट दिया, क्या योगदान था? क्या संघर्ष किया? पार्टी हाईकमान को देखना चाहिए हमारे जैसे कार्यकर्ता को मार रही है। अकेले खड़े हैं, वो निकल गया। पार्टी क्यों देती है पैसा देखकर, काम को आधार नहीं बनाते हो? यानी कांग्रेस के ही स्थानीय नेता अपने ही प्रत्याशी पर पहले से सवाल उठाते आए हैं। उन्हें डर था कि ये पार्टी पाला पर्चा सब बदलेंगे। हुआ वही जो कांग्रेस के नेताओं को डर था। अब सवाल है कि खजुराहो, सूरत और इंदौर में जो हुआ, क्या आगे मप्र में और भी किसी सीट पर हो सकता है? जवाब में मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कि हमारा दर खुला है, खुला ही रहेगा, तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा, करीब ढाई लाख लोग ज्वाइन कर रह हैं, हमको सेलेक्शन करना पड़ता है किसको आने दें। 179 पूर्व विधायक पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, पार्टी का बढ़ता ग्राफ है। छतरी में अधिकांश लोग समाहित हो रहे हैं। कांग्रेस सोचे उनके लोग पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं।

हर फेज में भाजपा को अच्छी खबर

बता दें कि हर चरण के चुनाव से पहले भाजपा के खाते में एक अच्छी खबर आ रही है। फर्स्ट फेज से पहले खजुराहो में सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ। दूसरे फेज से पहले सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ। तीसरे फेज से पहले अब इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापिस ले लिया। और अब उस सीट की दस्तक के बारे में बात करते हैं, जहां 2014 में

ऑपरेशन लोटस, जबरदस्त टीम वर्क

जिस दिन कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को इंदौर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया था, उसी दिन उन्हें भाजपा में शामिल करने की रणनीति पर काम शुरू हो गया था। अभियान को आपरेशन लोटस नाम दिया गया। फिल्म के मुख्य किरदार बने कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक रमेश मेंदोला। गुटबाजी के लिए कुख्यात इंदौर भाजपा में आपरेशन लोटस में जबरदस्त टीम वर्क दिखा। बड़े किरदारों ने इसे पार्टी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। दरअसल, योजना सूरत की तर्ज पर इंदौर में भी निर्विरोध निर्वाचन की थी। कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय को इसके लिए दिल्ली और भोपाल से हरी झंडी भी मिल गई थी, लेकिन अंतिम समय में कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन वापस नहीं लेने से ऐसा नहीं हो सका। तय रणनीति के मुताबिक, विजयवर्गीय ने करीब एक सप्ताह पहले बम से एक होटल में मुलाकात की थी। बम बैठक में अकेले ही पहुंचे थे। बैठक में नाम वापसी को लेकर चर्चा हुई। विजयवर्गीय ने बम को समझाया कि कांग्रेस में उनका कोई भविष्य नहीं है। इस मुलाकात में ही तय हो गया था कि नाम वापसी के अंतिम दिन यानी 29 अप्रैल को बम नामांकन वापस ले लेंगे। बैठक में बम ने आशंका जताई थी कि नाम वापसी की स्थिति में उन पर हमला हो सकता है। इसके बाद विजयवर्गीय ने विधायक रमेश मेंदोला को जिम्मेदारी सौंपी। मेंदोला ने वार्ड 24 से पार्षद जितेंद्र यादव जीतू को 29 अप्रैल को बम के आसपास बने रहने के निर्देश दिए। इस मुलाकात के बाद विजयवर्गीय ने उनके पिता कांतिलाल से भी मुलाकात की थी। इसके बाद बम की भाजपा में शामिल होने की राह साफ हो गई।

पहले निर्दलीयों को साधने का था प्रयास

बम से बात करने से पहले पार्टी का प्रयास निर्दलीय प्रत्याशियों को साधने का था, लेकिन ऐसा करने पर आशंका थी कि कांग्रेस इससे सतर्क हो जाएगी और बम को भाजपा में शामिल करने की योजना पर पानी फिर सकता है। इसके बाद तय हुआ कि बम के नामांकन फॉर्म वापस लेने के बाद ही निर्दलीय प्रत्याशियों से चर्चा की जाएगी। निर्दलीय प्रत्याशियों से चर्चा की जिम्मेदारी तीन नेताओं को सौंपी गई। इसके बाद इन नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशियों से संपर्क करना शुरू किया।

राजकुमार पटेल प्रदेश के पहले रणछोड़

अगर मप्र की बात करें तो कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल का नाम चुनाव छोड़ने वालों में पहले नंबर पर है। राजकुमार पटेल कांग्रेस के पुराने नेता हैं। वो बुधनी से विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। राजकुमार पटेल 2009 के लोकसभा चुनाव में तब चर्चा में आए थे जब कांग्रेस ने उन्हें विदिशा-रायसेन लोकसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन नामांकन पत्र फॉर्म-ए की मूल प्रति न जमा किए जाने की वजह से खारिज कर दिया गया था। इस वजह से कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा था। उस वक्त भाजपा की ओर से सुषमा स्वराज पार्टी प्रत्याशी थीं। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल का नामांकन रद्द होने के कारण लोकसभा चुनाव में सुषमा स्वराज को वॉक ओवर मिल गया था। बाद में एके अंटोनी की अध्यक्षता वाली कांग्रेस की अनुशासन कमेटी ने राजकुमार पटेल को छह साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। बाद में उनकी पार्टी में वापसी हो गई थी।

निर्विरोध निर्वाचित सांसद

- आनंद चंद (निर्दलीय) 1951 - बिलासपुर
- टीए रामलिंगम चेट्टियार (कांग्रेस) 1951 - कोयंबटूर
- टी सांगना (कांग्रेस) 1951 - रायगढ़ा-फुलबनी
- कृष्णा चार्य जोशी (कांग्रेस) 1951 - यादगीर
- मेजर जनरल एचएस हिम्मासिंहजी (कांग्रेस) 1951 - हलार
- डी सत्यनारायण राजू (कांग्रेस) 1957 - राजमुंदरी
- संगम लक्ष्मी बाई (कांग्रेस) 1957 - विकाराबाद
- बिजॉय चंद्र भगवती (कांग्रेस) 1957 - दरांग
- मंगरुबाबू उइके (कांग्रेस) 1957 - मंडला
- एचजे सिद्दनानजप्पा (कांग्रेस) 1957 - हसन
- मानवेंद्र शाह (कांग्रेस) 1962 - टिहरी गढ़वाल
- टीटी कृष्णामाचारी (कांग्रेस) 1962 - तिरुचेंदूर
- हरेकृष्ण महताब (कांग्रेस) 1962 - अंगुल
- कनुरी लक्ष्मण राव (कांग्रेस) 1967 - विजयवाड़ा
- आर ब्रह्मा (कांग्रेस) 1967 - कोकराझार
- मोहम्मद शफी कुरैशी (कांग्रेस) 1967 - अनंतनाग
- कुशोक बकुला रिनपोछे (कांग्रेस) 1967 - लद्दाख
- सेनयांगबा चुबातोशी जमीर या एससी जमीर (एनएनओ) 1967 - नागालैंड
- पीएम सईद (कांग्रेस) 1971 - लक्षद्वीप
- रिनचिन खांडू खिमरे (कांग्रेस) 1977 - अरुणाचल पश्चिम
- छत्र बहादुर छेत्री (कांग्रेस) 1977 - सिक्किम
- फारूक अब्दुल्ला (जेकेएनसी) 1980 - श्रीनगर
- मोहम्मद शफी भट (जेकेएनसी) 1989 - श्रीनगर
- डिंपल यादव (सपा) 2012- कन्नौज
- मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल (भाजपा) 2024 - सूरत

हारी भाजपा प्रत्याशी ने फिर हार नहीं मानी। उसी सीट को अपना घर बनाया। 2019 में जीत हासिल की। ये सीट है उप्र की अमेठी की। जहां स्मृति ईरानी ने नामांकन किया। हलफनामे में दिल्ली नहीं अमेठी में बनवाए गए घर को ही अपना पता दिखाया। इसी अमेठी को राहुल गांधी भी अपना घर-आंगन कहते थे। लेकिन अमेठी से राहुल के लड़ने को लेकर असमंजस अब तक बना हुआ है।

भाजपा शासित राज्य में इंडिया के सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस ने खजुराहो सीट सपा के लिए छोड़ दी थी। भाजपा ने इस सीट पर अपने प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को इस सीट से मैदान में उतारा है। रिटर्निंग अधिकारी ने सपा प्रत्याशी मीरा यादव के नामांकन पत्र में दो कमियां निकाल दीं। पहला, फॉर्म के साथ लगी मतदाता सूची प्रमाणित नहीं है या पुरानी है। दूसरी- दो जगह हस्ताक्षर कराना था, लेकिन केवल एक ही स्थान पर साइन किया गया है। यहां सपा का पर्चा खारिज होने के बाद इंडिया गठबंधन ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के कैंडिडेट को समर्थन दे दिया है। सूरत लोकसभा सीट से भाजपा के मुकेश दलाल को निर्विरोध विजेता घोषित किया गया था। इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार निलेश कुम्भानी का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रद्द कर दिया था। उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में गड़बड़ियों का हवाला देकर नामांकन रद्द किया गया था। कांग्रेस के उम्मीदवारों का नामांकन रद्द होने के बाद बाकी बचे 8 उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ऐसे में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए गए। चुनाव आयोग ने उन्हें जीत का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया है। यह पहली बार है जब लोकसभा चुनाव में भाजपा का कोई सांसद निर्विरोध चुना गया हो।

टिकट मिला, सहयोग नहीं

कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम द्वारा नामांकन वापस लेकर भाजपा ज्वॉइन करने की कहानी बड़ी लंबी है। इसमें कई मोड़ और हर मोड़ की अपनी ही गाथा है। इस निर्णय का इंदौर की राजनीति, प्रमुख नेताओं और अब बचे-खुचे चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आइए देखते हैं। पार्टियों के अपने शुभ-लाभ हो गए, लेकिन प्रशासन की चुनौती जरूर बढ़ गई है, चुनाव नीरस होने से मतदान का प्रतिशत बनाए रखना अब आसान नहीं होगा। दो वर्ष पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने वादा किया था कि उन्हें इंदौर-4 से टिकट देंगे। तब अक्षय ने वहां काम शुरू कर दिया था। पानी के टैंकर चलाए और कार्यकर्ताओं की टीम बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर राजा मंधवानी (वे भी आज भाजपा में आ गए) को टिकट दे दिया। वे पाकिस्तान से आए थे, वहां के कागजात को लेकर कोर्ट-कचहरी भी हुई। लोकसभा चुनाव में कोई वरिष्ठ नेता तैयार नहीं हुआ तो अक्षय को इसी आधार पर तैयार किया गया कि अगली विधानसभा में ध्यान रखेंगे, लेकिन जैसा सपोर्ट मिल रहा था, उससे समझ आ गया कि ये वादा भी बहुत भरोसा करने लायक नहीं है। कुछ ही दिनों में पूर्व विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल, अंतरसिंह दरबार और पंकज संघवी सहित कई बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। अक्षय ने सचिन पायलट सहित वरिष्ठ नेताओं की सभा कराने की मांग की थी। सचिन इंदौर भी आए, लेकिन सभा नहीं कराई गई। मतदान के दिन बूथ पर टेबल लगाने की व्यवस्था के लिए पिछले चुनाव से ढाई गुना अधिक खर्च बताया जा रहा था। 2500 से ज्यादा बूथ पर यह राशि बहुत हो रही थी।

प्रत्याशी के नाम की घोषणा में विलंब के दौरान बयानबाजी से विजयवर्गीय को लेकर सवाल उठ रहे थे। एक बार उन्होंने कहा- इंदौर का टिकट बदल रहा है, एक बार कहा- किसी महिला को मिल सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन वापस कराने में अहम भूमिका निभाकर उन्होंने पुराने सवालों का जवाब दे दिया है। हालांकि भाजपा प्रत्याशी लालवानी इसमें नजर नहीं आए। कांग्रेस के डमी उम्मीदवार मोतीसिंह पटेल की उम्मीदवारी पहले ही खारिज हो चुकी है। एक निर्दलीय लीलाधर चौहान, जिन्हें कांग्रेस से जुड़ा समझा जा रहा था, उन्होंने भी नाम वापस ले लिया है। ऐसे में कांग्रेस के पास किसी अन्य निर्दलीय का समर्थन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा है। अभी 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंदौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का गृह जिला है और उनके कहने पर अक्षय कांति बम का टिकट हुआ था। बम के टिकट पर दिल्ली की शुरू से नाराजगी रही। राहुल गांधी तो स्पष्ट कह चुके थे कि मप्र में सभी बड़े नेता चुनाव लड़ें। इसी के चलते इंदौर से कार्यकर्ताओं की ओर से पटवारी को चुनाव लड़ाए जाने की

क्या छिन रहा वोट का अधिकार

गुजरात के सूरत के बाद अब मप्र के इंदौर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव में क्या हुआ? सूरत में भाजपा प्रत्याशी को छोड़ सारे प्रत्याशियों का नामांकन रद्द हो गया। भाजपा के प्रत्याशी महेश दलाल बिना चुनाव लड़े, बिना वोटिंग हुए ही जीत गए। अब, इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस ले लिया। वह भी नामांकन वापस लेने के अंतिम दिन, अंतिम क्षणों में। कुछ ही देर बाद भाजपा के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ उनकी तस्वीर सामने आ गई। खजुराहो में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश हुई थी। तीनों सीटों पर हुए घटनाक्रमों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल तेजी से उभर रहे हैं कि क्या यह माना जाए कि आपके वोट का अधिकार छीना जा रहा है। वोट का अधिकार नागिरक का अधिकार है, इसे ही खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं। नागरिकों में समर्थक सभी दलों के हैं, भाजपा के, कांग्रेस के, अन्य दूसरे दलों के भी। तो क्या कुछ लोगों की मिलीभगत, पैसे व ताकत के बल पर नागरिकों के वोट डालने के अधिकार को ही खत्म किया जा सकता है! सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है कि क्या हम नो इलेक्शन की तरफ बढ़ चले हैं! सूरत व इंदौर की घटना से कांग्रेस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आखिर कांग्रेस कैसे लोगों को टिकट बांट रही है। प्रत्याशी चुनने के मामले में कांग्रेस चयन समिति गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। अब तक कांग्रेस के विधायक, सांसद व नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे थे। लेकिन अब तो पार्टी के प्रत्याशी ही नाम वापस ले रहे हैं या जानबूझकर गलती कर नामांकन रद्द करवा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना लाजिमी है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि भाजपा के शीर्ष नेता विपक्षी उम्मीदवारों को डराने-धमकाने और मामले दर्ज करवाने का काम कर रहे हैं।

मांग जोरों से उठी थी, लेकिन उन्होंने अक्षय कांति को टिकट दिलवाया।

अब तक 35 निर्विरोध जीते

लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा, लेकिन गुजरात की सूरत सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन खारिज होने और शेष 8 उम्मीदवारों के नाम वापस लेने से भाजपा के मुकेश दलाल को लोकसभा सीट से निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इसी तरह इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन नाम वापसी के अंतिम दिन लेकर वहां कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी। अब कांग्रेस प्रत्याशी के भाजपा नेताओं संग गलबहिया करने वाली तस्वीरें सामने आई है। इंदौर से पहले इंडिया गठबंधन के घटक दल समाजवादी पार्टी के खजुराहो से उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया और वहां भी भाजपा को मजबूत चुनौती देने वाला कोई उम्मीदवार नहीं बचा। सूरत, खजुराहो और इंदौर के वाकये के बाद विपक्ष इसे भाजपा की साजिश बता रहा है। राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने पटना में कहा कि पीएम मोदी के शासन में लोकतंत्र खत्म करने की कैसी तैयारी है यह सूरत, इंदौर और खजुराहो की घटनाओं से पता चलता है। अगर भाजपा फिर से सत्ता में आई तो लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर देगी।

हालांकि लोकसभा के लिए उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन कोई पहली बार नहीं हुआ है। इतिहास पर गौर करें तो वर्ष 1951 से अब तक 35 ऐसे सांसद रहे जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ। आखिरी बार ऐसा वाकया वर्ष 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव के दौरान देखने को मिला था। समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने 2012 में कन्नौज लोकसभा उपचुनाव निर्विरोध जीता था। उनसे पहले, उनके पति अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ते थे। फिर उप्र के मुख्यमंत्री बनने के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। उस दौरान डिंपल के निर्विरोध निर्वाचन पर इतना शोर नहीं मचा था क्योंकि किसी प्रमुख दल ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया था। वहीं इस बार सूरत और इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवार का तो खजुराहो में

समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ। यहां तक कि सूरत में नाटकीय घटनाक्रम में शेष उम्मीदवारों ने अचानक से अपना नाम वापस ले लिया। इससे भाजपा निशाने पर है और विपक्ष इसे भाजपा की साजिश बता रही है। जिन 35 सांसदों का अब तक निर्विरोध निर्वाचन हुआ है उसमें ज्यादातर कांग्रेस के हैं।

वर्ष 1951 में कांग्रेस के 5, वर्ष 1957 में कांग्रेस के 5, वर्ष 1962 में कांग्रेस के 3, वर्ष 1967 में कांग्रेस के 4 और एनएनओ के एक, वर्ष 1971 में कांग्रेस के एक, वर्ष 1977 में कांग्रेस के दो, वर्ष 1980 में जेकेएनसी के एक, वर्ष 1989 में जेकेएनसी के एक और वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी से एक सांसद का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वहीं इन वर्षों में जिन सांसदों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ, उसमें ज्यादातर उपचुनावों में निर्वाचित होने वाले रहे। साथ ही निर्विरोध निर्वाचित होने वाले सांसदों में ज्यादातर ऐसे रहे जिनके परिवार के किसी सदस्य का उस सीट से पुराना जुड़ाव रहा। वहीं सूरत, खजुराहो और इंदौर में ऐसी स्थिति नहीं है। यहां प्रमुख विपक्षी उम्मदीवार का पर्चा खारिज हुआ और कुछ उम्मीदवारों ने भाजपा नेताओं संग तस्वीरें भी साझा कीं। ऐसे में विपक्ष अब इसे भाजपा की साजिश करार दे रहा है।

हालांकि अभी इस बात को लेकर फैसला नहीं हुआ है कि अगर चुनाव में सिर्फ एक प्रत्याशी बचे, चुनाव ही ना हो, तो नोटा का क्या होगा? लेकिन वैसे चुनाव में मतदाता कितनी दिलचस्पी लेंगे, जिसमें मजबूत प्रत्याशी ही बाहर हो गया हो या उसका नामांकन रद्द हो गया हो। क्या मतदाताओं के मन में यह सवाल नहीं उठेगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। क्या आम वोटरों के सामने यह सवाल नहीं होगा कि अभी ऐसी चीजें एक-दो जगह पर हो रही हैं, अगर इसे प्रोत्साहन मिला, रोका नहीं गया, तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर मजबूत उम्मीदवार यही सब करने लगेंगे। संभव है, कुछ लोग इस तरह के पुराने उदाहरण सामने लाकर ऐसी घटनाओं को जायज ठहराने की भी कोशिश करें। लेकिन लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि ऐसे मामलों में चुनाव आयोग आगे आए और हस्तक्षेप करे।

दरअसल, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही भाजपा ने न्यू जॉइनिंग कमेटी बनाकर कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के नेताओं को भाजपा से जोड़ना शुरू कर दिया था। मप्र में न्यू जॉइनिंग कमेटी के नरोत्तम मिश्रा का दावा है कि अभी तक 2 लाख से अधिक कांग्रेस भाजपा में आ चुके हैं। दरअसल, मिशन 400 को पूरा करने के लिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रयास शुरू कर दिया था, इसके लिए पार्टी ने जहां अपने पदाधिकारियों की घोषणा पहले कर दी थी, वहीं दूसरी पार्टियों के असंतुष्ट नेताओं को भाजपा में लाने का प्रयास शुरू कर दिया था।

पहले 2 फेज में 190 लोकसभा सीटों पर वोटिंग खत्म

देश में दो चरणों में 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। यानी कुल 543 में 35 प्रतिशत सीटों के प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में बंद हो चुके हैं। इन दो चरणों में कम वोटिंग ने सियासी दलों के साथ वोटर्स को भी भ्रमित कर दिया है। चुनाव प्रचार भी पीक पर पहुंच गया है। सियासी दल एक-दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में देश के पांच हिस्सों में चुनावी तस्वीर हर रोज बदल रही है। महाराष्ट्र और कर्नाटक की लड़ाई सबसे रोचक है। 80 सीटों वाले उप्र की 16 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 7 मई 10 सीटों पर वोटिंग के साथ पश्चिमी उप्र कवर हो जाएगा। दो चरणों में हुई कम वोटिंग के असर को भांपने के लिए सियासी पार्टियां सीटों के उतार-चढ़ाव का आंकलन कर रही हैं। बीते चुनावों का वोटिंग ट्रेंड देखें तो क्षेत्र में भाजपा-रालोद गठबंधन की सपा-कांग्रेस पर बढ़त है। हालांकि यहां राजपूतों की नाराजगी एनडीए की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश के कन्नौज से उतरने व अमेठी-रायबरेली से राहुल-प्रियंका के नाम की चर्चा से सियासी ग्राफ में उछाल देखा जा रहा है। उधर, दिल्ली की धारा से विपरीत बहने वाले पंजाब में भाजपा, आप, अकाली व कांग्रेस अकेले लड़ रही हैं। सभी 13 सीटों पर कांटे की जंग है। भाजपा ने दूसरे दल से आए 6 लोगों को उतार मुकाबले को रोचक बना दिया है। हरियाणा में कांग्रेस ने 8 सीटों पर सधे प्रत्याशी घोषित कर भाजपा को चुनौती दी है। इनमें ब्राह्मण, पंजाबी, गुर्जर, ओबीसी, अहीर, एससी व जाट हैं।

आसान नहीं दिल्ली का मैदान

राजधानी दिल्ली में इंडिया गठबंधन की राह कठिन होती जा रही है। भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त मोर्चाबंदी भी मजबूत नजर नहीं आ रही है। यहां की सात सीटों में से देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस जहां तीन सीटों पर ही लड़ रही है, वहीं सबसे नई पार्टी आप चार सीटों पर मैदान में है। लेकिन दोनों ही पार्टियों में आपसी सामंजस्य नहीं दिख रहा है। रामलीला मैदान की रैली को छोड़ दें तो दोनों ही पार्टियों के नेता अब तक कहीं भी मैदान में एक साथ नजर नहीं आए हैं। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर मिलता दिख रहा है।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भले ही मिलकर लड़ रहे हों, लेकिन लगता नहीं कि दोनों ही दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं के दिल मिल गए हैं। वैसे कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह खूब दिख रही है। आम आदमी पार्टी का उभार कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हुआ था। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान अरविंद केजरीवाल अक्सर तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भ्रष्टाचारी बताते हुए सत्ता में आने पर जेल भेजने का दावा करते थे। कांग्रेसी कार्यकर्ता उस बात को अब तक भूल नहीं पाए हैं। शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित कहते भी कह रहे हैं कि अपनी मां के अपमान का बदला वे जरूर लेंगे। ऐलानिया तौर पर संदीप आम आदमी पार्टी के मुखर विरोधी रहे हैं। लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ जुबान बंद रखी। उन्होंने दिल्ली से चुनाव लड़ने की चाहत का खुलकर इजहार भी किया। उनकी नजरें कांग्रेस के हिस्से में आई उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट पर थीं, जहां से भाजपा के मनोज तिवारी तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने यहां से जेएनयू की वामपंथी छात्र राजनीति से कांग्रेसी दायरे में शामिल हुए कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बना दिया है जिसे संदीप दीक्षित पचा नहीं पा रहे हैं। एक चुनावी बैठक में तो उन्होंने कन्हैया कुमार के साथ ही दिल्ली के कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया को खरी-खोटी सुना दी। कन्हैया ने उन पर भाजपा की तरह बोलने का आरोप भी लगा दिया। जिसका संदीप ही नहीं, कई कांग्रेसी नेताओं ने जोरदार विरोध किया। गनीमत इतनी रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

उत्तर पश्चिमी दिल्ली से कांग्रेस ने जिस उदित राज को अपना उम्मीदवार बनाया है, वे 2014 में भाजपा के टिकट पर दिल्ली से ही सांसद बने थे। यह बात और है कि अगली बार उनका टिकट कट गया तो वे बागी बन गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। उदित राज को भी कांग्रेस के अंदरूनी हलके में खुलकर बाहरी उम्मीदवार बोला जा रहा है। उनकी उम्मीदवारी को कांग्रेसी ही नहीं पचा पा रहे हैं। उनके बड़बोलेपन से भी कांग्रेसी परेशान हैं।

दिल्ली के चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने दो तरह की चुनौतियां हैं। पहली चुनौती आप और कांग्रेस के बीच जमीनी स्तर पर तालमेल और सहयोग को लेकर है तो दूसरी चुनौती कांग्रेस का अपना अंदरूनी संकट है। कांग्रेस के अंदरूनी संकट का ही नतीजा है कि कन्हैया कुमार और उदित राज कांग्रेसी हलके को स्वीकार्य नहीं हो पा रहे हैं। दोनों नेताओं में एक समानता यह भी है कि दोनों की छवि अतिवादी विचारों की है। पारंपरिक कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि इनकी छवि के चलते इनके लिए समर्थन जुटाना आसान नहीं होगा। कन्हैया कुमार के जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष रहते हुए ही देश के टुकड़े होंगे... वाली नारेबाजी हुई थी। कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि कन्हैया कुमार पर इस नारे की छवि इतने गहरे तक अंकित हो चुकी है कि उनके लिए वोट हासिल कर पाना आसान नहीं होगा।

बेशक दिल्ली पर जेएनयू छात्रसंघ चुनाव नतीजों का असर नहीं पड़ता, लेकिन दिल्ली में जेएनयू के होने की वजह से वहां होने वाली घटनाओं की जानकारी दिल्लीवालों को और इलाके के लोगों की तुलना में ज्यादा ही है। कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि जैसे ही वे मैदान में उतरेंगे, भाजपा के कार्यकर्ता और नेता भारत तेरे टुकड़े होंगे... जैसे नारों की जनता को खूब याद दिलाएंगे। प्रचार में उतरे कांग्रेसी नेताओं के लिए उसका बचाव करना आसान नहीं है। स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को लगता है कि संदीप दीक्षित अगर मैदान में होते तो वे कन्हैया की तुलना में ज्यादा प्रभावी होते। उनकी वजह से सुस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मैदान में उतर जाते। दिल्ली में कांग्रेस विरोधी भी शीला दीक्षित के विकास कार्यों को नकार नहीं पाते। शीला दीक्षित के दिल्ली में अब भी समर्थक ज्यादा हैं। इसी तरह उदित राज को लेकर भी कांग्रेसी सहज नहीं हैं।

● **ब्रजेश साहू**

आप और कांग्रेस में तालमेल नहीं

दिल्ली में इंडिया गठबंधन का दूसरा बड़ा संकट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आपसी तालमेल का ना होना है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ साल पहले तक कांग्रेस के ही खिलाफ सड़कों पर उतरते रहे हैं, जिसे कांग्रेसी कार्यकर्ता अब तक भुला नहीं पाए हैं। दिलों की यह दूरी इतनी है कि जमीनी स्तर पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं का मन नहीं मिल पा रहा है। प्रत्याशियों और नेताओं के बीच भी कोई सामंजस्य नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता उदित राज जरूर संजय सिंह से मिल आए हैं। लेकिन इसका असर जमीनी स्तर पर प्रचार अभियान में नहीं दिख रहा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता ही नहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी उदास हैं। इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। जिन चार सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, वहां सिर्फ उसके ही कार्यकर्ता सक्रिय हैं, जबकि कांग्रेसी हिस्से वाली दो सीटों पर आपसी खींचतान ही जारी है। ऐसे में एक-दूसरे दलों के समर्थकों का वोट दोनों दल के कार्यकर्ता किस तरह अपने पक्ष में शिफ्ट करा पाएंगे, इसकी ना तो ठोस रणनीति नजर आ रही है और ना ही आपसी तालमेल। ऐसे दिल्ली के दंगल में इंडिया गठबंधन की सफलता संदिग्ध मानी जा रही है। कह सकते हैं कि आपसी तालमेल की कमी, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के दिल ना मिलने से दिल्ली में इंडिया गठबंधन के लिए पनघट की डगर कठिन नजर आ रही है।

लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए दावों और वादों का पिटारा खुल गया है। जितने उम्मीदवार, उतने वादे। जितने दल, उतने दावे। इन वादों और दावों की अंधी गलियों में आम आदमी खो सा गया है। आम आदमी से जुड़े रोटी, कपड़ा, रोजगार, मकान, पढ़ाई और दवाई के मुद्दे बात-बहस में तो बढ़-चढ़कर बोले जा रहे हैं लेकिन तलाशने पर वैसे ही गायब हैं जैसे चील के घोंसले से मांस।

गरीबी हटाओ बनाम गरीबी हटाओ

भाजपा के संकल्प पत्र में कई वाद

भाजपा ने अयोध्या में राममंदिर निर्माण, जम्मू-कश्मीर से धारा 35ए और 370 हटाने, आयुष्मान भारत योजना जैसे वादों को पूरा किया है लेकिन, प्रत्येक परिवार के लिए पक्का मकान, छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन, छोटे किसानों के लिए पेंशन किसानों की दोगुनी आय, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार अभी भी दूर की कौड़ी साबित हो रहे हैं। यहां यह कहना गलत न होगा कि दस साल के शासनकाल में भाजपा अपने संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए संकल्पित दिखी। कई वादों पर भाजपा ने गंभीरता से काम किया है। समान नागरिक संहिता की दिशा में भी पर्याप्त प्रगति हुई है। वादे के अनुरूप भाजपा के काम करने का उत्साह सहज ही देखा जा सकता है। कांग्रेस भी विधानसभा चुनावों में जिन राज्यों में सत्ता में आई, वहां घोषणापत्र को अमलीजामा पहनाने के लिए प्रयासरत दिखी। 2014 से कांग्रेस केंद्रीय सत्ता से दूर है, ऐसे में कहना मुश्किल है कि कांग्रेस अगर केंद्र की सत्ता में आती है, तो अपने घोषणापत्र को जमीन पर उतारने में सफल रहती, या उसके सिर्फ वादे ही रह जाते हैं। अब देखना है कि 2024 लोकसभा चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है।

राजनीतिक दलों की ओर से घोषणाओं की प्रतिस्पर्धा चालू है। कोई घी दूध की नदियां बहाने का सपना परोस रहा है, तो कोई पलक झपकते चांद-सूरज मुट्ठी में कर लेने का पासा फेंक रहा है। संख्या बल के हिसाब से जो दल न तीन में है न तेरह में वे तो घोषणाओं के मामले में स्थापित दलों से कई गज आगे कूद रहे हैं। मिनटों में हथेली पर सरसों उगा लेने जैसे असंख्य नुस्खों के साथ वे जनता को भरमाने में जुटे हुए हैं। आप चाहे मोदी की गारंटी कहें, न्याय पत्र कहें, संकल्प पत्र कहें, विजन डॉक्यूमेंट कहें या फिर घोषणापत्र, बात एक ही है कि किसी तरह जनता को सपनों की दुनिया में ले जाकर उनके कीमती वोटों की फसल काटना। इस सपनीली दुनिया की माया भी है, और राम भी। गेहूं भी है, और गुलाब भी। निर्भर जनता पर करता है कि उसकी रूचि किसमें है, लौकिक जीवन के सुख में, या पारलौकिक दुनिया में सब कुछ पा लेने की उम्मीद भरे संतोष में।

कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे के घोषणा पत्रों को जुमलेबाजी कहा है। राहुल गांधी का यह जुमला बहुत चर्चित हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि वह एक झटके से गरीबी दूर कर देंगे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के खाते में डायरेक्ट एक लाख रुपया डालकर एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। उनके खातों में हर महीने साढ़े आठ हजार रुपया खटाखट डालेंगे। भाजपा ने कांग्रेस के गरीब परिवारों को एक-एक लाख रुपए देने के चुनावी वायदे को जुमला कहा है, तो कांग्रेस ने भाजपा के संकल्प पत्र में देशभर में बिजली फ्री देने को जुमला और फ्रीबीस (मुफ्त में रेवड़ियां बांटना) कहा है। हालांकि दोनों में कुछ फर्क है, कांग्रेस ने कहा है कि वह सरकारी खजाने से गरीब परिवारों के खाते में हर साल एक लाख रुपया डालेगी। जबकि भाजपा ने कहा है कि वह हर घर सोलर पैनल योजना शुरू करेगी, सोलर पैनल लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देगी, उसके बाद जो बिजली का उत्पादन होगा, वह एक तरह से फ्री होगा। सरकार सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बिजली फ्री नहीं देने वाली। मोदी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि एक करोड़ लोगों ने सोलर पैनल के लिए फार्म भर भी दिया है।

सरकार का मानना है कि ग्रामीण व्यक्ति अगर खुद पर 26 रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं है, और शहरी व्यक्ति अगर खुद पर 32 रुपए खर्च करने की स्थिति में नहीं है तो वह गरीबी रेखा के नीचे है। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। जिसमें कहा गया है कि 2015-16 से 2019-21 के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। मोदी सरकार बनने के बाद 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक देश की 24.85 प्रतिशत आबादी बहुआयामी गरीब थी, जो 2019-21 के आंकड़ों में 14.96 प्रतिशत पर आ गई। 2021 के इन आंकड़ों के अनुसार देश के 26 करोड़ 97 लाख 83 हजार लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे थे।

मोदी सरकार के आखिरी शीतकालीन सत्र

मौन मतदाताओं ने बढ़ाई राजनीतिक दलों की परेशानी

मतदाता जब चुप होता है तो उसके मन की थाह लगाना आसान नहीं होता। सोशल मीडिया के मंचों को छोड़ दें तो आज का मतदाता दशक-डेढ़ दशक के मतदाताओं की तुलना में कहीं ज्यादा सयाना हो चुका है। ज्यादातर मतदाताओं की राजनीतिक दलों को लेकर अपनी पसंद और नापसंद है। चूंकि उसके पास अब सूचनाओं और जानकारी के कई संसाधन मौजूद हैं, लिहाजा वह पहले के वोटरों की तुलना में जानकारियों से कहीं ज्यादा लैस है। आज तकरीबन सबके हाथ में मोबाइल के रूप में जादुई बक्सा आ गया है, जिसके जरिए मनोरंजन और सूचनाओं की अबाध बारिश हो रही है, इसलिए आज का मतदाता पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सूचनाओं से लैस है। हां, एक खतरा जरूर है कि सोशल मीडिया माध्यमों के जरिए फेक न्यूज और जानकारियां भी आ रही हैं, इसलिए कुछ मतदाताओं की सोच इसकी वजह से भी प्रभावित है। लेकिन मोटे तौर पर कह सकते हैं कि आज का मतदाता पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जागरुक हो गया है, इसलिए वह कहीं ज्यादा सचेत भी है। वैसे जब भारत में साक्षरता कम थी, तब भी मतदाता बेहद जागरूक था। इसका उदाहरण है, 1967 का चुनाव। तब तक देश में विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते थे। तब मतपत्र पेटियों में डाला जाता था। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की मतपेटियां साथ-साथ रखी जाती थीं।

में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस समय 21.9 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है। इसका मतलब है कि पिछले दस सालों में 18.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। मोदी सरकार ने यह काम विभिन्न छोटे-छोटे धंधों के लिए बिना गारंटी बैंक लोन की व्यवस्था करवाकर सफलतापूर्वक किया है। ऐसे छोटे-छोटे बैंक कर्ज में सरकार ने ब्याज में सब्सिडी जैसी योजनाएं लागू की। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के जरिए भी लोगों का जीवन स्तर सुधारने की कोशिश की। सैद्धांतिक सवाल यह है कि लोगों का जीवन स्तर सुधारने और किसी भी नई योजना को जमीन तक पहुंचाने के लिए सब्सिडी दिया जाना ठीक है, या टैक्स से हासिल किए गए पैसे का इस्तेमाल राष्ट्र के विकास में खर्च करने की बजाय अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए सीधे लोगों के खाते में डाल देना चाहिए। इस मामले में न कांग्रेस दूध की धुली है, न भाजपा दूध की धुली है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र (जिसे उसने संकल्प पत्र कहा है) में फ्री बिजली का वैसा वायदा नहीं किया, जैसा कांग्रेस कह रही है, लेकिन किसानों के खाते में 2000 रुपए महीना डालने वाली योजना तो मोदी सरकार पहले से चला रही है।

80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का दावा और अगले पांच साल तक जारी रखने का वादा भी भाजपा कर रही है। इसी तरह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को हर साल एक लाख रुपया उनके खातों में डालने का वादा कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी किया गया है। अगर इस तरह फ्रीबीस से गरीबी दूर की जा सकती है, तो यह फॉर्मूला कांग्रेस ने मनमोहन सिंह की सरकार के समय क्यों इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन यह वास्तव में ही एक जुमला है। हैरानी है कि कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र बनाने वाले पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री रहे हैं। क्या उन्होंने चुनाव घोषणा पत्र में यह जुमला लिखने से पहले सरकारी बजट पर गौर नहीं किया। संसद के शीत सत्र में दिए गए आंकड़ों को ही सही मान लें, तो 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, हम 6 करोड़ परिवार मान सकते हैं।

6 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष एक लाख रुपया महीना देने से सरकार को प्रति वर्ष 60 खरब (6 ट्रिलियन) रुपए खर्च करने होंगे। केंद्र सरकार का पिछले साल का कुल खर्चा 45,03,097 करोड़ था। तो राहुल गांधी क्या विदेशी मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडार को बेचकर पैसा खर्च करेंगे या दुनियाभर से कर्ज लेकर भारत को एक झटके में कंगाल कर देंगे। शायद कांग्रेस और उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी को पता है कि वे सत्ता में आने से रहे, इसलिए रेवड़ियों के जुमले बांटने में क्या जाता है।

राहुल गांधी जिस डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, शायद वह भूल गए कि गरीब कल्याण की सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीबों के खातों में ट्रांसफर करने का करिश्मा नरेंद्र मोदी सरकार ने ही किया है। उनके पिता राजीव गांधी ने तो 35 साल पहले कहा था कि केंद्र से एक रुपया भेजते हैं, तो नीचे 15 पैसा पहुंचता है। यानी कांग्रेस को 35 साल पहले सरकारी और राजनीतिक भ्रष्टाचार की पक्की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने की कोई कोशिश नहीं की। अलबत्ता कांग्रेस की सरकार ने 2008 में जब नरेगा (बाद में मनरेगा) योजना शुरू की, तो उसमें भी कमीशनखोरी और फर्जी इनरोलमेंट शुरू हो गई थी। जब तक नरेंद्र मोदी ने जनधन खाते नहीं खुलवाए और डायरेक्ट बेनिफिट शुरू नहीं किया, तब तक ऊपर से लेकर निचले स्तर तक भ्रष्टाचार हो रहा था। इसीलिए अमित शाह ने राहुल गांधी की खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि यही जुमला उनकी दादी इंदिरा गांधी ने और बाद में उनके पिता राजीव गांधी ने भी बोला था।

बहरहाल, 18वीं लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव के नए घोषणापत्र पर आम और खास सभी की नजरें टिकी हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र का नाम न्याय पत्र दिया है। इसके नाम के पीछे तर्क है, न्याय पत्र आम लोगों को न्याय दिलाएगा। कांग्रेस के न्याय पत्र में पांच न्याय और 25 गारंटी हैं। पांच न्याय हैं- हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय। कांग्रेस के घोषणापत्र में सभी वर्गों के लिए रेवड़ियां हैं। इसमें 30 लाख नौकरियां, गरीब परिवार की महिलाओं को एक लाख रुपए सालाना, राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना, एमएसपी को कानूनी दर्जा, मनरेगा मजदूरी को प्रतिदिन 400 रुपए किया जाना, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकना, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाना और पीएमएलए कानून में बदलाव किया जाना शामिल हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के न्याय पत्र के जवाब में सत्ताधारी दल भाजपा ने भी मोदी की गारंटी शीर्षक से अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में 10 सामाजिक समूहों के लिए वादों पर खूब जोर है। यह समूह है गरीब, मध्यम वर्ग, महिलाएं, युवा, वरिष्ठ नागरिक, किसान, मछुआरे, मजदूर, व्यापारी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे पारंपरिक रूप से वंचित वर्ग।

● **विपिन कंधारी**

18वीं लोकसभा की 180 सीटों पर 2 चरण में मतदान संपन्न हो चुके हैं। लेकिन अभी तक चुनाव में मुद्दों की बात नहीं हुई है। इस चुनाव में सिर्फ आरोप-प्रत्यारोप सुनने को मिल रहे हैं। हालांकि भाजपा और कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने अपने घोषणापत्र में वादों की बौछार कर दी है। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान जनता के मन की बात नहीं कही जा रही है। हर मंच से केवल एक-दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि दो चरणों में मतदाता घरों से निकलने में हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में पार्टियों के साथ ही प्रत्याशी भी परेशान हैं।

मुद्दाविहीन चुनाव

18वीं लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह अपनी पार्टी भाजपा के लिए धुंआधार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं ने चुनावों की घोषणा से एक महीना पहले ही लगभग सारे देश का एक-एक बार भ्रमण कर लिया था। दोनों नेता भाजपा सरकार की उपलब्धियां और कार्यक्रम गिनाने के साथ-साथ विपक्ष पर कड़े हमले भी कर रहे थे। इन दोनों के हमलों का मुख्य टारगेट राहुल गांधी थे। किसी अन्य नेता का नाम या जिक्र तो दोनों यदा कदा ही करते थे।

ईडी-सीबीआई ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में डाल दिया, तो दोनों की पत्नियां विपक्ष की नुमाईशी नेता बन गईं। कांग्रेस का चुनाव घोषणापत्र आने के बाद नरेंद्र मोदी ने लीक से हटकर कांग्रेस पर पहला हमला तब किया, जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। मोदी ने न कांग्रेस पर चोट की थी, न मुस्लिम लीग पर चोट की थी और न ही मुसलमानों पर चोट की थी। उन्होंने अपने कोर हिंदू वोट बैंक को बताया था कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के बारे में ही सोचती है, इसलिए हिंदुओं को उससे सावधान रहने की जरूरत है। अपने चुनाव घोषणापत्र को कांग्रेस ने न्याय पत्र का नाम दिया है। जिसमें पांच न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बिहार के नवादा में, फिर उप्र के सहारनपुर में और राजस्थान की पुष्कर रैली में कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कहा। उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र के आधे हिस्से में मुस्लिम लीग की छाप है, तो बाकी के आधे पर वामपंथियों का प्रभाव है।

कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में तीन ऐसे वादे किए थे, जो आजादी से पहले 1936 के मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में भी थे, उन्हीं तीन मुद्दों के कारण भारत का विभाजन हुआ था। तब गांधी, नेहरू, पटेल की कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के वे तीनों मुद्दे ठुकरा दिए थे। पहला मुद्दा था- मुस्लिम पर्सनल लॉ की गारंटी, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा करती है। दूसरा, 1936 के मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र में कहा गया था कि वह बहुसंख्यकवाद के खिलाफ लड़ेगी। इसका मतलब था कि मुस्लिम लीग हिंदुत्ववाद

दक्षिण में भाजपा की उम्मीदें मोदी मैजिक के भरोसे

प्रधानमंत्री मोदी ने जब 18वीं लोकसभा में अपने अंतिम संबोधन में भाजपा के लिए 370 सीटें और एनडीए के लिए 400 सीटों का जिक्र किया तो प्रधानमंत्री को इस बात का एहसास था कि उनके लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए वह 370 सीटों का जो टारगेट सेट कर रहे है वह दक्षिण के राज्यों के समर्थन के बिना संभव नहीं है। दक्षिण से आने वाले राज्यो में शामिल कर्नाटक से 28, आंध्र पदेश से 25, तेलंगाना से 17, तमिलनाडु से 39, केरल से 20 और एक सीट वाले पुडुचेरी में कुल मिलाकर लोकसभा की 130 सीटें आती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी इन 130 सीटों में से 29 सीटें ही जीत पाई थी। उसमें भी 25 सीटें अकेले कर्नाटक और चार सीटें तेलंगाना से मिली थी। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी मिलाकर 85 लोकसभा सीटों में से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी। भाजपा उत्तर भारत में अपने प्रदर्शन के शीर्ष पर है और अपने आंकड़ों को बढ़ाने के लिए इस बार भाजपा दक्षिण में अपने प्रदर्शन पर निर्भर है। इसलिए भाजपा ने दक्षिण की 130 सीटों में से 50 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भाजपा की रणनीति लंबे समय से दक्षिण को फतह करने की रही है, परंतु दक्षिण की हिंदुत्व विरोधी राजनीतिक संस्कृति में पले बढ़े मतदाताओं के बीच उसकी यह इच्छा मोटे तौर पर अधूरी ही रहती आई है।

के खिलाफ लड़ेगी। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत में बहुसंख्यकवाद के लिए कोई जगह नहीं। तीसरा, 1936 के मुस्लिम लीग के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था कि मुसलमान छात्रों के लिए खास छात्रवृति और नौकरियों के लिए संघर्ष करेंगे। कांग्रेस के 2024 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है कि मुस्लिम छात्रों को विदेशों में पढ़ाई के लिए छात्रवृति की व्यवस्था की जाएगी और नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। हो सकता है कि यह एक संयोग हो, लेकिन इससे यह तो साबित हो गया कि कांग्रेस की रिसर्च टीम कितनी कमजोर है, और भाजपा की रिसर्च टीम कितनी तेजतर्रार है, जिसने कांग्रेस का घोषणापत्र आते ही मुस्लिम लीग का 88 साल पुराना चुनाव घोषणापत्र खोज निकाला।

अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का नारा लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिन्होंने कई बार दावा किया कि केंद्र सरकार की रसोई गैस उज्ज्वला योजना, हर घर शौचालय, और प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम महिलाओं को हुआ। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं का दिल जीतने के लिए उन्होंने तीन तलाक की प्रथा पर कानून बनाकर रोक लगाई। उन्होंने युवा मुस्लिमों का दिल जीतने के लिए कई योजनाएं भी शुरू कीं, जैसे मुस्लिम छात्र-छात्राओं को फ्री कोचिंग के लिए उड़ान योजना, ग्रेजुएशन करने वाली मुस्लिम लड़कियों को शादी के मौके पर केंद्र सरकार की ओर से 51000 रुपए की शगुन योजना, मुस्लिम कारीगरों को परंपरागत कला और हस्तकला की ट्रेनिंग योजना, हुनर हाट, मुस्लिम युवाओं के लिए सीखो और कमाओ योजना, 5 करोड़ मुस्लिम छात्र-छात्राओं के लिए प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना, हज पर जाने वाले मुसलमानों की संख्या बढ़ाना। यानी मुसलमानों का दिल जीतने के लिए मोदी ने कोई कोरकसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन देशभर के दौरों में मिले फीडबैक से उन्हें विश्वास हो गया है कि मुस्लिम वोट एकतरफा कांग्रेस और इंडी एलायंस के घटक दलों के साथ जा रहा है, मुस्लिम वोट में सेंधमारी के उनके सारे प्रयास विफल हो गए हैं।

इसलिए कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र को आधार बनाकर उन्होंने अपने कोर हिंदू वोटबैंक को सुरक्षित करने के लिए अपने तेवरों को बदलना शुरू किया। कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र के तीन मुद्दों मुस्लिम पर्सनल लॉ की गारंटी, बहुसंख्यकवाद का खात्मा और नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण ने उन्हें अपने तेवर बदलने का मौका दे दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद के खिलाफ जंग की घोषणा ने सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा निवारण विधेयक की याद ताजा कर दी। यूपीए शासनकाल में सोनिया गांधी की राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया था, जिसे मनमोहन सरकार संसद से पास करवाकर क़ानून बनाना चाहती थी। बिल का वह प्रारूप अल्पसंख्यकों को तो सुरक्षा प्रदान करता था, लेकिन अल्पसंख्यकों की सांप्रदायिक हिंसा से पीड़ित बहुसंख्यकों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता था। बहुसंख्यकों को अपनी बेगुनाही का सबूत देना पड़ता।

यह बिल अगर कानून बन जाता तो मुसलमानों के हाथ में हिंदुओं के खिलाफ बड़ा हथियार साबित होता। भाजपा, शिवसेना, अन्नाद्रमुक, तृणमूल कांग्रेस ने मिलकर बिल का विरोध किया, जिस कारण मनमोहन सरकार इसे पास नहीं करवा सकी। संभवत कांग्रेस घोषणापत्र में उसी बिल को पास करवाने का इशारा किया गया है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र को मुस्लिम लीग का चुनाव घोषणा पत्र कहा। कांग्रेस का घोषणापत्र भले ही मुस्लिम लीग का 1936 का चुनाव घोषणा पत्र देखकर न बनाया गया हो, कुछ हिस्सा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को देखकर जरूर बनाया गया है। 2005 में मनमोहन सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसे मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक स्थिति का अध्ययन करके उनकी हालत सुधारने के लिए सिफारिशें करने को कहा गया था।

सच्चर कमेटी ने अपनी सिफारिशों में मुसलमानों को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। मुसलमानों को आरक्षण कांग्रेस और कम्युनिस्टों के एजेंडे पर हमेशा से रहा है। सच्चर कमेटी और बाद में कांग्रेस के नेता रहे पूर्व चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा आयोग की दूसरी सिफारिश हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम या ईसाई बने दलितों या आदिवासियों को भी आरक्षण देने की थी, जबकि भाजपा धर्मांतरण करने वालों को आरक्षण के लाभ से वंचित करने की समर्थक है। भाजपा का तक्र संविधान सभा में हुई बहस पर आधारित है, जहां संविधान सभा ने धर्म आधारित आरक्षण को ठुकरा दिया था।

● **इन्द्र कुमार**

राहुल गांधी के सलाहकारों ने दूर कर दी मोदी की चिंता

चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर आ गया है, पहले चरण की वोटिंग के बाद यह धारणा बननी शुरू हो गई थी कि दक्षिण में भाजपा का मामला कुछ बन नहीं रहा और हिंदी बेल्ट में कमजोर पड़ रही है। इस धारणा के दो कारण सामने आए हैं, पहला कारण यह कि 2014 और 2019 में भाजपा हिंदुओं के वोटों को एकजुट करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी के जाति आधारित जनगणना के एजेंडे ने हिंदुओं में फिर से फूट डाल दी है। पहले चरण की वोटिंग से यह संकेत निकला कि हिंदी बेल्ट में 2014 से पहले की तरह जाति आधारित वोटिंग हो रही है। कांग्रेस दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के दिमाग में यह बात डालने में कामयाब होती दिखाई दी कि वह जाति आधारित जनगणना करवाकर उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण देगी, जो अब तक नहीं हुआ है। आम धारणा है कि देश में आधी से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, दलित और आदिवासी उनके अलावा है। कांग्रेस जाति आधारित जनगणना करवाकर उसके आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में रखने का वादा कर रही है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में लगी 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को बढ़वाया जा सके। दूसरा कारण वोट प्रतिशत का गिरना है, पिछले दो चुनावों में वोट प्रतिशत बढ़ रहा था, तो भाजपा की सीटें भी बढ़ रही थीं। हालांकि यह कोई पक्का आधार नहीं है कि वोट प्रतिशत गिरने से भाजपा की सीटें घटेंगी ही, लेकिन पिछले ट्रेंड को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी खुद आशंकित हो गए हैं।

बसपा फेल, कांग्रेस से फाइट

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में जमकर पसीना बहा रही हैं। सत्तारूढ़ भाजपा को उम्मीद है कि वह लगातार तीसरी बार दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने जा रही है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हर संभव कोशिश में लगा हुआ है। दरअसल राज्य में बसपा फेल हो गई है। इसलिए भाजपा और कांग्रेस के बीच फाइट है। कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ फॉर्मूले के दम पर लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार कांग्रेस की सरकार में हुई किसान कर्जमाफी योजना को पूरे देश में लागू करना चाहती है। यह कांग्रेस के एक बड़े दांव के रूप में देखा जा रहा है। बस्तर की धरती से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस संबंध में ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि साल 2018 में छत्तीसगढ़ में जब हमारी सरकार बनी तो हमने प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया था। उनसे समर्थन मूल्य पर धान खरीदा था। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, तो यही योजना देशभर में लागू करेंगे। किसानों का कर्जा माफ करेंगे। महिलाओं को सलाना एक लाख रुपए और युवाओं को रोजगार देंगे। अग्निपथ योजना बंद करेंगे। युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देंगे। इन्हीं वादों के सहारे कांग्रेस देश में लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर कब्जा करना चाहती है।

दूसरी ओर विधानसभा चुनाव 2023 में मिली शानदार जीत से भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ भाजपा के सुस्त रफ्तार के बाद भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के सीनियर नेताओं ने जिस तरह से विधानसभा चुनाव 2023 में छत्तीसगढ़ का मोर्चा संभाला था। प्रदेश में धुआंधार प्रचार किया था। ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव 2024 में भी भाजपा यही क्रम दोहराना चाहती है। केंद्रीय नेतृत्व के नेता लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं। भाजपा के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इसलिए भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से पहले ही एक ही चरण में 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया था, जबकि कांग्रेस ने उसके बाद तीन बार में लिस्ट जारी की है।

विधानसभा चुनावों की तर्ज पर भाजपा इस बार भी भ्रष्टाचार के मुद्दों को कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने की शुरुआत कर चुकी है। महादेव सट्टा ऐप का जिन्न फिर से बाहर आ गया है। आर्थिक अपराध शाखा की एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल का नाम आने के बाद भाजपा उन्हें घेरने में लगी है। कांग्रेस को महंगाई समेत अन्य मुद्दों का सहारा है। पार्टी किसानों की दयनीय स्थिति और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी भाजपा पर निशाना साध रही है। भाजपा के पिछले महीनों का राज भी कांग्रेस के लिए एक मुद्दा है, हालांकि लोकसभा चुनाव में पिछले दो बार की तरह इस बार भी भाजपा को प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का ही बड़ा सहारा है। प्रचार-प्रसार के मामले में भी भाजपा कांग्रेस से आगे चल रही है। भाजपा चुनाव प्रभारी नितिन नबीन मोर्चा संभाले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में तो राजनाथ सिंह दंतेवाड़ा और बालोद, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह खैरागढ़ जिले में चुनावी सभा कर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ही बस्तर में चुनावी सभा हुई है। भाजपा के केंद्रीय और स्थानीय नेता प्रदेश की सभी 11 की 11 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश में पूरी तरह से कांग्रेस का सफाया करने पर तूली हुई है। विगत दो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की 11 में से 1 और 2 सीटें कब्जे में रही हैं। लोकसभा चुनाव 2014 में दुर्ग से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू चुनाव जीते थे बाकी 10 सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी थी। लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस ने बस्तर और कोरबा का किला जीता था। बस्तर से दीपक बैज, तो कोरबा से पूर्व केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत जीती थीं।

इस बार भाजपा पूरी तरह से मैदान खाली करवाना चाहती है। सभी 11 की 11 सीटों पर कब्जा करना चाहती है। वह फुल कॉफिडेंस में है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के रूप में सचिन पायलट छत्तीसगढ़ किले में मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस अपने ही अंदर भितरघात से जूझ रही है। पार्टी में सिर फुटौवल का सिलसिला जारी है। समय-समय पर लेटरबाजी कर पार्टी में बम फोड़ रहे हैं। इस बम के आवाज की गूंज उनके दिल्ली हाईकमान तक गूंज रही है। पार्टी इससे परेशान हैं और इसे फौरीतौर पर सुलझाने में ही लगी हुई है। तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चुनाव से पहले नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने का दौर भी चल रहा है। दूसरी ओर पार्टी सख्त कदम उठाते हुए चुनाव छोड़ ऐसे नेताओं को बर्खास्त करने और अनुशासन का पाठ पढ़ाने में भी लगी हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ता एक-दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। बयानबाजी कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने ही मंच से अपनी भड़ास सुनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस हाईकमान तक लेटर लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री की शिकायत कर रहे हैं। भूपेश राज के कामकाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का कहना है कि हम भाजपा की तरह 400 प्लस सीटें जीतने का दावा नहीं करते हैं पर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 3 से 4 सीटें जीतने का पूरा प्रयास जरूर करेंगे।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

भाजपा लगातार कर रही अच्छा प्रदर्शन

2000 में छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद संपन्न हुए चार लोकसभा चुनावों में यहां की 11 लोकसभा सीटों पर हमेशा भाजपा का ही पलड़ा भारी रहा है। 2004, 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस हारती रही, या उसे एकाध सीटें ही मिलीं। लगातार 15 वर्षों तक भाजपा इस राज्य से 10 सांसदों को भेजने में कामयाब रही। इन चार चुनावों में कांग्रेस के कई दिग्गजों को मुंह की खानी पड़ी। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी, श्यामाचरण शुक्ल, पिछली सरकार में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत और बस्तर टाइगर कहे जाने वाले दिवंगत महेंद्र कर्मा शामिल रहे। पहले लोकसभा चुनाव यानी 2004 में सिर्फ अजित जोगी ही कांग्रेस से जीत पाए थे। तब भाजपा में शामिल हुए विद्याचरण शुक्ल की महासमुंद सीट पर जोगी के हाथों हार हुई थी। उसके बाद विद्याचरण दोबारा कांग्रेस में चले गए। कर्मा और विद्याचरण 25 मई 2013 को दरभा घाटी में हुए नक्सली हमले में मारे गए। भाजपा की हैट्रिक पर 15 वर्षों बाद जाकर रोक लगी जब 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दो सीटें पाने में सफल रही।

मराठी अस्मिता की लड़ाई

महाराष्ट्र में शिवसेना और राकांपा में बड़ी टूट से लोकसभा चुनावों में लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इसे मराठी अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि मराठी अस्मिता पर चोट भाजपा खेमे को भारी पड़ सकती है। महाराष्ट्र इस मायने में क्लासिक केस है कि कैसे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी जोड़-तोड़, तोड़फोड़ और पाला बदल के सहारे अपना दबदबा कायम रख रही है। दबदबे की यह पटकथा जून 2022 के आखिरी हफ्ते में लिखी गई। उस दिन मुंबई में काले बादल छाए हुए थे, लेकिन उन्हें बरसने की कोई जल्दी नहीं थी। बल्कि उससे ज्यादा जल्दबाजी और हड़बड़ी तो सियासी आसमान में दिख रही थी। उस दिन पटकथा के मुख्य किरदार 58 वर्षीय एकनाथ शिंदे थे, जो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उस वक्त वे शिवसेना के बड़े नेता और राज्य की महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार में शहरी मामलों के मंत्री थे। लेकिन देखते ही देखते परिदृश्य बदला और सियासी गणित बिलकुल अलग हो गए। एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया। दोनों के मिलने से राजनीति में हलचल हुई और एकनाथ शिंदे शिवसेना के 40 बागी विधायकों की मदद से राज्य में नई सरकार के मुखिया बन गए।

उनके इस कदम से सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना को हुआ। उनके इस कदम की किरकिरी भी हुई लेकिन सत्ता के आगे ये ताने-उलहाने बहुत कम थे। उन्होंने एक तरह से एमवीए और शिवसेना की कमर तोड़ दी। राजनीतिक विश्लेषक, राजनीति के दिग्गज समझे जाने वाले बड़े नेता, राजनीति की खबर रखने वाले खिलाड़ी सब इस कदम के आगे फेल हो गए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ जैसे प्रश्नों के भंवर में सबको छोड़ शिंदे मुख्यमंत्री होने का आनंद उठा रहे हैं। इसमें भी गजब यह हुआ कि भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने उनके मातहत उपमुख्यमंत्री बनना मंजूर कर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका को असंवैधानिक करार दिया। चुनाव आयोग ने शिंदे के गुट को ही असली शिवसेना के रूप में मान्यता दे दी। अब शिंदे के पास ही पार्टी का नाम और धनुष-बाण चुनाव चिन्ह है। शिवसेना बनाने वाले बाला साहेब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे की शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे या यूबीटी) को जलती हुई मशाल का चुनाव चिन्ह थमा दिया गया। 2023 भी तोड़फोड़ वर्ष ही साबित हुआ। एमवीए के दूसरे बड़े घटक शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) भी टूट की शिकार हुई। शरद पवार के भतीजे अजित पवार अधिकांश विधायकों को लेकर अलग हो गए और सरकार में दूसरे उपमुख्यमंत्री बन गए। इस मामले में भी चुनाव आयोग ने असली पार्टी अजित गुट को माना और घड़ी चुनाव चिन्ह सौंप दिया। पार्टी के संस्थापक शरद पवार की पार्टी अब राकांपा (शरद पवार) हो गई है और उनका चुनाव चिन्ह तुरही या तुतारी बजाता आदमी है। यही नहीं, 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज होते ही कांग्रेस के भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम भाजपा की ओर चले गए। खबर है कि भाजपा बाला साहेब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे को भी अपने पाले में ला रही है। इसी साल यहां विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। लेकिन चुनाव की दिशा तय करने वाले सवाल वही हैं, राकांपा के अजित गुट का क्या होने वाला है? शिंदे की शिवसेना का भाग्य क्या करवट लेगा? क्या शरद पवार के बिना राकांपा और ठाकरे परिवार के बिना शिवसेना कोई मायने रखती है? क्या पवार नए सिरे से अपनी पार्टी जगा पाएंगे या उद्धव ठाकरे अपनी भरी-पूरी सियासी पूंजी वापस पा पाएंगे?

शिवसेना (यूबीटी) ने 17 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं और मुंबई पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए खम ठोक रही है। ठाणे, कल्याण और भिवंडी निर्वाचन क्षेत्र शिंदे गुट के असर वाले हैं। लेकिन उसे उद्धव गुट से यहां कड़ी टक्कर मिलेगी। उद्धव गुट की पूरी कोशिश कल्याण में शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को इस बार हराकर उन्हें सबक सिखाने की है।

दरअसल 2022 के बाद से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से शिंदे शिवसेना-भाजपा गठबंधन में नेताओं की आमद बढ़ती जा रही है। हालांकि अतीत में कई हाई-प्रोफाइल बगावतों से भी शिवसेना को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। 1991 में छगन भुजबल के नेतृत्व में 18 बागी कांग्रेस में शामिल हो गए, जबकि नारायण राणे 1995 में कांग्रेस और बाद में भाजपा में शामिल हो गए। 2005 में राज ठाकरे ने अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली। अब सभी भाजपा के खेमे में पहुंचते जा रहे हैं। भाजपा में आने की खबर के बाद राज ठाकरे एक बार फिर चर्चा में हैं। भाजपा उन्हें मराठी वोट की गोलबंदी के लिए अपने पाले में लाना चाहती है। कहा जा रहा है कि उनके सामने शिंदे शिवसेना में एमएनएस विलय की पेशकश रखी गई है, ताकि शिंदे शिवसेना के साथ भी कोई ठाकरे जुड़ जाए। लेकिन शिवसैनिकों के लिए दादर में पार्टी का मुख्यालय सेना भवन और बांद्रा के कलानगर में मातोश्री में ठाकरे परिवार का निवास न सिर्फ ऐतिहासिक, बल्कि राजनीतिक तीर्थस्थल भी है। ऐसे में क्या राज ठाकरे शिंदे शिवसेना को वह मान्यता दिला पाएंगे?

● **बिन्दु माथुर**

कई सीटों पर मुकाबला दिलचस्प

एमवीए में इस गतिरोध के मद्देनजर कांग्रेस ने सांगली और मुंबई दक्षिण मध्य और भिवंडी सीटों पर दोस्ताना लड़ाई की पेशकश की है। इसका मतलब यह है कि सहयोगी दल इन सीटों पर एक चेहरे के बजाय अपने संबंधित उम्मीदवारों को उतारने के लिए स्वतंत्र होंगे। सबसे दिलचस्प मामला कांग्रेस की परंपरागत सीट सांगली का है, जहां शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा (शरद पवार) की दिलचस्पी भी देखी जा रही है। सांगली कांग्रेस के दिग्गज नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव पाटिल का घरेलू मैदान है। यहां से वसंत दादा 1980 में पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। उनके बाद लगातार यहां से उनकी पत्नी शालिनीताई, बेटे प्रकाशबापू, भतीजे मदन (वसंतराव के चचेरे भाई विष्णुअन्ना के बेटे) या पोते प्रतीक ही चुने जाते रहे थे। लेकिन 2014 में सांगली का यह कांग्रेसी गढ़ नरेंद्र मोदी लहर में टूट गया। भाजपा के संजय काका पाटिल ने 2014 में तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटिल को हरा दिया। 2019 में दोबारा संजय काका ने कांग्रेस की टिकट पर खड़े हुए प्रतीक के भाई विशाल को हरा दिया।

बंद हुई कल्याणकारी योजनाएं

लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में एक सिविल सोसायटी फोरम द्वारा किए गए हालिया सर्वेक्षण में कहा गया है कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं में फेरबदल किया गया है, जिसकी वजह से कई तरह के लाभ मिलने अब बंद हो गए हैं। फोरम ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सहायता के उद्देश्य से चल रहे सरकारी कार्यक्रमों की प्रभावकारिता और पहुंच का आंकलन करने के लिए एक जांच शुरू की और पाया कि कई कमजोर वर्गों को अब आवश्यक सहायता नहीं मिल पा रही है। राजस्थान के 25 संसदीय क्षेत्रों में से 16 क्षेत्रों में 3,968 लोगों पर यह सर्वे किया गया। सर्वे में शामिल लोगों ने बताया कि पिछली सरकार द्वारा प्रदान किए गए पांच में से चार लाभ अब नहीं मिल रहे हैं। नवंबर 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हार गई और उसकी जगह वर्तमान भाजपा सरकार ने ले ली।

राजस्थान में ग्रामीण आबादी के रोजगार के अधिकारों के लिए काम करने वाली एक नागरिक संस्था सूचना एवं रोजगार अधिकार अभियान के राज्य समन्वयक मुकेश गोस्वामी ने दावा किया कि आधे से अधिक उत्तरदाताओं (56 प्रतिशत) ने वर्तमान भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार को उन्हें पहले प्रदान किए गए लाभों को बंद करने के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने दावा किया कि बंद की गई योजनाओं में लगभग 95 लाख लाभार्थियों वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन और लगभग 1.25 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने वाली **चिरंजीवी योजना** शामिल है। इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। गोस्वामी ने कहा, हालांकि मौजूदा राजस्थान सरकार ने कहा है कि कल्याणकारी योजनाओं को निलंबित करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। उत्तरदाताओं ने आरोप लगाया कि 1.1 करोड़ परिवारों के लिए शुरू की गई अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना और रोजगार योजनाओं को निलंबित कर दिया गया है।

बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में सबसे पहले लोगों ने योजनाओं का लाभ न मिलने का मुद्दा उठाया। यहां लगभग 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दावा किया कि उन्हें योजनाओं तक पहुंचने से वंचित कर दिया गया है। भरतपुर और टोंक निर्वाचन क्षेत्रों में भी यह मुद्दा गंभीर था, जहां 86 प्रतिशत लोगों ने लाभ रुकने का दावा किया था। अलवर जैसे निर्वाचन क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत कम प्रभाव पड़ा, जहां 75 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने दावा किया कि उन्हें लाभ मिलना बंद हो गया है। गोस्वामी के अनुसार नागरिक समाज ने सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए सहमत उत्तरदाताओं से केवल तीन प्रश्न पूछने के लिए स्वचालित टेलीफोन प्रणाली तकनीक का उपयोग किया, जिसे इंटरैक्टिव वॉयस प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा, सर्वेक्षण में योजना के लाभ बाधित होने की समस्या की सीमा को मापने की कोशिश की गई, यह पूछा गया कि प्रभावित उत्तरदाताओं ने किसे जिम्मेदार ठहराया, और अंत में आगामी लोकसभा चुनाव में उनकी मतदान प्राथमिकता की जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान इन उत्तरदाताओं की पृष्ठभूमि के बारे में कोई जानकारी एकत्र नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण उन लोकसभा क्षेत्रों में किया गया, जहां आम चुनाव के पहले और दूसरे चरण के दौरान मतदान होना है। लगभग 60 प्रतिशत प्रभावित उत्तरदाताओं ने पिछली सरकार का समर्थन करने का इरादा व्यक्त किया। दरअसल, राजस्थान गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 में राज्य का कर्ज बढ़कर 5,37,013 करोड़ रुपए हो गया है। पंजाब के बाद राजस्थान देश का सबसे ज्यादा कर्ज वाला राज्य है। इस राज्य को कांग्रेस से जीतने के बाद राजस्व कैसे लाया जाए, यह भाजपा सरकार के सामने अरबों डॉलर की चुनौती बनी हुई है। वित्तीय निहितार्थों के अलावा, मंत्रिमंडल की विलंबित घोषणा भाजपा के सामने एक और परीक्षा है। सूत्रों का कहना है कि सबसे बड़ी चुनौतियां गृह और वित्त हैं, क्योंकि यही वो प्रमुख मुद्दे हैं, जिनके दम पर भाजपा ने राजस्थान में वापसी की है। कानून-व्यवस्था से निपटना और घटता राजस्व अभी भी भाजपा के लिए चिंता का विषय है। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेगिस्तानी राज्य के लोगों के लिए कई गारंटी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार सभी समस्याओं से अधिक कुशलता से निपटेगी। हालांकि, राजस्थान में ये गारंटी कैसे पूरी होंगी, क्योंकि सरकार कमजोर वित्तीय प्रबंधन से जूझ रही है, क्या ये सवाल हर जगह पूछा जा रहा है? पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं का क्या होगा? यह एक और सवाल है, जो घूम रहा है। हालांकि, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राजस्थान में कांग्रेस द्वारा शुरू की गई जनकल्याणकारी योजनाएं रद्द नहीं की जाएंगी, लेकिन, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें कैसे लागू किया जाएगा।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

सुविधाओं की कमी से प्रभावित हो रही है बालिकाओं की शिक्षा

हाल ही में राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों के विकास से संबंधित कई अहम निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में लागू होने वाले नवाचारों और नई तकनीकों पर आधारित गतिविधियों से राज्य के ग्रामीण विद्यालयों को जोड़ने में प्राथमिकता पर जोर दिया है, ताकि नई तकनीक पर आधारित कार्यक्रमों से गांव के विद्यार्थी भी लाभांवित हो सकें। दरअसल आज भी राजस्थान के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां शिक्षा का प्रतिशत अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। हालांकि राज्य सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की औसत दर 61.4 प्रतिशत दर्शाया गया है। जिसमें सबसे अधिक गंगानगर के ग्रामीण क्षेत्रों में 66.2 प्रतिशत और सबसे कम प्रतापगढ़ में 53.2 प्रतिशत बताया गया है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रतिशत कम है उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख गांव से स्कूल की दूरी है जिससे सबसे अधिक किशोरियों की शिक्षा प्रभावित होती है। राज्य के अजमेर जिला स्थित धुवालिया नाडा गांव इसका एक उदाहरण है। जिला के रसूलपुरा पंचायत स्थित इस गांव में अनुसूचित जनजाति भील और रैगर समुदाय की बहुलता है।

अकेला क्या कर पाएगा हाथी... ?

जब बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेगी तो बहुत से लोगों ने उन पर आरोप लगाया था कि ऐसा वो भाजपा की मदद करने के लिए कह रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से बसपा ने टिकटों का बंटवारा किया है, उससे उप्र की सीधी लड़ाई त्रिकोणीय संघर्ष बनती हुई दिख रही है। मायावती द्वारा उप्र में टिकटों के बंटवारे पर नजर डालें तो इतना साफ दिखता है कि बसपा की कोशिश वोट काटने के बजाय अपनी जीत का प्रयास करना है। इसलिए टिकट बंटवारे में जाति-धर्म की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। लेकिन टिकट इस तरह से दिया गया है कि पार्टी के सिंबल पर उतरने वाला उम्मीदवार दमदारी से लड़ सके। इसके लिए बसपा ने सपा-कांग्रेस और भाजपा के टिकट बंटवारे का इंतजार किया। पार्टी ने अपने सियासी पांसे को चुनावी चौंसर पर उसी तरह चला है ताकि वह उप्र में लड़ती हुई दिखे। उप्र के जो राजनीतिक हालात हैं उसमें कांग्रेस के बाद बसपा ही वो पार्टी है जिसके सामने जीत-हार से अधिक महत्वपूर्ण है कि वो मैदान में बनी रहे। इस बार बसपा ऐसा करने में कामयाब होती दिख रही है।

बसपा का अपना एक निश्चित वोटबैंक है। उप्र की जाटव जाति पूरी तरह से बसपा के समर्पित वोटर हैं जो लगभग 12 प्रतिशत के आसपास हैं। हालांकि पश्चिमी उप्र में चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी बन जाने के बाद उसके इस वोटबैंक में भी सेंध लगी है। नगीना से खुद चंद्रशेखर मैदान में हैं और सपा भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। पश्चिमी उप्र में जाटव जाति के वोटर बसपा से दूर होकर चंद्रशेखर के पाले में न चले जाएं इसलिए बसपा के उत्तराधिकारी आकाश आनंद खुद नगीना की देखरेख कर रहे हैं। चंद्रशेखर लुटियन जोन में घूमने वाले लिबरल्स के प्रिय पात्र हैं इसलिए उनकी मौजूदगी को मीडिया का एक वर्ग बहुत बढ़ा-चढ़ाकर बताता है। फिर चंद्रशेखर और उनके समर्थक सवर्णों से सीधी लड़ाई की बात करते हैं, इसलिए इस जाति के युवाओं को आकर्षित करते हैं। चंद्रशेखर की बनाई भीम आर्मी का प्रभाव आज पूरे प्रदेश में दिखता है। अंबेडकर जयंती का मौका हो या फिर दूसरी जातियों से झगड़ा झंझट, इस जाति के युवा चंद्रशेखर की भीम आर्मी के बैनर तले ही गोलबंद होते हैं। लेकिन इस गोलबंदी का मतलब यह नहीं है इनकी जाति का वोट चंद्रशेखर के पाले में चला जाएगा। इस जाति के लोगों का हाथी से गहरा लगाव है और मतदान केंद्र पर उसी के सामने वाला बटन दबता है। प्रदेश में यही बसपा की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी है जो कांशीराम और मायावती ने 30 सालों में अर्जित की है। फिर चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अभी राज्यव्यापी नहीं है। इसलिए उसका अगर कुछ प्रभाव है भी तो एक सीमित क्षेत्र में ही है।

ऐसे में बसपा ने इस बार जहां अपने वोटबैंक को तो बचाकर ही रखा है वहीं उसने दूसरी जातियों और मुसलमानों को भी साधने का प्रयास किया है। मसलन, मेरठ की सीट पर जहां भाजपा ने अग्रवाल समाज से आने वाले अरुण गोविल को टिकट दिया तो बसपा ने त्यागी उम्मीदवार पर दांव लगाकर यहां से देवव्रत त्यागी को टिकट दे दिया। इस सीट पर त्यागी मतदाताओं का ठीक-ठाक प्रभाव है और अगर बसपा का त्यागी कार्ड चल गया तो भाजपा उम्मीदवार को जीत के लिए संघर्ष जरूर करना पड़ेगा। इसी तरह जौनपुर से बसपा ने श्रीकला सिंह को टिकट दे दिया है जो कि इस **क्षेत्र में माफिया नेता** कहे जाने वाले धनंजय सिंह की पत्नी हैं। धनंजय सिंह न केवल जौनपुर क्षेत्र में अच्छा खासा राजनीतिक प्रभाव रखते हैं बल्कि वो यहां से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके थे। ऐन मौके पर एक पुराने केस में उनको सजा हो गई और वो जेल में हैं। ऐसे में बसपा ने धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट देकर इस सीट पर अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है। पिछली बार भी यह सीट बसपा ने ही जीती थी। कभी पैसा देकर टिकट बंटवारे के लिए बदनाम रही बसपा ने इस बार टिकट बंटवारे में बहुत सावधानी बरती है। एक ओर जहां मुस्लिम दावेदारों पर दांव लगाया है वहीं दूसरी ओर स्थानीय समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा है। जहां मुस्लिम मतदाता अधिक हैं और उम्मीदवार हिंदू हैं, वहां पार्टी की ओर से मुस्लिम पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं ताकि मुस्लिम वोटर पूरी तरह से सपा कांग्रेस के पाले में न चला जाए।

मुसलमानों से अपील करते हुए मायावती उन्हें भरोसा दिला रही हैं कि सिर्फ बसपा के साथ जाने पर ही मुसलमान भाजपा को हरा पाएंगे क्योंकि बसपा के पास उसका अपना दलित वोटबैंक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मायावती की नजर में सिर्फ दलित या मुस्लिम वोटर ही हैं। ऐसा लगता है कि शायद पहली बार बसपा में टिकट देते समय सिर्फ अपने वोटबैंक और उम्मीदवार के पैसे को ही ध्यान में नहीं रखा गया है। हर एक सीट पर मंथन हुआ है और उस जाति या वर्ग के उम्मीदवार पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसकी सपा-कांग्रेस या फिर भाजपा के द्वारा उपेक्षा की गई है। इसलिए अकेले होने के कारण बसपा प्रदेश में कुछ खास नहीं कर पाएगी, ऐसा समझ बैठना एक प्रकार की भूल होगी। सर्वे भले ही यह बता रहे हों कि बसपा का खाता नहीं खुलेगा लेकिन संभव है कि टिकट बंटवारे में जिस गणित का ध्यान रखा गया है, उसका परिणाम आए और बसपा दो से तीन सीटें जीत भी जाए। अगर वह सीट जीतने में कामयाब नहीं भी होती है तो दूसरे दलों के उम्मीदवारों की हार-जीत का कारण तो बन ही जाएगी। जौनपुर को ही देखें तो धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट देकर बसपा ने भाजपा के ठाकुर उम्मीदवार की परेशानी बढ़ा दी है। इसी तरह मुजफ्फरनगर में जहां भाजपा और सपा ने जाटों पर दांव लगाया है वहीं बसपा ने एक पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को टिकट दे दिया है।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

किसका खेल बिगाड़ेंगी मायावती?

लोकसभा चुनाव में बसपा की भूमिका केवल वोट कटवा से अधिक नहीं दिख रही है। बसपा टिकट अपने मूल कार्यकर्ता को देने की बजाय भाजपा व कांग्रेस के नाराज नेताओं के लिए सुरक्षित रखती है। टिकट भी ऐसे दिए जाते हैं, सुबह सदस्यता लो, दोपहर को हाथी की सवारी के लिए टिकट भी ले जाओ। बिजनौर में भाजपा ने गुज्जर को टिकट दिया और सपा ने सैनी को। उम्मीद की जा रही थी कि बसपा मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दे सकती है। अगर ऐसा होता तो वह सपा कांग्रेस का वोट काटने का काम करता जबकि बसपा ने जाट उम्मीदवार को टिकट दे दिया। इस तरह इस सीट पर जाट, गुज्जर और सैनी की त्रिकोणीय लड़ाई हो गई। आशय यह है कि इस बार बसपा अकेले जरूर है लेकिन न तो वह सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए चुनाव लड़ रही है और न ही उसने किसी दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा के इतिहास में शायद पहली बार एक प्रोफेशनल पार्टी की तरह टिकट बंटवारा किया है। पार्टी के उम्मीदवार भले हार जाएंगे लेकिन उसकी पूरी कोशिश एक पार्टी के तौर पर पुनर्वापसी है। एक ऐसी पार्टी जिसका अपना मजबूत वोटबैंक तो है लेकिन वह बाकी जातियों के साथ तालमेल करके एक बार पुनः प्रदेश में खड़ा होने का दम रखती है।

जाति की जमावट

क्या बिहार में इस बार राजनीतिक दल लोकसभा का चुनाव कुछ अलग तरीके से लड़ रहे हैं। आखिर क्यों पुराने समीकरण इस बार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा पहले के चुनावों में दिखता था। भाजपा की ओर से इस बार बिहार में ऐसा क्या किया गया है कि विपक्षी दल खासकर आरजेडी की ओर से जाति जनगणना पर पहले वाला जोर नहीं दिखाई पड़ रहा। आरजेडी की रणनीति में भी इस बार सिर्फ एम और वाय समीकरण ही नहीं है। बिहार में इस बार पिछड़ा बनाम अगड़ा के व्यापक ढांचे में जाति वैसे शामिल नहीं है जैसा कि हाल तक बिहार में समझा जाता था। जो पैटर्न दिखाई पड़ रहा है उससे ऐसा लगता है कि एक चुनावी क्षेत्र से दूसरे चुनावी क्षेत्र तक जाते-जाते जाति वाला समीकरण कुछ अलग तरीके से चल रहा है।

बिहार में जाति वाले मिथक को तोड़ने का प्रयास भाजपा की ओर से एक दशक पहले ही शुरू हो गया था। पारंपरिक जातिगत आधिपत्य को तोड़ने की क्षमता का एहसास करने वाली भाजपा ने एक दशक पहले व्यक्तिगत समूहों तक अपनी पहुंच शुरू की थी। देखा जाए तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ-साथ भाजपा के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा दोनों कुशवाहों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कुर्मियों को जद(यू) के नीतीश कुमार के माध्यम से एक छतरी के नीचे लाया गया है। एलजेपी (रामविलास) नेता चिराग पासवान के जरिए दुसाध जाति जबकि मुसहरों का प्रतिनिधित्व एनडीए के सहयोगी और बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी कर रहे हैं। लंबे समय से बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी केवल दो समूह मुसलमानों और यादवों के साथ जाती रही है। अब आरजेडी की मजबूरी कहें या उसकी रणनीति जिसके बाद एमवाय समीकरण में बदलाव आया है। बिहार की बदली सियासत को तेजस्वी के इस बयान से भी समझा जा सकता है। तेजस्वी यादव ने कुछ दिनों पहले कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि आरजेडी एमवाय (मुस्लिम-यादव) की पार्टी है। मैं कहता हूं एमवाय के साथ ही आरजेडी बाप की भी पार्टी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बाप का अर्थ है बी से बहुजन, ए से अगड़ा (अगड़ी जाति), ए से आधी आबादी (महिला), और पी से गरीब।

तेजस्वी अब कहते हैं कि हम ए-टू-जेड पार्टी हैं। मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी और मल्लाहों के बीच उसके आधार का इंडिया गठबंधन में प्रवेश एक बोनस है, साथ ही ओबीसी और दलित समर्थन भी है जो राजद की सहयोगी सीपीआई (एमएल) भी है। इन जातीय गणनाओं के बीच चर्चा में आने वाले एकमात्र राष्ट्रीय नेता मोदी हैं। राजद की उम्मीदवार सूची भी उसके नए दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें जाति समूहों के कई नाम शामिल हैं जिन पर भाजपा की नजर है। उदाहरण के लिए, पार्टी जिन 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से चार पर कुशवाहा जाति के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। पहले चरण में राजद के कुशवाहा उम्मीदवार औरंगाबाद में अभय कुमार कुशवाहा और नवादा में श्रवण कुशवाहा हैं। गया से, एक आरक्षित सीट पर राजद ने कुमार सर्वजीत पासवान को मैदान में उतारा है, इस उम्मीद में कि वह कुछ पासवान वोटों को आरजेडी की ओर खीचेंगे और इसे एमवाई समीकरण में जोड़ देंगे। मांझी गया से पिछले तीन लोकसभा चुनाव हारे हैं। इस बार, उन्हें उम्मीद है कि वे भाजपा के पारंपरिक उच्च जाति के वोटों के साथ-साथ अपने मुसहर वोटों और पासवान वोटों का एक बड़ा हिस्सा भी जोड़ लेंगे। माना जाता है कि गया में पासवान और मुसहर दलितों के दो सबसे बड़े समूह हैं, जिनकी लगभग 30 प्रतिशत आबादी है। बिहार की चौथी सीट औरंगाबाद में 19 अप्रैल को मतदान हो गया है, जहां आरजेडी ने लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। पहले भाजपा के लिए आसान सीट के रूप में इसे देखा जा रहा था, उसने अपने तीन बार के सांसद सुशील कुमार सिंह को उतारा है। सुशील सिंह जो कि एक राजपूत हैं वहीं राजद से अभय कुमार कुशवाह हैं। यादवों के अलावा कुशवाहों की भी महत्वपूर्ण उपस्थिति है, हालांकि राजपूत वोटर्स की संख्या अधिक है। पहले चरण के साथ शुरू यह लड़ाई आगे के चरणों में और दिलचस्प होगी।

किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि पहले आम चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा सीटों पर जाति की बहुलता के अनुसार अपने उम्मीदवारों को टिकट दिया। इसके पहले 1926 के लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव के वक्त उनकी टिप्पणी गौर करने लायक है- बिहार के अधिसंख्य राष्ट्रवादी नेता जातिवादी हो गए। चुनाव और जाति के अंतर संबंधों को देखें, तो राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चयन में इसका रंग और गाढ़ा होता गया है। जातियों की राजनीतिक चेतना के अनुसार सत्ता या राजनीति में हिस्सेदारी का सवाल पेंचीदा रहा है। जाति से जमात का दर्शन कब निखालिस जातिवाद में बदल जाए, कहना मुश्किल नहीं। जातियों की खेमेबंदी और सामाजिक समीकरण आज भी राजनीतिक दलों के आधार बने हुए हैं। समाजवादी चिंतक डॉ. राम मनोहर लोहिया जब पिछड़ा पावे सौ में साठ की बात करते हैं, तो इसका अर्थ जाति से जमात की ओर बढ़ना है। पर उसी समय वह आगाह भी करते हैं कि पिछड़ों की अगड़ी जातियां दूसरी अन्य पिछड़ी जातियों की हकमारी कर लेंगी। डॉ. लोहिया की यह आशंका निम्न या छोटी जातियों के राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की ओर थी। पर राजनीति इतनी उदार नहीं हो सकी। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पटना में एक के बाद एक विभिन्न जातियों की सभाएं-रैलियां हुईं। पर उम्मीदवारों की लिस्ट देखने पर पता चलता है कि उनकी हिस्सेदारी न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है।

● **विनोद बक्सरी**

जातियों की खेमेबंदी का गवाह भी रहा बिहार

गौर से देखें तो पता चलता है कि राजनीतिक दल अपने सामाजिक आधार के हिसाब से ही उम्मीदवारों के चयन को प्राथमिकता देते हैं। कुछ अपवाद ऐसे रहे हैं जब संख्या की बहुलता नहीं होने के बावजूद बिहार की जमीन ने उन्हें राजनीति के ऊंचे पायदान पर बिठाया है। कर्पूरी ठाकुर और रामसुंदर दास ऐसे अपवाद रहे हैं। इसके उलट राजनीतिक उठापटक के जरिए जातियों की खेमेबंदी का बिहार गवाह भी रहा है। 1961 में श्रीकृष्ण सिंह के निधन के बाद जातियों की गोलबंदी का एक रूप इतिहास में दर्ज है। भूमिहार विरोधी जातियां विनोदानंद झा के नेतृत्व में एकजुट हुईं। इसका परिणाम यह हुआ कि उस जमाने के बड़े भूमिहार नेता महेश प्रसाद को पराजय का सामना करना पड़ा। इस परिघटना से इतिहास ने करवट ली और बिहार में पहली बार एक ब्राह्मण की मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी हुई। हाल में आई बिहार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार अगड़ी, पिछड़ी, अति पिछड़ी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और मुसलमानों की कुल जातियों की संख्या 215 है। पर लोकसभा के मौजूदा चुनाव में राज्य की 40 सीटों पर केवल 15 जातियों के उम्मीदवार ही उतारे गए हैं। इससे पता चलता है कि जातियों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समायोजन की रफ्तार कितनी धीमी या उपेक्षित है।

पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक सात चरणों में मतदान होना है। 2019 की तरह इस बार भी ममता और मोदी आमने-सामने हैं। ममता बनर्जी 13 साल से बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और वह इसी दबदबे के आधार पर भाजपा की बढ़त को रोकने की हरसंभव कोशिश कर रही हैं। बंगाल का यह चुनाव भाजपा और तृणमूल दोनों पूरी तरह ध्रुवीकरण पर लड़ रही हैं। भाजपा का पूरा फोकस और प्रचार राम मंदिर निर्माण, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), संदेशखाली में महिलाओं के साथ शोषण और प्रदेश में ममता राज में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है। भाजपा को उम्मीद है कि इन सब मुद्दों के दम पर वह 2019 में जीती 18 सीटों से आगे बढ़कर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी।

भाजपा इस लोकसभा चुनाव को 2026 के लिए वार्मअप चुनाव के रूप में भी देख रही है। उधर ममता बनर्जी प्रदेश के मुस्लिम नेताओं को साफ-साफ कह रही हैं कि भाजपा के आते ही सीएए और एनआरसी लागू हो जाएगा और आप लोगों से देश की नागरिकता छीन ली जाएगी। जब तक मैं हूं, आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। तृणमूल कांग्रेस ने इस बार घर-घर बैठक पर चुनाव प्रचार अभियान पर फोकस किया है। ममता के छोटे-छोटे वीडियो हर घर में दिखाए जा रहे हैं जिसमें वह कह रही हैं कि जब तक ममता है, मोदी बंगाल में आ नहीं सकते। ममता बनर्जी जहां मुस्लिम वोटर्स को कांग्रेस और लेफ्ट में जाने से रोकने में कामयाब लग रही हैं, वहीं ममता के मुस्लिम वोटर्स को काउंटर करने के लिए भाजपा एससी-एसटी और हिंदू वोटर्स को अपने पाले में लाने का हरसंभव प्रयास कर रही है। मुस्लिम मतदाता पूरी तरह से ममता के साथ हैं। मुसलमानों को लगता है कि ममता के रहते सीएए और एनआरसी बंगाल में लागू नहीं होगा। ऐसे में मुसलमानों का एकमुश्त वोट ममता को मिलता दिख रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी के पास मुसलमान वोटर के अलावा दो बड़े वोट बैंक भी हैं। महिला और अपर कास्ट बंगाली ब्राह्मण। महिलाएं ममता के लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री योजनाओं से खुश हैं। बंगाली भद्रलोक यानी अपर कास्ट बंगाली ब्राह्मण करीब 3 से 4 प्रतिशत है। बंगाली ब्राह्मण खुद को सेकुलर साबित करने के लिए टीएमसी को वोट देते हैं। यह भद्रलोक प्रोग्रेसिव सोच को मानते हैं और भाजपा की हिंदू राजनीति को पंसद नहीं करते हैं। इनको लगता है कि भाजपा इनके रहन-सहन और संस्कृति को अपने हिंदुत्व एजेंडा से बदल देगी। 2024 के चुनाव में ममता मोदी पर भारी नजर आ रही थी, लेकिन संदेशखाली में महिलाओं के उत्पीड़न ने भाजपा के पक्ष में कुछ हद तक माहौल बना दिया है। जो संदेशखाली महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर पूरे देश में चर्चा में आया वह बशीरहाट लोकसभा सीट में आता है। इसकी सरहद बांग्लादेश से सटी है। इस कारण अवैध घुसपैठ भी एक बड़ा मुद्दा है। बशीरहाट में आखिरी फेज में वोटिंग है। टीएमसी ने विधायक हाजी नरूल इस्लाम को टिकट दिया है। हाजी नरूल इस्लाम 2009 से 2014 तक बशीरहाट से सांसद रहे हैं। बशीरहाट में मुस्लिम आबादी 45 प्रतिशत है।

संदेशखाली एसटी बाहुल्य है। इसलिए भाजपा यहां एससी-एसटी की राजनीति कर रही है। भाजपा की उम्मीदवार रेखा पात्रा अनुसूचित जाति के बागड़ी समुदाय से आती हैं। मोदी कूचबिहार और जलपाईगुडी में रैली कर चुके हैं। दोनों सीटें एससी आरक्षित सीटें हैं। भाजपा यहां पर एससी और एसटी लोगों से कह रही है कि टीएमसी जीत गई तो आपकी जमीन पर फिर कब्जा हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में एससी आबादी 23.51 प्रतिशत है और एसटी आबादी 5.8 प्रतिशत है। पश्चिम बंगाल में एससी के लिए लोकसभा की 8 और विधानसभा में 68 सीटें आरक्षित हैं। बंगाल में भाजपा एससी समुदाय में आने वाले दास, राजबंशी, खान, मंडल, प्रामाणिक, सरदार और पात्रा को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में बागड़ी समुदाय सबसे अधिक है और रेखा पात्रा को आगे कर भाजपा इस समुदाय को भी संदेश देने की कोशिश में है।

बंगाल में संघ भी जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रहा है। इसके साथ ही मोदी की लोकप्रियता के साथ टीएमसी के बड़े नेताओं के भाजपा में आने से भाजपा का आधार मजबूत हुआ है। 2020 में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी छोड़कर भाजपा में आ गए थे। वे अपने साथ बर्धमान के बड़े नेता सुनील मंडल को भी ले आए। शुभेंदु की वजह से भाजपा मेदिनीपुर डिवीजन में मजबूत हो रही है। यहां 9 लोकसभा सीटें हैं। इसके अलावा भाजपा नॉर्थ बंगाल में भी मजबूत नजर आ रही है। नॉर्थ बंगाल की 4 सीटों दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूचबिहार, अलीपुरद्वार के साथ ही मेदिनीवुर डिवीजन की 9 सीटों तमलुक, कांथी, मेदिनीपुर, घाटल, पुरूलिया, बांकुरा, विष्णुपुर, झारग्राम और श्रीरामपुर सीट पर भाजपा को उम्मीद है कि वह इन सीटों पर कब्जा कर लेगी। इसके अलावा बर्धमान डिवीजन की 7 सीटों आसनसोल, बर्धमान दुर्गापुर, बीरभूम, बर्धमान ईस्ट, हुगली, आरामबाग और बोलपुर में भी भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा को 2019 के चुनाव में झारखंड से सटे दक्षिण बंगाल के जंगल महल इलाके और उत्तर बंगाल से फायदा हुआ था। लेकिन ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के साथ ही भाजपा शहरी सीटों पर भी पूरा ध्यान दे रही है।

● **राकेश ग्रोवर**

चुनाव में ममता का सबकुछ दांव पर

बंगाल में ममता के ठुकराने के बाद सीपीएम, कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यह गठबंधन मिलकर कुछ कर सके इसकी संभावना कम ही है। कांग्रेस के नेता अधीर रजंन चौधरी अपनी सीट बहरामपुर पर फंस गए हैं क्योंकि टीएमसी ने यहां से क्रिकेटर युसूफ पठान को उतारा है। ममता खुद बहरामपुर से अधीर रजंन चौधरी की हार तय करने के लिए दो बार इस क्षेत्र का दौरा कर चुकी हैं। कांग्रेस का खाता बंगाल में अधीर रजंन चौधरी ही खोल सकते हैं, बाकी कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन से उम्मीद करना बेकार है। इस बार के चुनाव में ममता का सबकुछ दांव पर है। अगर राज्य में भाजपा बड़ी पार्टी बनने में सफल रहती है तो ममता के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा से लड़ना मुश्किल होगा। पूरी लड़ाई ममता और मोदी के बीच है। ध्रुवीकरण के दो छोर पर खड़े दोनों नेता अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 4 जून को बंगाल के नतीजे हमें बंगाल के भविष्य की कहानी अच्छे से समझाएंगे।

कौन मार रहा आतंकियों को?

पाकिस्तान में वर्षों से सुरक्षित पनाह पाकर भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को संचालित करने वाले आतंकियों की लगातार हत्याएं हो रही हैं। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों और कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट के आधार पर आशंका जाहिर की है कि हो न हो पाकिस्तान में बीते तीन सालों में आतंकियों की जो टार्गेट किलिंग हुई है, उसके पीछे भारत की खुफिया एजंसी रॉ का हाथ हो। ऐसा कहने के पीछे उसके अपने सबूत हैं जो पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों ने उन्हें मुहैया कराए हैं। ब्रिटिश मीडिया के अनुसार अपने स्तर पर भी उन्होंने इन घटनाओं की पड़ताल की है जिसमें पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा बिल्कुल आधारहीन नहीं लगता है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान में रहस्यमय बंदूकधारियों द्वारा की जाने वाली टार्गेट किलिंग का संदेह पहले भी भारत पर होता रहा है। लेकिन यह पहली बार है कि उपलब्ध कागजात इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो टार्गेट किलिंग हुई हैं उसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इस संबंध में पहली बार उसने भारतीय खुफिया अधिकारियों से बात भी की है।

ब्रिटिश मीडिया का दावा और पड़ताल एक ओर, लेकिन उसके इस दावे से पाकिस्तान ही नहीं भारत में भी हलचल तो हुई है। भारत में इस समय आम चुनाव चल रहे हैं और ऐसे समय में अगर यह खबर आती है कि मोदी सरकार पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मार रही है तो इसका सीधा लाभ मोदी को ही होगा। इसीलिए रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने **एक टीवी इंटरव्यू** में यह कहकर रहस्य को और गहरा कर दिया है कि घर में घुसकर मारेंगे। इसी तरह चुनाव प्रचार के दौरान उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हाल ही में ब्रिटेन के एक सम्मानित अखबार ने दावा किया है कि 2020 से लेकर अब तक पाकिस्तान में 20 खतरनाक आतंकवादियों की टार्गेट किलिंग हुई है जिसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है। हम नहीं जानते कि अखबार किस आधार पर यह दावा कर रहा है लेकिन यह नया भारत है जो यह जानता है कि अपने लोगों और अपनी सीमाओं की सुरक्षा कैसे करनी है।

बहरहाल, चुनावी बयान से अलग इस बात की पड़ताल जरूरी है कि क्या भारत ने पाकिस्तान में घुसकर 20 ऐसे आतंकियों को मार गिराया है जो किसी न किसी रूप में भारत में आतंकवाद फैलाने में लिप्त रहे हैं। पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों और दस्तावेजों के हवाले से गार्डियन अखबार का दावा है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों की यह टार्गेट किलिंग पूरी तैयारी के साथ की गई है। शुरुआत में पाकिस्तान के अधिकारियों में भी इस बात को लेकर भ्रम था कि वो अज्ञात बंदूकधारी कौन हैं जो चुन-चुनकर कट्टरपंथी मौलानाओं को शिकार बना रहे हैं। लेकिन फिर जब उन्होंने जांच की तो इसके पीछे भारत का हाथ पाया।

टार्गेट किलिंग पाकिस्तान में आए दिन की बात है। सिंध से लेकर खैबर तक आए दिन कोई न कोई टार्गेट किलिंग का शिकार होता रहता है। कभी कोई हिंदू डॉक्टर इसका शिकार बनता है, कभी कोई सिख, तो कभी आपसी रंजिश के कारण कोई मुल्ला मौलवी या आम शहरी। लूटमार और छिनैती पाकिस्तान का सबसे बड़ा असंगठित कारोबार है इसलिए कई दफा इस लूटमार और छिनैती के चक्कर में भी बाइक सवार अपराधी लोगों पर गोलियां बरसाकर उनकी जान ले लेते हैं। पाकिस्तान के ऐसे माहौल में अगर कुछ ऐसे लोगों की टार्गेट किलिंग हो जाती है जिनको खुद पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट का संरक्षण प्राप्त हो तो सवाल उठता ही है कि आखिर कौन है जो यह कर रहा है? इसके पीछे दो ही संभावना हो सकती है। पहली यह कि कोई बाहरी एलिमेन्ट किसी खास मकसद से इन्हें रास्ते से हटा रहा है और दूसरा यह कि खुद पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आईएसआई ही उन्हें ठिकाने लगा रही हो।

अगर पहली संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता तो दूसरी संभावना को भी खारिज नहीं किया जा सकता। आईएसआई अपने यहां मुल्ला मौलवियों का आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करने और फिर उन्हें रास्ते से हटा देने में माहिर रही है। अफगान तालिबान तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले मौलाना शमीउल हक हों या तहरीक-ए-लब्बैक चलाने वाले खादिम हुसैन रिजवी। एक को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली से मार दिया और दूसरा अचानक हुए रहस्यमय बुखार से आनन-फानन में मर गया।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

पाकिस्तान ने लगाए गंभीर आरोप

इस पूरे मामले में एक बात और गौर करने लायक है कि पाकिस्तानी अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि जो लोग टार्गेट किलिंग करवा रहे हैं उनका बेस यूएई में है। वहीं रहने वाले पाकिस्तानी या अफगानी मुसलमानों को पैसा देकर पाकिस्तान भेजा जा रहा है जो आतंकियों की टार्गेट किलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का यूएई का नाम लेना भारत-यूएई संबंधों में दरार डालने का प्रयास भी हो सकता है। पाकिस्तान से यूएई ने लगभग पूरी तरह से दूरी बना ली है और मोदी कार्यकाल में यूएई भारत संबंध बहुत बेहतर स्थिति में हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि खुद आईएसआई एक ग्रैंड प्लान के तहत एक तीर से दो शिकार कर रही हो। पाकिस्तान अपने इस आरोप से यह भी साबित करने का प्रयास कर सकता है कि कनाडा में सिख अलगाववादी निज्जर की हत्या के पीछे भी भारत का हाथ है, क्योंकि वह अपने दुश्मनों को उन देशों में जाकर मार रहा है, जहां वो छिपे हुए हैं। फिर चाहे वह कनाडा हो या पाकिस्तान। मोदी सरकार में देश के दुश्मनों से निपटने का तरीका बदल गया है। हालांकि जब कनाडा के प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया था उस समय विदेशमंत्री एस जयशंकर ने बहुत सधे हुए शब्दों में कहा था कि भारत ऐसी गैरकानूनी कार्रवाईयों में विश्वास नहीं करता है। बहरहाल, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। खुफिया एजेंसियों की दुनिया में ऐसे खेल चलते रहते हैं। कौन किसके खिलाफ क्या चाल चल रहा है यह उनके अलावा कोई जान नहीं सकता। लेकिन इस प्रकरण में इतना तो हुआ है कि पाकिस्तान से लेकर यूरोप और कनाडा तक जो भारत के दुश्मन हैं वो मारे जा रहे हैं। भारत देश के लिए यही शुभ संकेत है।

अमेरिका, यूरोप के निशाने पर मोदी

भारत की लोकसभा के चुनावों में अमेरिका, यूरोप और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र की दिलचस्पी 2014 के चुनावों से भी ज्यादा है। 2014 में भाजपा की ओर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भारत के विपक्षी नेताओं ने दुनियाभर के मीडिया में उनके खिलाफ अभियान चलाया था। उनके प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद भी यह अभियान चलता रहा है। पिछले कुछ सालों में विपक्ष के प्रमुख नेता राहुल गांधी अपने विदेशी दौरों में मोदी सरकार पर संविधान और लोकतंत्र को कुचलने और अपने विरोधियों के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं के दुरूपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। यहां तक कि भारतीय संसद से पारित कई बिलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी सवाल उठाए जाते रहे। भारत के विपक्ष के उकसावे पर विदेशी मीडिया ने भी नागरिकता संशोधन कानून और कृषि कानूनों की गलत व्याख्या करने से परहेज नहीं किया। कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 हटाए जाने को भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, जिसका पाकिस्तान ने लाभ उठाकर इसे संयुक्त राष्ट्र में उठाया।

राहुल गांधी को जब मानहानि के एक केस में दो साल की सजा हुई और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले और जन प्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई, तो उसकी भी विदेशी मीडिया और विदेशी सरकारों ने गलत व्याख्या की। राहुल गांधी ने देश से बाहर जाकर कहा कि उन्होंने संसद में नरेंद्र मोदी से उद्योगपति गौतम अडानी से उनके रिश्तों पर सवाल पूछे थे, इसलिए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। अमेरिकी सरकार ने तथ्यों की जानकारी लेने के बजाय राहुल गांधी के बयान को ही सच मानकर भारत के लोकतंत्र पर चिंता प्रकट की। यह कहा गया कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई। जबकि कोर्ट के फैसले के कारण ही उनकी सदस्यता गई थी, और कोर्ट के फैसले से ही उनकी सदस्यता बहाल हो गई। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में भी अमेरिका, जर्मनी और संयुक्त राष्ट्र ने अज्ञानता भरा वही रूख अपनाया है। अज्ञानता नहीं, बल्कि जानबूझकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश के तहत प्रतिक्रिया दी गई है। अमेरिका और जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय लोकतंत्र पर चिंता प्रकट की है।

स्वाभाविक है कि यह भारत के आंतरिक मामलों में बेवजह का दखल है, जिस पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने इन दोनों देशों के दूतावास के अधिकारियों को तलब करके न सिर्फ नाराजगी का इजहार किया, बल्कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने की नसीहत भी दी। लेकिन अमेरिका और जर्मनी के बयान राहुल गांधी के पिछले साल ब्रिटेन में दिए गए बयान की तर्ज पर ही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि खुद को लोकतंत्र का झंडाबरदार समझने वाले अमेरिका और यूरोपियन देशों को भारत में लोकतंत्र पर मंडरा रहे खतरे पर आंख मूंदे नहीं रहना चाहिए। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने अमेरिका और ब्रिटेन में दिए भाषणों में मोदी के नेतृत्व में भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कही थी। राहुल गांधी के अमेरिका और यूरोप के दौरे के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस और पंजाब प्रदेश कांग्रेस के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को विपक्षी गठबंधन में शामिल किया। जिस तरह अमेरिका ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने पर सवाल खड़ा किया था, ठीक उसी तरह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़ा किया। संयुक्त राष्ट्र की टिप्पणी और भी ज्यादा आपत्तिजनक है, जिसमें कहा गया कि लोकसभा चुनावों से पहले उनकी गिरफ्तारी के बाद दुनिया को उम्मीद है कि भारत में संसदीय चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के प्रवक्ता स्टीफन से एक प्रायोजित सवाल पूछा गया था। सवाल पूछने वाला बांग्लादेशी पत्रकार मुश्फिकुल फजल अंसारी पहले भी भारत विरोधी सवाल पूछता रहा है। वह बांग्लादेश में कई मामलों में वांछित है। अंसारी ने कांग्रेस के बैंक खाते सील होने और केजरीवाल की गिरफ्तारी को भारत में राजनीतिक अशांति करार देते हुए सवाल किया था। क्या भारत के कानून के अंतर्गत हुई ये दोनों घटनाएं राजनीतिक अशांति है? कांग्रेस के बैक खातों को सील किए जाने पर अदालत ने कोई राहत नहीं दी, अलबत्ता आयकर विभाग की कार्रवाई को उचित ठहराया है। क्योंकि कांग्रेस ने आयकर से छूट हासिल करने के लिए समयसीमा में रिटर्न नहीं भरा और अपनी आय को छुपाया। उसी तरह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी कोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया, जबकि उनसे पूछताछ के लिए रिमांड दिया गया है। इसलिए पत्रकार का सवाल ही राजनीति से प्रेरित और प्रायोजित था, और जवाब उससे भी अधिक प्रायोजित और राजनीति से प्रेरित था। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन ने पहले से लिखा हुआ जवाब पढ़ते हुए कहा कि भारत या जहां कहीं भी चुनाव होते हैं, वहां सभी के नागरिक अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

● **कुमार विनोद**

दो साल पहले लिखी विरोध की पटकथा

चुनावों से ठीक पहले विदेशों से नरेंद्र मोदी सरकार पर अचानक हमले तेज नहीं हुए हैं। इसकी पटकथा पिछले दो साल से लिखी जा रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे ज्यादा फंडिंग करने वाले जार्ज सोरोस ने कुछ महीने पहले कहा था कि भारत में लोकतंत्र तब पुनर्जीवित होगा, जब नरेंद्र मोदी चुनाव हारेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समय जार्ज सोरोस का एक प्रतिनिधि उनसे मिलने भी पहुंचा था, जिसकी राहुल गांधी के साथ चलते हुए तस्वीर वायरल हुई थी। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्राओं के दौरान अमेरिका और ब्रिटेन गए थे, तो उनके सारे कार्यक्रमों का आयोजन जिन एनजीओ ने किया था, उनको जार्ज सोरोस फंडिंग करते हैं। जार्ज सोरोस ने मोदी को चुनावों में हराने के लिए असीमित पैसा खर्च करने का ऐलान किया हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टी को सबसे ज्यादा फंडिंग जार्ज सोरोस ही करते हैं, और वह अमेरिका की नीतियों को भी प्रभावित करते हैं। सवाल यह है कि क्या अमेरिका का बाइडेन प्रशासन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहता। खबर यह है कि अमेरिका मोदी के मुकाबले लचीले रूख वाला प्रधानमंत्री देखना चाहता है, ताकि वह आसानी से भारत की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को प्रभावित कर सके। अमेरिका को यह कतई पसंद नहीं आया कि उसके विरोध के बावजूद भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल खरीदा। मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव के आगे झुकने से इंकार कर दिया था।

mycem cement

HEIDELBERGCEMENT

mycem power

Trusted German Quality

Over 150 Years

Send 'Hi' 7236955555

पार लेंगे हम...

पोथी खोलने के बाद पुरोहित हिचकिचाने लगे। यह तय शादी बेमेल होने जा रही है। कैसे और किसे हम बताएं कि कभी भी अनिष्ट हो सकता है।

क्या हुआ पुरोहित जी, जो सोचे जा रहे हैं आप? जाह्नवी के पिता रामेश्वर ने कहा।

अनिष्ट लिखा है यजमान बहुत भारी अनिष्ट। पुरोहित ने सकुचाते हुए कहा।

बहुत सारे ग्रह विधि-विधान से टल भी तो जाते हैं। रामेश्वर ने उत्सुकता से कहा। क्योंकि वे अपनी बेटी की शादी के लिए सुयोग्य लड़का ढूंढ़ते-ढूंढ़ते काफी परेशान हो चुके थे।

आगे कुआं पीछे खाई... किसे टालेंगे आप? पुरोहित ने ऐसा कहा कि लोग और असमंजस में पड़ गए। एक तो कहीं शादी जल्दी लगती नहीं थी और लगी तो अनिष्ट लिखा है। क्या करें हम। पिता के लिए गंभीर समस्या थी, यह।

आखिर लिखा क्या है? जो खुलते नहीं हैं आप और हम सभी को चिंता में डाले हुए हैं। जाह्नवी ने सभी के सामने आते के साथ कहा।

तुम विष-कन्या हो। पुरोहित ने एक बेटी को गंभीर चोट देते हुए कहा। जैसे जन्म लेना उसके अपने बस की बात हो। और वह भी विष-कन्या। यह कितनी भद्दी गालियां पड़ती है बेटी जाति पर किसी ने आज तक सोचा कभी।

यह एक अंधविश्वास है। मैं नहीं मानती, इसे। जाह्नवी ने अपने पिता की आंखों में छलछलाए आंसू को देखते हुए कहा।

बेटी मां की कोंख से सुकन्या जन्म लेती है, विष-कन्या नहीं। पुरोहित जी, हम आगे का कुआं पार लेंगे। समधी के रूप में आए हुए रूद्र नारायण ने डंके की चोट पर कहा।

और हम मुड़ेंगे न पीछे की खाई में गिरेंगे। एक बेटी के पिता ने खुलते हुए कहा।

अब कोई बेटी विष-कन्या नहीं होगी।

- विद्या शंकर विद्यार्थी

घर का सुख...

स्कूल के बगल में आर्मी का ट्रांजिट कैंप होने के कारण आते-जाते फौजी वहां रुकते। घर से आते फौजी ने स्कूल के बरामदे में अपना पिट्टू व राइफल एक तरफ टिकाते हुए चढ़ाई के कारण चेहरे पर आया पसीना पौंछा और फिर मास्टर रामदास की ओर मुखातिब होते हुए बोला- मास्टरजी तीन-तीन महीने पहले अर्जी लगाने के बाद जब छुट्टी मिलती है, तो बिना रिजर्वेशन के तीन-तीन दिन का सफर ट्रेन में खड़े खड़े कर देते हैं, फिर भी कोई थकान नहीं होती। परंतु वापसी में रिजर्वेशन के बावजूद स्टेशन पर पहुंचते-पहुंचते शरीर टूटने लगता है। उसके चेहरे पर फिर उभर आईं पसीने की बूंदें मानो उसकी अनुभूति की गवाही दे रही थीं।

- अशोक दर्द

जिव्हा रूपी शमशीर

सत्ता पाने का अहंकार,
सत्ता खोने की पीर बड़ी।
दोनों ने मिलकर खींची है,
रंजिश की एक लकीर बड़ी।।
है एक पक्ष जो भारत को
अपनी जागीर समझता है।
सत्ता को सोने की प्याली में
रक्खी खीर समझता है।
भ्रष्टाचारी गंगा जिसके शासन में
कल-कल बहती थी,
जो खुद को ही हर
भारतवासी की तकदीर समझता है।
जनता ने उसके पांवों में
पहना दी है जंजीर बड़ी।
दोनों ने मिलकर खींची है,
रंजिश की एक लकीर बड़ी।।
है एक दूसरा पक्ष,
जिसे जनता ने गले लगाया है।
दशकों के बाद किसी को
अपने सिर-माथे बिठलाया है।
पकड़ी है राह सही लेकिन,
भाषणबाजी कुछ ज्यादा है,
सच में उतना भी नहीं हुआ,
जितने का ख्वाब दिखाया है।
जितने भी काम किए अब तक,
उससे भी हैं तकरीर बड़ी।
दोनों ने मिलकर खींची है,
रंजिश की एक लकीर बड़ी।।
सत्ता हो चाहे हो विपक्ष,
दोनों ही कुंठित लगते हैं।
दोनों की वाणी से प्रकटे
उद्गार संकुचित लगते हैं।
आरोपों-प्रत्यारोपों से
गाली-गलौज तक जा पहुंचे,
भाषा की मर्यादाओं से
दोनों ही वंचित लगते हैं।
दोनों की है अपनी-अपनी
जिव्हा रूपी शमशीर बड़ी।
दोनों ने मिलकर खींची है,
रंजिश की एक लकीर बड़ी।।

- बृज राज किशोर 'राहगीर'

हैदराबाद ने गढ़ा नया कीर्तिमान

आईपीएल 2024 एक ओर जहां अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है, वहीं बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया आईपीएल के इस सीजन का तीसवां मुकाबला इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में कई कीर्तिमान स्थापित कर गया। इस मुकाबले में चौकों-छक्कों की ऐसी बारिश हुई कि इससे पहले कभी नहीं देखी गई। आईपीएल ही नहीं टी-20 क्रिकेट में भी इससे पहले एक मैच में इतने रन नहीं बने। रनों के इस तूफान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बेंगलुरु की टीम 262 रन बनाने के बावजूद 25 रनों से यह मुकाबला हार गई। असल में आईपीएल-17 के 30वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए एक बार फिर आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले हैदराबाद ने आईपीएल के मौजूदा सीजन में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 277 रन बनाए थे। तब उसने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 11 साल पुराने 263 रन के रिकॉर्ड को तोड़ा था। लेकिन अब बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सनराइजर्स ने एक बार फिर इतिहास रचते हुए तीन विकेट पर 287 रन बनाकर आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर बना डाला है। यही नहीं यह टी-20 क्रिकेट का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। टी-20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर तीन विकेट पर 314 रन है, जो नेपाल ने 2023 में मंगोलिया के खिलाफ बनाया था।

हैदराबाद के इस स्कोर के लिए ट्रेविस हेड के 41 गेंद में 9 चौकों और 8 छक्कों की मदद से बनाए गए 102 रन मददगार रहे। वहीं हेनरिक क्लासेन ने 31 गेंद में 67 रन बनाए। हेड ने अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 49 गेंद में 108, क्लासेन ने मार्करम के साथ तीसरे विकेट के लिए 27 गेंद में 66 और अंत में मार्करम और अब्दुल समद ने 19 गेंद में 56 रन की अटूट साझेदारी की। इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने जमकर रन लूटे। रॉयल बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने भी अच्छा जवाब दिया, हालांकि, वे अपनी टीम को जिता नहीं सके। मैच की दोनों पारियों में कुल 81 बाउंड्री लगीं जिसमें 43 चौके, 38 छक्के लगे जो आईपीएल और ही टी-20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक हैं।

सनराइजर्स हैदराबाद के ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड ने इस मैच में 41 गेंद पर 102 रन की पारी खेली। उन्होंने 39वीं गेंद पर शतक पूरा किया। यह सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू ने सनराइजर्स हैदराबाद के 287 रनों के जवाब में 7 विकेट पर 267 रन बनाए। इस तरह उसे 25 रन से हार का सामना करना पड़ा। हैदराबाद की इस जीत और बेंगलुरु की हार में टी-20 मैच के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड भी बन गया है। इस मुकाबले में कुल 549 रन बने जो आईपीएल समेत किसी भी टी-20 मैच की दोनों पारियों को मिलाकर सबसे ज्यादा रन हैं। एक पारी में सबसे **अधिक छक्के सनराइजर्स हैदराबाद** के बल्लेबाजों ने बेंगलुरु के खिलाफ 22 छक्के लगाए। यह आईपीएल में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड है। बेंगलुरु की टीम ने भी जवाब में 16 छक्के लगाए। इस तरह मैच में कुल 38 छक्के लगे। यह आईपीएल में एक मैच में सबसे अधिक छक्कों का रिकॉर्ड है। इससे पहले सिर्फ एक बार ही ऐसा हुआ है कि किसी एक मैच सनराइजर्स हैदराबाद बनाम मुंबई इंडियंस में 38 छक्के लगे हों। इससे पहले आईपीएल 2013 में आरसीबी ने 21 छक्को का रिकॉर्ड बनाया था। हैदराबाद के बल्लेबाजों के कहर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टी-20 क्रिकेट में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि किसी टीम के एक-दो नहीं, चार गेंदबाजों ने एक ही मैच में 50 रन से ज्यादा लुटा दिए। जिसमें सबसे ज्यादा रीस टॉप्ली ने 68 और विजय कुमार विशक ने 64 रन खर्च किए तो वहीं लाकी फर्ग्युसन के 4 ओवर में 52 और यश दयाल के 4 ओवर के स्पेल में 51 रन बने।

आईपीएल के इतिहास का अब तक का सबसे शानदार मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखने को मिला। इस मैच में एसआरएच ने 20 ओवरों में रिकॉर्ड तोड़ 287 रन बनाए। जवाब में लक्ष्य पीछा करने **उतरी बेंगलुरु** की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया और लोगों का दिल जीत लिया। हालांकि वह मैच जीत पाने में असफल रही। हैदराबाद ने मैच महज 25 रनों से जीता। बेंगलुरु ने 262 रन बनाए। इस दौरान मैदान पर जमकर रनों की बरसात हुई। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के इतिहास में अब तक किसी भी टीम के सबसे बड़े टोटल रनों का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। एसआरएच ने बेंगलुरु के खिलाफ 287 रनों का रिकॉर्ड स्कोर बनाया है। टीम ने इससे पहले 27 मार्च 2024 को मुंबई के खिलाफ बनाए 277 रनों के रिकॉर्ड को खुद ही तोड़ा है।

हैदराबाद द्वारा दिया गया 288 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेंगलुरु की शुरुआत भी धमाकेदार रही और विराट-डुप्लेसी ने 7वें ओवर में टीम को 80 तक पहुंचा दिया। हालांकि इसी ओवर में विराट 42 रन बनाकर आउट हो गए। डुप्लेसी ने भी 62 रन की पारी खेली। विल जैक्स, रजत पाटीदार और सौरव चौहान सस्ते में पवेलियन लौटे तो दिनेश कार्तिक ने कोहराम मचाया और 35 गेंदों में 83 रन की पारी खेल डाली। इस दौरान दिनेश ने 7 छक्के और 5 चौके लगाए। अनुज रावत ने भी 14 गेंदों में 25 रन की पारी खेली लेकिन टीम लक्ष्य से 25 रन दूर रह गई और बेंगलुरु लगातार 5वां मैच हार गई।

● **आशीष नेमा**

हेड ने तोड़ा 17 साल पुराना रिकॉर्ड

ट्रेविस हेड चिन्नास्वामी में गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ करते नजर आए। उन्होंने महज 41 गेंद में 102 रनों की शतकीय पारी खेली। इस तूफानी पारी में 9 चौके और 8 छक्के शामिल थे। 39 गेंद में शतक ठोकने के बाद हेड ने गिलक्रिस्ट का साल 2008 में मुंबई के खिलाफ महज 42 गेंद में सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने एबी डिविलियर्स और डेविड वॉर्नर के 43 गेंद में शतक का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। गौरतलब है कि इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का 30वां मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया, जहां कई इतिहास रचे गए। इस मुकाबले में 38 छक्के और 43 चौके लगे। दोनों टीमों ने मिलकर 40 ओवर में 549 रन बना डाले, जो आज तक किसी टी-20 मैच में नहीं बने। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 287 रन बनाए। 288 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु की टीम ने भी 262 रन बनाए।

देवदास का चुन्नी बाबू होता ये एक्टर

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी देवदास बांग्ला के उपन्यासकार शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है, जिसमें संजय लीला भंसाली ने अपने अनुभव को जोड़ते हुए पानी की तरह पैसा बहाया था। इस फिल्म में चुन्नी बाबू का किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया था, जो मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे। फिल्म के लिए उस एक्टर को अप्रोच किया था, जो आज ओटीटी पर लोगों को लुभा रहा है।

डायरेक्टर को कर बैठा ना, फिल्म ने मचाया धमाल तो मले सिर्फ हाथ!

संजय लीला भंसाली बॉलीवुड के वो फिल्ममेकर हैं, जिनके साथ काम करना हर स्टार का सपना होता है। फिल्म देवदास के एक किरदार चुन्नी बाबू के रोल के लिए मनोज बाजपेयी के पास मेकर्स पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने उस रोल को करने से इंकार कर दिया। देवदास मूवी के इस कैरेक्टर रोल में बाद में जैकी श्रॉफ नजर आए थे। और, इसे यादगार बनाने में भी कामयाब रहे थे। मनोज बाजपेयी ने खुद एक इंटरव्यू में इस रोल को ठुकराने की वजह बताई थी। ऐसा उन्होंने क्यों किया? इसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। मनोज बाजपेयी ने बताया था कि दरअसल, उस दौर में मनोज बाजपेयी कुछ लीड रोल कर रहे थे। उनका मानना था कि वो साइड या सपोर्टिंग रोल करेंगे तो उनकी इमेज पर फर्क पड़ेगा। मनोज बाजपेयी अपने करियर में देवदास जैसा एक रोल करना चाहते थे।

छह अलग-अलग सेट तैयार किए गए थे...

भंसाली की इस फिल्म की शूटिंग के लिए छह अलग-अलग सेट तैयार किए गए थे, जिस पर 2500 लाइट्स, 700 लाइट मैन, 42 जेनरेटर और 30 लाख वॉट की पावर सप्लाई लगती थी। आम तौर एक फिल्म की शूटिंग के लिए 2 से 3 जेनरेटर लगते थे। इस फिल्म का हर एक सेट इतना आलीशान था कि देखने वाले की आंखें तक रोशन हो जाती थीं। हैरानी की बात ये है कि फिल्म में चंद्रमुखी का कोठा 12 करोड़ में तैयार हुआ था। वहीं पारो का महल 3 करोड़ में बनकर तैयार हुआ था।

रणबीर कपूर को टक्कर देकर सुपरस्टार बन सकता था ये एक्टर, एकसाथ साइन की थीं 12 फिल्में, फिर हुआ ऐसा...

बॉलीवुड एक्टर अध्ययन सुमन इन दिनों वेब सीरीज हीरामंडी-द डायमंड बाजार को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं। कमाल की बात है कि उनके पिता शेखर सुमन भी इस सीरीज का हिस्सा हैं। अध्ययन सुमन ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्होंने अपनी दूसरी मूवी की रिलीज के बाद एकसाथ 12 फिल्में साइन की थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका फिल्मी करियर एक झटके में अर्श से फर्श पर आ गया था।

द बॉम्बे जर्नी को दिए इंटरव्यू में अध्ययन सुमन ने बताया कि उनकी दूसरी फिल्म राज 2 बड़ी हिट साबित हुई थी, जिसके बाद उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई थी। उन्होंने कहा, मैंने 12 फिल्में साइन की थीं। मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। एक न्यूजपेपर में टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट को लेकर खबर छपी थी, उसमें रणबीर कपूर और इमरान खान ने बाद मेरा नाम था। तो मुझे लगा कि लाइफ में मजा आ रहा है। लेकिन जिस तरह से जिंदगी ने फिर यू-टर्न लिया और चीजें बदलीं कि सारी मूवीज एक झटके में बंद हो गई थी।

जश्न की वजह से बंद हो गई थीं सारी फिल्में... अध्ययन सुमन ने इसके पीछे की वजह का खुलासा करते हुए बताया कि उनकी तीसरी मूवी जश्न बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली थी। उसके बाद उनकी सारी फिल्में बंद हो गईं। उनका कहना है कि जश्न एक खूबसूरत फिल्म थी, लेकिन उसे सही तरीके से शोज नहीं मिले थे, उसे सही रिलीज नहीं मिली थी। इस वजह से फिल्म फ्लॉप हो गई थी लेकिन उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी।

शाहरुख-सुष्मिता की वो फिल्म, जिसने बर्बाद किया था 1 एक्टर का करियर, 14 सालों तक बॉलीवुड से रहना पड़ा दूर

बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार्स हैं, जो लंबे गैप के बाद दमदार वापसी कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पर शाहरुख खान को ही ले लीजिए। बॉक्स ऑफिस पर जीरो के पिटने के बाद उन्होंने 4 साल तक फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली थी, लेकिन फिर साल 2023 में उन्होंने पठान से दमदार वापसी कर फैंस को हैरान कर दिया था। आज हम आपको एक स्टार के बारे में बताते हैं, जिनका करियर शाहरुख खान की मूवी ने ही तबाह कर दिया था।

हम जिस स्टार की बात कर रहे हैं उनका नाम है फरदीन खान। फरदीन खान की आखिरी फिल्म साल 2010 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से पूरी तरह किनारा कर लिया था। उस मूवी का नाम है दूल्हा मिल गया। इसमें शाहरुख खान और सुष्मिता सेन अहम किरदारों में नजर आए थे। यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी, जिसमें किंग खान का स्पेशल अपीयरेंस था। उन्होंने मूवी में सुष्मिता सेन के बॉयफ्रेंड का किरदार निभाया था, जिसकी एंट्री फिल्म में इंटरवल के बाद होती है। लेकिन अफसोस कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी।

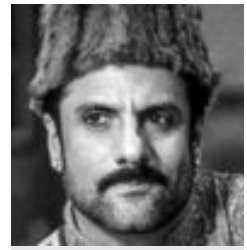

हीरामंडी से कमबैक... अब फरदीन खान वेब सीरीज हीरामंडी-द डायमंड बाजार से 14 साल बाद कमबैक करने जा रहे हैं। इसमें वह वाली मोहम्मद के रोल में नजर आएंगे। वेब सीरीज से उनका लुक भी सामने आ चुका है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी ये सीरीज 1 मई, 2024 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। इसके अलावा फरदीन के पास एक्शन थ्रिलर मूवी विस्फोट भी है।

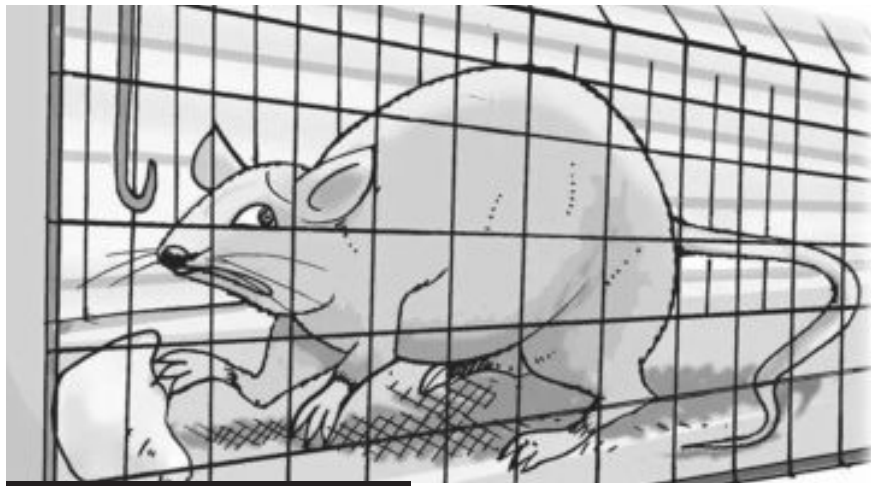

अचार में चूहा

लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। बिल्ली बंदर का किस्सा हो या बिल्ली भेड़िये का। अंगूर सदा खट्टे ही रहते हैं और रोटी कभी बिल्ली नहीं खा पाती है। किसी को भी लालच से लाभ हुआ हो, ऐसी मिसाल नहीं मिलती हैं। फिर भी लालच वो बला है जिससे गले मिलने के लिए सभी आतुर रहते हैं। लालच सदा ही ले डूबता है, कभी लालच में घिरकर कोई डूबने से बच नहीं पाया है। चाहे वो इंसान हो या कोई जीव जंतु। आज आपको चूहे की ऐसी कथाएं बतला रहा हूं जो लालच से घिरने पर अपने प्राण दे बैठे, वो सौ ग्राम का जीव लालच के कारण ही निर्जीवता को प्राप्त हुआ।

एक शब्द ज्ञानधारी चूहे ने अपने पैने दांतों से कागज को कुतरने से पहले अपनी निगाहों और पढ़ने के कौशल के जरिए उस लेख को पढ़ लिया जो कि फल-सब्जी के खाने से मिलने वाले फायदों को बतला रहा था। उस लेख को पढ़ने पर चूहे का अपने चूहेधर्म यानी कागज कुतरने से मोहभंग हो गया और वह तुरंत ही फल-सब्जियों की तलाश में दौड़ता कि तभी वो कागज चूहे की कूद फांद के कारण उलट गया और उसके दूसरी ओर प्रकाशित विज्ञापन पढ़ने पर उसे ज्ञान हुआ कि मध्यम प्रदेश (एमपी) में अचार बनाने की एक मल्टीनेशनल फैक्टरी लगी हुई है जहां पर रोजाना हजारों बोतलें अचार बनाया जाता है। विज्ञापन में दरअसल श्रमिकों की मांग की गई थी परंतु अपना चूहा क्योंकि आधुनिक युग का ज्ञानवान चूहा था और पढ़ना जानता था इसलिए वो यह समझ गया कि अचार बनाने में फल-सब्जियों का ही इस्तेमाल किया जाता है।

विज्ञापन पढ़ते ही वो मध्यम प्रदेश की ओर जाने वाली एक फ्लाईट में चढ़ गया जबकि उससे जानकारी पाकर बाद में फ्लाईट में सवार हुआ चूहा पकड़ा गया। बाद वाली फ्लाईट चाहे देरी से गई परंतु विमान के सुरक्षाकर्मियों ने तलाश करके उसकी बलि चढ़ा दी। चूहे की बलि का किस्सा आप अखबारों में पिछले दिनों पढ़ ही चुके हैं, वो चूहा विदेश से भारत में फल-सब्जियों की तलाश में ही पहुंचा था परंतु वो फ्लाईट से बाहर निकल नहीं पाया और जब जहाज का दोबारा उड़ने का समय हुआ तो वो उतरता कि इससे पहले दिखलाई दे गया और जब दिखलाई दे ही गया तो उसे तलाश करके मार डाला गया। इस चूहामार युद्ध में चूहे ने विमान में भरपूर आतंक भी फैलाया।

तो अपना यह पहले वाला सौ ग्राम का चूहा, जिसे विज्ञापन पढ़ने पर आइडिया आया था, वो सकुशल उस अचार फैक्टरी में प्रवेश पा गया। उस फैक्टरी में घुसने में उसे खूब मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि रात्रि में दरवाजे के नीचे जाने पर उसके जाति वालों ने उसे खदेड़ दिया पर वो वहां से खदेड़े जाने पर भी नहीं रुका और सीवर की नालियों के जरिए फल-सब्जियों के उस भंडार में जा पहुंचा जहां पर पहुंचने की उसकी दिली तमन्ना थी। चूहे के दिल रहा होगा और वो चूहा दिलदार भी था क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उसने हौंसला नहीं खोया था।

भंडार में पहुंचकर उसने खूब फल-सब्जियों को खाने का कम और कुतर डालने का खूब आनंद उठाया और विटामिन हासिल किए और कैलोरी का खर्चा किया। वो महंगी गोभी, शकरकंदी, शलजम, घिया, आम, कमल ककड़ी, सीताफल, आलू इत्यादि सभी पर अपने पैने दांत आजमा रहा था। कुछ सब्जियां तो अचार के लिए जरूरी होती हैं परंतु कुछ सब्जियां अचार का वजन बढ़ाने और कम कीमतें होने के कारण प्रयोग में लाई जाती हैं। जिससे अचार व्यवसाय में खूब मुनाफा मिलता है। चूहा चाहे पढ़ा हुआ था परंतु उसे अचार बनाने की विधि के बारे में जानकारी नहीं थी। उसे नहीं मालूम था कि फल-सब्जियों का अचार बनाने से पहले खूब उबालकर फिर मशीनों में सुखाया भी जाता है। उसके बाद ही अचार बनता है। फैक्टरियों में धूप इत्यादि दिखलाने की रस्म-अदायगी नहीं की जाती और न इतना समय ही होता है। यह कार्य मशीनों के द्वारा ही निपटाए जाने का युग है।

जिस भंडार में चूहे ने दावत उड़ाई थी, वो उसी में खर्राटे भर रहा था। उसे नहीं मालूम था कि उसके खर्राटों की आवाज किसी के कानों तक नहीं जाएगी क्योंकि चूहे के खर्राटे कोई आसमान नहीं हिला सकते जबकि इस चूहे की मौत से भी पृथ्वी पर कोई भूकम्प नहीं आया। शाम होते न होते फल-सब्जियों के उस ढेर में एकाएक उबला पानी छोड़ दिया गया, उस पानी के निकलने के सभी रास्ते पहले से ही बंद कर दिए गए थे। गर्मागर्म खौलते पानी और फल-सब्जियों के बीच में छिपे रहने के कारण वो जब तक उछलकर बाहर अपना मुंह निकालता, तब तक तो वो पूरी तरह उबल चुका था। उसकी चूहालीला समाप्त हो चुकी थी। यही चूहालीला बाद में अचारलीला बनी। जिसकी खबर अखबार में पिछले दिनों आप सभी पढ़ ही चुके हैं कि पांच किलो के एक अचार के डिब्बे में ढाई सौ ग्राम का चूहा निकला। सौ ग्राम का चूहा ढाई सौ ग्राम का कैसे बना, कुछ तकनीकी पहलुओं के चलते इस रहस्य से पर्दा नहीं हटाया जा रहा है।

इस संदर्भ में कई ज्वलंत प्रश्नों पर प्रबुद्ध और अचार प्रेमी संगत की प्रतिक्रिया की जरूरत है। वैसे इस प्रकरण से इंसान के अतिरिक्त अन्य जीव जंतु भी सबक ले सकते हैं। इंसान को इस रिपोर्ट को अपने घर में जगह-जगह पर चस्पा कर देना चाहिए और इसकी ऑडियो कैसेट बनाकर घर में बजानी चाहिए, जिससे वे सभी सावधान हो सकें और इनकी हत्या का सबब इंसान की लापरवाही न बने। अचार खाने से बचना भी इसका एक निदान है परंतु ऐसे इंसान ने अचार खाना छोड़ दिया फिर तो वो जीभ के चटकारे कैसे ले पाएगा, रसना का बेरस होना एक भला इंसान सह नहीं सकता।

पहला प्रश्न, पांच किलो अचार के डिब्बे में चूहा ही निकल सकता है। उसमें से हाथी का निकलना क्यों संभव नहीं है?

दूसरा प्रश्न, इस डिब्बे में से छिपकली इत्यादि का मिलना तो संभव है और एकाध प्रकरणों में वे मिली भी हैं परंतु उनका इन अचारों में मिलना छिपकलियों के साक्षर होने का सबूत नहीं माना जा सकता है?

और अब तीसरा और अंतिम पर निहायत जरूरी प्रश्न-

चूहा, छिपकली इत्यादि तो इतने बड़े होते हैं कि बाद में अचार में आंखों से दिखलाई दे जाते हैं परंतु काक्रोच, गोभी के कीड़े, सुरियां इत्यादि जो अचार बनाते समय इसमें घुल जाते हैं, क्या वे कभी पकड़े जा सकते हैं और क्या इंसान इस डर से कभी अचार खाना छोड़ सकेगा?

● **अविनाश वाचस्पति**

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

पर्यावरण
की सुरक्षा का
संकल्प
इस संकल्प ने हमारे मन-मानस
में गहरी जड़ पकड़ ली है
कोल इण्डिया लिमिटेड
विश्व की वृहत्तम कोयला उत्पादक संस्था
A Maharatna Company
प्रकृति के अस्तित्व में ही हमारा अस्तित्व है